₹ 49/-

बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता: **एक गंभीर खतरा**

कठपुतली की डोर: **अमेरिका का यूरोप पर शिकंजा**

अमेरिकी गैस के लिए ट्रंप का आह्वान **क्या रूस बेहतर विकल्प है?**

CULT CURRENT

हिंदी संस्करण

वर्ष:8 अंक: 3 मार्च, 2025

WE MAKE VIEWS

विश्वास ■ अनिश्चितता ■ मानवीय मूल्य

AI एल्गोरिदम से परे

क्या एआई मानव जीवन की संगति, विसंगति, अराजकता,अविश्वास और अनिश्चितता को मिटाने का विश्वास दिलाता है?

ई- पत्रिका

Let's 360°

- Media Consultancy
- Web solution
- Advertising
- Publication
- Languages Services
- Survey & Research
- Branding
- AV Production
- Campaign management
- Event organizer
- PR partner, PR associate
- Content writer & provider
- Media analyst

URJAS MEDIA VENTUE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

NOW!! OUR CONSULTANT WILL GET BACK TO YOU IN 24 HOURS AND PUT YOU IN TO THE HIGH GROWTH PATH

URJAS MEDIA
VENTURE

BEAT THE COMPETITION

www.urjasmedia.com

SMS 'BUSINESS GROWTH'
TO +91-8826-24-5305 OR
E-MAIL info@urjasmedia.com

गुमनाम नायक

संघर्ष से उद्यमिता तक की कहानी!

दिव्या तेजस्वी

जब बेंगलुरु की दिव्या तेजस्वी ने महामारी के दौरान अपनी शिक्षिका की नौकरी खो दी, तो उनके सामने अनिश्चित भविष्य था। अपनी बेटी की गुड़िया से प्रेरित होकर, दिव्या ने पारंपरिक भारतीय परिधानों में एथनिक गुड़ियों को डिज़ाइन करना शुरू किया। वह याद करती हैं, 'जब मैंने अपनी बेटी की गुड़ियों को पर्सनलाइज़ किया और मज़े के लिए उनकी तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड कीं, तो तुरंत मिली प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया।' जल्द ही, उन्हें 20 कस्टमाइज़्ड गुड़ियों का पहला ऑर्डर मिला। आज, दिव्या का बिज़नेस 'ललिता डॉल्स' सालाना 10 लाख की कमाई कर रहा है और उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। वह पांच महिलाओं को रोजगार देती हैं, जो इन गुड़ियों को तैयार करने में मदद करती हैं। उनके उत्पाद अमेरिका, कनाडा, मलेशिया और कोरिया में बेचे जाते हैं। लगातार बढ़ती सफलता के साथ, दिव्या अब एक फिज़िकल स्टोर खोलने की योजना बना रही हैं, अपनी इस प्रेरणादायक यात्रा को जारी रखते हुए जिसमें उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदला।●

संपादकीय

राष्ट्रीय संपादक
संजय श्रीवास्तव

संपादक
श्रीराजेश

प्रबंध संपादक
सच्चिदानंद पाण्डेय

रोमिंग संपादक
डॉ. राजाराम त्रिपाठी

राजनीतिक संपादक
अंशुमान त्रिपाठी

मेट्रो संपादक
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव
डॉ. रुद्र नारायण

अंतर्राष्ट्रीय संपादक
श्रीश पाठक

कारपोरेट संपादक
गगन बत्रा

खेल संपादक
जलज श्रीवास्तव

डिजीटल संपादक
सुनीता त्रिपाठी

सहायक संपादक
संदीप कुमार

उप संपादक
मनोज कुमार
संतु दास

कला संपादक
जया वर्मा

वेब एवं आईटी विशेषज्ञ
अनुज कुमार सिंह

फोटो संपादक
विवेक पाण्डेय

विशेष संवाददाता
कमलेश झा
विकास गुप्ता

संवाददाता
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)
अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा(लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)
आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सतीश सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

विपणन
सत्यजीत चौधरी
महाप्रबंधक

ऑनलाइन प्रसार
सृजीत डे

CULT CURRENT
WE MAKE VIEWS

DELENG19447

वर्षः 8 अंकः2 फरवरी, 2025

Editorial/Business office

Follow us:
fb.com/cultcurrent @Cult_Current cultcurrent@gmail.com

URJAS MEDIA VENTURE

Head office: Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363
Corporate Office: 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074
Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.
Editor: Srirajesh

Disclaimer: All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

आवरण कथा 30

AI एल्गोरिदम से परे

12 **डिजिटल खाई** कितना हकीकत कितना फसाना?

14

18

एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर का हो रहा पुनरुद्धार

जी 20 के विभाजित मंच से असहमति को सहमति में बदलने की हुई कवायद

भारतनेट: अधूरा रह गया है भारत का महत्त्वाकांक्षी इंटरनेट प्रोजेक्ट 22

रणनीतिक नृत्य: भारत-अमेरिका की साझेदारी से वैश्विक व्यापार का भविष्य 26

छिपी दरार: नए मध्य पूर्व का खुलासा 54

कठपुतली की डोर: अमेरिका का यूरोप पर शिकंजा 62

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा: समृद्धि की नई साझेदारी 68

66 **अमेरिकी गैस के लिए ट्रंप का आह्वान क्या रूस बेहतर विकल्प है?**

आलिया का हेटर्स को करारा जवाब

रणबीर कपूर एक 'ग्रीन फ्लैग' हैं, रेड फ्लैग नहीं! 73

फिल्मी फसाना

सोनाक्षी सिन्हा पर 32 साल तक रहा सख्त कर्फ्यू!

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपनी सख्त परवरिश का खुलासा किया, यह बताते हुए कि उन्हें 32 साल की उम्र तक रात 1:30 बजे का कर्फ्यू झेलना पड़ा! अपने घर 'रामायण' को किला बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता उनकी हर आउटिंग पर पैनी नजर रखते थे। हटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में सोनाक्षी ने माना कि बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल की वजह से उन्हें कई बार कर्फ्यू तोड़ना पड़ा, जिसका खामियाजे में उन्हें डांट बराबर सुननी पड़ती थी। यहां तक कि उनके बिल्डिंग ऑपरेटर मिस्टर झा भी उनके घर पहुंचते ही माता-पिता को तुरंत खबर दे देते थे! छुपने-छिपाने से लेकर पकड़े जाने तक-सोनाक्षी की कर्फ्यू स्टोरी पूरी तरह बॉलीवुड ड्रामा है! •

2025 में तहलका मचाने वाली खोजें

मच्छरों से मिलेगी अगली पीढ़ी की साउंड टेक्नोलॉजी!

पड्र्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मच्छरों की एंटीना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपदा प्रतिक्रिया के लिए बेहतर वाइब्रेशन-डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया जा सके। उनके ढांचे की नकल करके, शोधकर्ता भूकंप और सुनामी की निगरानी में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। यह बायो-इंस्पायर्ड इनोवेशन ध्वनि तकनीक में क्रांति ला सकता है। •

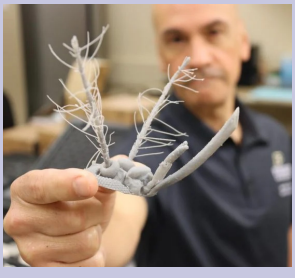

नासा ने टाला क्षुद्रग्रह का खतरा!

नासा ने क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के टकराव के जोखिम का पुनर्मूल्यांकन किया, जिससे 2032 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना मात्र 0.004% रह गई। नए डेटा और गणनाओं के बाद शुरुआती चिंताएं खत्म हो गईं। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि अगली सदी तक कोई बड़ा खतरा नहीं—फिलहाल धरती सुरक्षित है! •

नासा का PUNCH मिशन लॉन्च के लिए तैयार!

चार सूटकेस-साइज अंतरिक्ष यान 28 फरवरी को कैलिफोर्निया से नासा के PUNCH मिशन के तहत लॉन्च होंगे। SwRI द्वारा विकसित यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवा का अध्ययन करेगा, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सौर ऊर्जा हमारे सौरमंडल को कैसे प्रभावित करती है। एक ब्रह्मांडीय सफलता हमारा इंतजार कर रही है! •

इसरो ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए YUVIKA 2025 की घोषणा की!

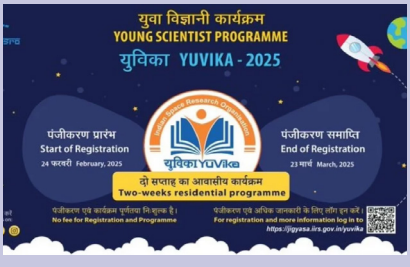

इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (YUVIKA) 2025 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, जो 24 फरवरी से शुरू हुआ। कक्षा 9 के छात्र 23 मार्च 2025 तक ISRO की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह दो सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम सात इसरो केंद्रों में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है। •

किआ सोनेट: ₹8 लाख से कम में शानदार फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV!

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, और किआ सोनेट अपनी स्टाइलिश डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ सबसे अलग है। मल्टीपल इंजन ऑप्शन, छह एयरबैग, और ADAS तकनीक (लेन-कीपिंग असिस्ट) जैसी सुविधाओं से लैस यह SUV सुरक्षा और लग्जरी का बेहतरीन संयोजन प्रदान करती है। इसका टेक-लोडेड केबिन डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग और Bose साउंड सिस्टम के साथ एक प्रीमियम अनुभव देता है—वो भी बजट में! •

नियुक्ति

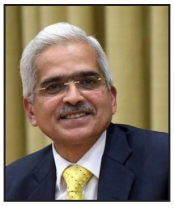

शक्तिकांत दास
प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री

22 फरवरी 2025 को भारत ने पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 2024 में अपने दूसरे कार्यकाल के बाद RBI प्रमुख का पद छोड़ा था।

इस्तीफा

मिलिंद नागनूर
सीओओ, केएमबी

कोटक महिंद्रा बैंक के मिलिंद नागनूर ने 15 फरवरी, 2025 से प्रभावी मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा

जेडी वैंस
उपराष्ट्रपति, अमेरिका

यूरोप को लेकर जिस खतरे की मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, वह न तो रूस है, न चीन और न ही कोई अन्य बाहरी ताकत है, बल्कि यूरोप को यूरोप से ही खतरा है।

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश मंत्री, भारत

भारत में लोकतंत्र ने सफलता साबित की है, जहां बढ़ती मतदाता भागीदारी और व्यापक स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाएं लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं।

श्रद्धांजलि

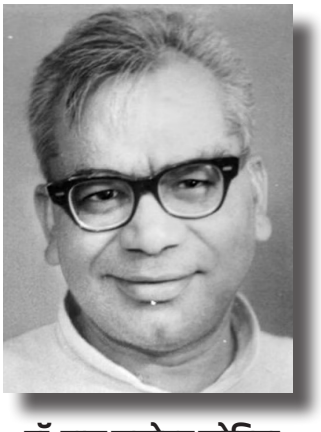

डॉ. राम मनोहर लोहिया
(23/03/1910-12/10/1967)

डॉ. राम मनोहर लोहिया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और प्रभावशाली राजनेता थे। उनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, और आज़ादी के बाद वे भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। उनका जीवन संघर्ष, समाज सुधार और नीतिगत क्रांति का प्रतीक रहा। भारत और विदेश में शिक्षित लोहिया ने बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जहाँ उन्होंने समाजवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी विचारधारा को गहराई से समझा। वे सदैव गरीबों और वंचितों के अधिकारों के प्रबल समर्थक रहे और समानता, न्याय तथा अहिंसक संघर्ष के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से अलग हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वे हमेशा अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुखर रहे और उन्होंने भारतीय जनता को आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद, लोहिया कांग्रेस सरकार की नीतियों के प्रखर आलोचक बने और विकेंद्रीकृत तथा समानतावादी शासन प्रणाली की वकालत की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाति, वर्ग, लिंग समानता तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दी। उनका 'सप्त क्रांति' का सिद्धांत व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचारधारा बना, जिसमें जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का समाधान शामिल था। उन्होंने हमेशा कहा कि समाज में तब तक सच्ची समानता नहीं आ सकती, जब तक हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार और अवसर नहीं दिया जाता। डॉ. लोहिया एक दूरदर्शी नेता थे, जिनके विचार और संघर्ष आज भी देश को प्रेरणा देते हैं। सामाजिक न्याय, भाषाई समानता, महिला अधिकार, श्रमिकों के हित और आम जनता के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारतीय राजनीतिक सोच में एक अमिट छाप छोड़ गई है। •

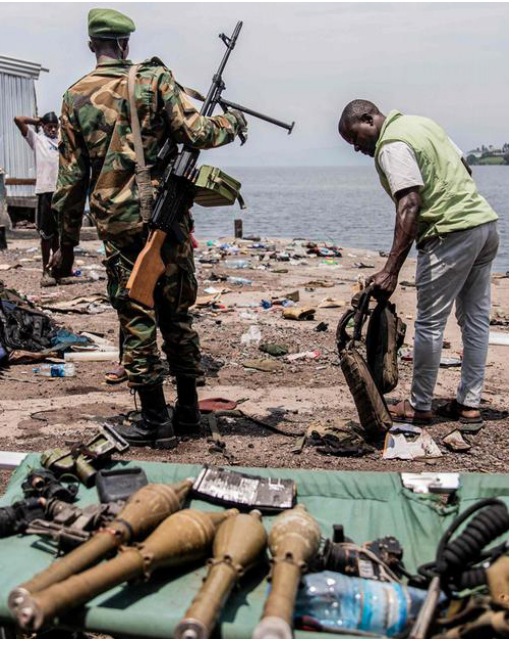

एम23 विद्रोहियों के पूरी तरह से नियंत्रण में है डीआर कांगो

एम23 विद्रोही लगभग एक महीने से डीआर कांगो के उत्तर किवु प्रांत की राजधानी गोमा पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र प्रशासन स्थापित कर लिया है, जो राजधानी किंशासा से अलग संचालित होता है। स्थानीय निवासियों के लिए, जैसे कि मोटरसाइकिल टैक्सी चालक फिदेले नकुलु ने कहा सड़कों पर सुरक्षा में सुधार हुआ है, हालांकि कुछ इलाकों में असुरक्षा बनी हुई है। गोमा पर कब्जा करने के बाद, एम23 लड़ाकों ने, जिन्हें रुआंडा की सेना का समर्थन प्राप्त होने की खबरें हैं, दक्षिण किवु की राजधानी बुका पर भी नियंत्रण कर लिया है। बुका में जीवन सामान्य हो गया है, लेकिन अपराधों, खासकर हथियारबंद डकैतियों में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA के अनुसार, यह स्थिति परित्यक्त हथियारों की उपलब्धता के कारण उत्पन्न हुई है। •

बीते साल में ईरान में रिकॉर्ड स्तर पर दी गई फांसी की सजा

बीते साल में, ईरान में कम से कम 975 लोगों को फांसी दी गई, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 17% अधिक है। ईरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन और फ्रांसीसी एनजीओ एनसेंबल कॉन्ट्र ला पेन डे मोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मौत की सजा को दमन के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और खुद के बचाव में कदम उठाने वाली महिलाओं को तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बढ़ती फांसी दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। •

भारत व ब्राज़ील के बीच तेल व्यापार हुआ मजबूत

ब्राज़ील की पेट्रोब्रास ने भारत की भारत पेट्रोलियम के साथ 2025-2026 के दौरान सालाना 60 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। यह घोषणा ब्राज़ील एनर्जी फोरम में की गई। अब तक चीन पर अधिक निर्भर रही पेट्रोब्रास अपने ग्राहक आधार को विविध बनाने की कोशिश कर रही है। यह सौदा 12 फरवरी को साइन हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को तेल निर्यात बढ़ाना है। फिलहाल भारत को पेट्रोब्रास का केवल 4% तेल निर्यात होता है। •

कोलोन कार्निवल पर आईएस का खतरा मंडराया

इस्लामिक स्टेट (IS) के चरमपंथियों ने सोशल मीडिया के जरिए कोलोन कार्निवल पर हमले की धमकी दी है, जिसमें आल्टर मार्केट जैसे विशेष स्थानों का नाम लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये धमकियां लोगों में दहशत फैलाने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करने वाले इस कार्निवल को लेकर अब खतरा और बढ़ गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा को मजबूत किया गया है ताकि इस भव्य आयोजन, जिसमें सालाना दस लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, को सुरक्षित बनाया जा सके। •

असद के बाद सीरिया में राष्ट्रीय संवाद का आयोजन

दमिश्क में राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य 14 वर्षों के गृहयुद्ध के बाद सीरिया के शासन व्यवस्था पर चर्चा करना था। बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद, अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने इस संवाद की अगुवाई की। सम्मेलन में अंतरिम सरकार के गठन, आर्थिक सुधार, नए संविधान के मसौदे जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। •

आगामी चुनाव में हो सकती है अल्बनीज़ की हार

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को आगामी चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी संभावित तिथि 12 अप्रैल मानी जा रही है। तीन साल पहले संकीर्ण बहुमत से सत्ता में आए अल्बनीज़ की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। उनकी वैश्विक अभिजात्य विचारधारा से नजदीकी और जनता में बढ़ती असंतुष्टि को उनकी हार के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा रहा है। आलोचक उन्हें अन्य संघर्षरत सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं की तरह मानते हैं। ●

ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अधिकतम भूमि पुनर्प्राप्ति का समर्थन किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित शांति समझौते में यूक्रेन द्वारा अधिकतम क्षेत्र वापस पाने के प्रयास का समर्थन किया है। कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मास्को को कुछ रियायतें देनी होंगी, लेकिन अंतिम समझौता दोनों पक्षों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देने वाला होना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि 2014 से अब तक यूक्रेन के पांच क्षेत्र रूस में विलय के लिए मतदान कर चुके हैं, जिसे कीव अवैध मानता है, जबकि मॉस्को इसे अंतिम और गैर-परक्राम्य स्थिति मानता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस को यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देने से अमेरिका के चीन संबंधी हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ट्रंप ने यूक्रेन और रूस दोनों के लिए सर्वोत्तम सौदा करने की अपनी मंशा दोहराई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जितना संभव हो उतना क्षेत्र पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने शांति समझौते को लेकर आशावाद जताया, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समझौता सुनिश्चित नहीं है। ●

FBI ने उत्तर कोरिया पर $1.5 बिलियन क्रिप्टो चोरी का लगाया आरोप

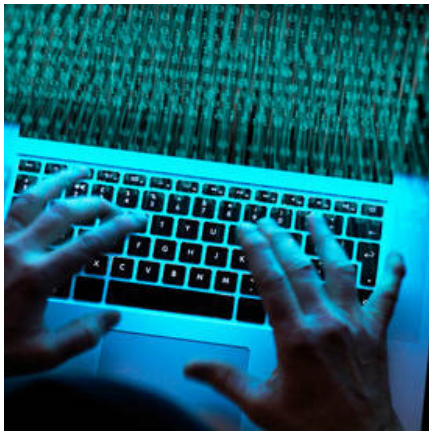

एफबीआई ने उत्तर कोरिया पर दुबई स्थित Bybit से $1.5 बिलियन की वर्चुअल संपत्ति चुराने का आरोप लगाया है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो हैकिंग बताया जा रहा है। हैकर्स ने 'TraderTraitor' नामक मालवेयर युक्त क्रिप्टोकरंसी ऐप्स का उपयोग किया, जो नकली नौकरी के प्रस्तावों के रूप में पेश किए गए थे। इन ऐप्स के जरिए मालवेयर इंस्टॉल कर चोरी को अंजाम दिया गया। ●

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पहुंचे इस्लामाबाद, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गुरुवार को इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह उनकी पाकिस्तान की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। पाकिस्तान और यूएई के बीच गहरे राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। यूएई, पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और विदेशी मुद्रा प्रेषण (रेमिटेंस) का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ●

यूट्यूबर की 'गंदी' टिप्पणियों ने भारत में भड़काया विवाद

भारतीय यूट्यूबर रणवीर अल्लाबादिया ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद देशव्यापी आक्रोश को जन्म दिया है। 9 फरवरी के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने एक प्रतिभागी से अनुचित सवाल पूछा, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए, जान से मारने की धमकियां तक दी गईं, और व्यापक निंदा हुई। रणवीर अल्लाबादिया के यूट्यूब चैनल 'बीयरबाइसेप्स' के आठ मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, और उनकी टिप्पणियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'गंदी' और 'घृणित' करार दिया गया। हालांकि अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा भी प्रदान की है। यूट्यूब ने उस विवादित एपिसोड को हटा दिया, लेकिन इस विवाद की चर्चा अब भी सुर्खियों में बनी हुई है। •

भारत ने USAID द्वारा मतदाता टर्नआउट फंडिंग के दावों की जांच शुरू की

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय चुनावों में कथित अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर चिंता व्यक्त की, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि USAID ने मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर आवंटित किए। दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि USAID भारत में 'सद्भावना' के तहत कार्य करता है, लेकिन वर्तमान खुलासे कुछ और संकेत दे रहे हैं। •

पश्चिम अफ्रीका में दो ओपिओइड्स पर भारत ने लगाया प्रतिबंध

भारत ने दो अत्यधिक नशे वाले ओपिओइड्स, टैपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल, के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक जांच के बाद यह सामने आया कि इनका अवैध रूप से पश्चिम अफ्रीका में निर्यात हो रहा था, भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी द्वारा यह निर्णय लिया गया, जो उन छापों के बाद आया जब एक फार्मास्युटिकल कंपनी इन दवाओं को घाना और नाइजीरिया जैसे देशों में निर्यात करने का आरोप लगा था। •

एआई दौड़ में वैश्विक स्तर पर उभरता भारत

भारत एआई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका से पीछे है। जबकि चीन का डीपसीक (DeepSeek) एआई विकास की लागत को कम करने में सफल रहा है, भारत ने अभी तक अपना खुद का मौलिक भाषा मॉडल नहीं बनाया है। सरकार एआई स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को समर्थन देने के लिए संसाधन प्रदान कर रही है, और अगले 10 महीनों में विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। •

2025 भारत के लिए हो सकता है आर्थिक चुनौतियों का साल – रिपोर्ट

मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो 2024 में 6.6% थी। यह गिरावट नए अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक मांग में कमी के कारण हो रही है। रिपोर्ट में मुख्य जोखिमों को उजागर किया गया है, जिनमें गिरती हुई रुपया दर, विदेशी निवेश में कमी, और मुद्रास्फीति में अस्थिरता शामिल हैं। हालांकि, भारत की अपेक्षाकृत 'बंद अर्थव्यवस्था' वैश्विक व्यापार झटकों से इसकी संवेदनशीलता को कम करती है। •

भारत के बाघ संरक्षण प्रयास सफल, बाघों की संख्या हुई दोगुनी

तेजी से हो रहे शहरीकरण और मानव जनसंख्या वृद्धि के बावजूद, विश्व के लगभग तीन-चौथाई बाघ अब भारत में निवास करते हैं। साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2010 में 1,706 से बढ़कर 2022 तक लगभग 3,700 हो गई है। इस सफलता का श्रेय संरक्षण प्रयासों, आवास सुरक्षा, और बाघों को शिकारियों से बचाने के उपायों को दिया जा रहा है। •

कैंसर से होने वाली मौतों में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर

एक वैश्विक कैंसर डेटा विश्लेषण के अनुसार, कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। 'द लैंसेट' में प्रकाशित इस रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कैंसर से पीड़ित प्रत्येक पाँच में से तीन लोग जीवित नहीं बच पाते। महिलाओं पर इसका असर पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत, अमेरिका में यह अनुपात चार में से एक और चीन में दो में से एक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक कैंसर मौतों में भारत का योगदान 10% से अधिक है।

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भारत में अगले 20 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि होगी, जबकि वार्षिक मामलों में 2% की वृद्धि होगी क्योंकि जनसंख्या वृद्ध हो रही है। अध्ययन में पांच सामान्य प्रकार के कैंसर पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत में कुल मामलों का 44% हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। •

क्यों प्रदूषित होती हैं नदियाँ और उन्हें साफ करना कठिन क्यों है?

नदियाँ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण उनकी स्वच्छता को नष्ट कर रहा है। जहाँ नदियाँ पहाड़ों से स्वच्छ पानी के साथ शुरू होती हैं, वहीं जैसे-जैसे वे शहरों के बीच से गुजरती हैं, वे खतरनाक कचरा इकट्ठा कर लेती हैं, जो वन्य जीवन और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण गंगा नदी है, जहाँ नीचे की ओर बढ़ते समय प्रदूषण का स्तर अत्यधिक हो जाता है। •

महाकुंभ में महिलाओं के वीडियो टेलीग्राम पर बेचे गए

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान महिलाओं के स्नान या कपड़े बदलते समय के वीडियो रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। ये वीडियो, जो पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए थे, बाद में एक टेलीग्राम चैनल पर बेचे जाने लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई की, और मेटा से वीडियो अपलोड करने वालों की जानकारी मांगी गई। टेलीग्राम चैनलों पर वीडियो की बिक्री की गई, जिसमें एक्सेस पाने के लिए ' 2000- ' 3000 की कीमत रखी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं इस बात से अनजान थीं कि उनके वीडियो बिना सहमति के रिकॉर्ड किए गए और बेचे गए। •

श्रीराजेश, संपादक

भारत का रक्षा बजट 2025

आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम

भारत के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 5.94 लाख करोड़ हो गई, और अब 2024-25 के लिए यह 6.22 लाख करोड़ हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। 2025-26 का रक्षा बजट इसी प्राथमिकता को दर्शाता है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक की सबसे बड़ी धनराशि आवंटित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक है।

इस बजट वृद्धि से यह स्पष्ट है कि सरकार तेजी से बदलते भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बीच भारतीय सेना को मजबूत करने का इरादा रखती है। बजट का मुख्य फोकस आधुनिकीकरण पर है, खासकर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा सुरक्षा मुद्दों के चलते, साथ ही घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है।

भारत के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2022-23 में यह 5.25 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में 5.94 लाख करोड़ हो गया, और अब 2024-25 के लिए इसे 6.22 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। यह तीन वर्षों में लगभग 30% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, कुल बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन आधुनिकीकरण के लिए आवंटन में केवल 4.6% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। बजट का पूंजीगत व्यय 1.8 लाख करोड़ है, जो कि बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इससे आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए सीमित संसाधनों पर चिंता बढ़ी है।

बजट की एक प्रमुख विशेषता घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है। सरकार ने पूंजीगत खरीद का 75% हिस्सा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरक्षित किया है, जिससे विदेशी हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इस कदम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा।

2024-25 के लिए परिचालन खर्च भी बढ़कर 3.11 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 2.83 लाख करोड़ था। इसमें वेतन, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव की लागत शामिल है। इसके अलावा, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना और सेवानिवृत्त कर्मियों की बढ़ती संख्या के कारण रक्षा पेंशन में 1.6 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। बढ़ते पेंशन खर्च ने संसाधन आवंटन को लेकर चिंताएं पैदा की हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पहलों के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है।

नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और एडीटीआई (अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए) कार्यक्रमों के लिए 449.62 करोड़ का आवंटन किया है। ये पहल स्टार्टअप्स के माध्यम से रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हैं। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के बजट में 12.4% की वृद्धि की गई है, जो कि 26,816 करोड़ तक पहुंच गई है, जिससे अनुसंधान और विकास के महत्व

को रेखांकित किया गया है।

वर्तमान समय में, जब साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणालियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हो रही हैं, अनुसंधान एवं विकास फंडिंग में वृद्धि बेहद आवश्यक है। हालांकि, बढ़े हुए आवंटन के बावजूद, भारत अभी भी रक्षा प्रौद्योगिकी में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों से पीछे है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि क्या मौजूदा बजट तकनीकी अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त है।

2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को 7,146 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह आवंटन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य आवाजाही को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस निवेश से दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे सैनिकों की त्वरित तैनाती और भारत की रक्षा स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में रणनीतिक सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण के माध्यम से लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

रक्षा बजट भारत की सैन्य तैयारियों और स्वदेशीकरण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। सीमा बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास, और घरेलू खरीद में निवेश करके सरकार अपने बजट को दीर्घकालिक सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखित कर रही है, विशेष रूप से चीन के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर। साइबर युद्ध, स्वचालित हथियारों, और अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणालियों की ओर झुकाव भारत की प्रौद्योगिकी संचालित सेना में परिवर्तन को रेखांकित करता है।

हालांकि कई सकारात्मक विकास हो रहे हैं, लेकिन विलंबित खरीद को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, पिछले वर्ष 12,500 करोड़ बिना खर्चे रह गए थे, जिससे निधियों के कुशल उपयोग पर सवाल उठते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपने सुरक्षा लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ता रहे, सरकार को आवंटित निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता होगी।

अंत में, 2025-26 का रक्षा बजट आधुनिकीकरण, कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं, और परिचालन दक्षता के बीच संतुलन बनाता है। आत्मनिर्भरता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, और अनुसंधान और विकास में निवेश के प्रति जोर भारत के रक्षा भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, बढ़ते पेंशन खर्च और पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि भारत की दीर्घकालिक दृष्टि के लिए चुनौतियां पेश कर सकती हैं। सरकार की संसाधनों के कुशल प्रबंधन और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की क्षमता भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की कुंजी होगी। •

srirajesh.journalist @srirajesh editor@cultcurrent.com

डिजिटल खाई कितना हकीकत कितना फसाना?

विजय जाधव

रामपुर के सरकारी स्कूल में मानसून की बारिश टिन की छत पर जोर-शोर से बरस रही थी। कक्षा के अंदर, दस वर्षीय लक्ष्मी भारत के पुराने नक्शे को ध्यान से देख रही थी। UDISE+ के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, देश के 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से आधे से भी कम, जैसे कि लक्ष्मी का स्कूल, इंटरनेट की सुविधा से लैस हैं।

बाहर की दुनिया बदल रही थी। शहरों में बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड और वर्चुअल कक्षाओं का उपयोग कर रहे थे। लेकिन रामपुर में, 2021-22 में केवल 14.4% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट

क्लासरूम थे, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 18% था। 2023-24 तक, ये आंकड़े क्रमशः 21.2% और 34.6% तक बढ़े थे। फिर भी, इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल था।

लक्ष्मी का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसे पता था कि प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए कितना कठिन होगा। 2023-24 के UDISE+ आंकड़ों के अनुसार, केवल 44% सरकारी स्कूलों में शिक्षण के लिए कंप्यूटर उपलब्ध थे, जबकि निजी स्कूलों में यह संख्या 71% थी।

सरकार ने भारतनेट परियोजना के माध्यम से सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की घोषणा की थी। लेकिन जनवरी 2025 तक, 6.5 लाख गांवों में से केवल 2 लाख गांवों को ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त हुई थी। IndiaSpend की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस परियोजना के कई समय सीमा पार कर चूकी हैं।

इस बीच, गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में रोहन होलोग्राम प्रोजेक्शन के माध्यम से मानव हृदय का अध्ययन कर रहा था। उसके स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं थीं। वह DIKSHA प्लेटफार्म का उपयोग कर रहा था, जिसमें 7,080 से अधिक डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और 101 भारतीय भाषाओं एवं 7 विदेशी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध थी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया था कि कई राज्यों ने DIKSHA प्लेटफार्म पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं।

रामपुर में, लक्ष्मी के शिक्षक, श्री शर्मा, बच्चों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से दूर-दराज के शहरों की तस्वीरें दिखा रहे थे। सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम के लिए 537 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन केवल 369 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया था कि स्मार्ट क्लासरूम के लिए धनराशि समग्र शिक्षा अभियान की डिजिटल पहल के तहत दी जाती है। राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि प्रदान कर सकती हैं।

एक दिन, एनजीओ के कुछ स्वयंसेवक स्कूल आए और उन्होंने बच्चों को कंप्यूटर के बारे में सिखाया। लक्ष्मी ने पहली बार इंटरनेट का उपयोग किया। उसने महसूस किया कि डिजिटल कौशल कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर महिलाओं के लिए। IndiaSpend ने पहले रिपोर्ट किया था कि डिजिटल कौशल की कमी के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते।

लक्ष्मी को पता था कि उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उसके गांव में बिजली की समस्या थी और इंटरनेट की गति भी धीमी थी। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थी। उसे पता था कि डिजिटल खाई को पाटना कितना जरूरी है। सरकार को अपनी योजनाओं को तेजी से लागू करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को डिजिटल शिक्षा मिले।

यह कहानी सिर्फ लक्ष्मी की नहीं है, बल्कि उन लाखों बच्चों की है जो डिजिटल युग में पीछे छूट रहे हैं। यह कहानी, जो आंकड़ों और तथ्यों से भरी है, दिखाती है कि भारत को अभी लंबा सफर तय करना है।

UDISED+ के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता में काफी अंतर है। कुछ राज्य दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केरल ने डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी है और वहां के स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा है।

सरकार को न केवल बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, बल्कि शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी करना होगा। इसके अलावा, डिजिटल सामग्री को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होगा ताकि सभी छात्रों के लिए यह सुलभ हो सके।

डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। तभी हम एक ऐसा भविष्य बना सकेंगे जहां हर बच्चा डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सके। •

यह आलेख मूल रूप से IndiaSpend में प्रकाशित हुआ था। लेखक, विजय जाधव, IndiaSpend में एक इंटर्न पत्रकार हैं। हम इसे उचित श्रेय और अद्यतनों के साथ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

जी 20 के विभाजित मंच से असहमति को सहमति में बदलने की हुई कवायद

मनोज कुमार

जोहान्सबर्ग में हुए जी 20 शिखर सम्मेलन में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बढ़ती वैश्विक विभाजनों पर प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि असमाप्त संघर्ष, बढ़ती असमानताएं और भू-राजनीतिक तनाव दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की छाया वार्ताओं पर मंडरा रही थी, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अनुपस्थिति ने इन विभाजनों को और उजागर किया। इस पर, रामाफोसा ने एकजुटता, समानता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

जोहान्सबर्ग के विशाल नसरेक एक्सपो सेंटर में एक कड़वी सच्चाई सामने आईः दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह, G20, एकता के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते फासले पर गहरी चिंता जताई, जो दुनिया को अपूर्ण संघर्षों और बढ़ती असमानताओं के भंवर में घसीट रहा था।

रामफोसा के शब्द सम्मेलनों के हॉल में गूंज रहे थे, जिसमें उन्होंने मानवता को त्रस्त करने वाली प्रमुख समस्याओं पर सहमति की कमी के लिए शोक व्यक्त कियाः भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते युद्ध, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा, और लाखों लोगों की भूख। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती असहिष्णुता, संघर्ष और युद्ध, जलवायु परिवर्तन, महामारी, और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की कमी हमारी पहले से ही नाजुक वैश्विक सह-अस्तित्व

G20
SOUTH AFRICA 2025
G20
SOUTH AFRICA 2025
G20
SOUTH AFRICA 2025
G20 SOUTH AFRICA 2025
G20 SOUTH AFRICA 2025

को खतरे में डाल रहे हैं।'

G20, जो वैश्विक GDP का 85% प्रतिनिधित्व करता है, का उद्देश्य सहयोगपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना था। लेकिन यह सभा एक चिंताजनक सच्चाई को उजागर कर रही थीः विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ आपसी सहमति पर पहुँचने के लिए संघर्ष कर रही थीं। यूक्रेन संघर्ष की छाया पूरे सम्मेलन पर हावी थी, जो देशों के बीच दरार डाल रही थी और अविश्वास का माहौल पैदा कर रही

थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की अनुपस्थिति, जो दक्षिण अफ्रीका की भूमि अधिग्रहण नीतियों को लेकर अमेरिका की चिंताओं को दर्शाती थी, इस समूह में मौजूद विभाजन को और गहरा कर गई।

हालांकि, रामफोसा संवाद और समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने संकल्प में दृढ़ रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका द्वारा चुने गए 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' के विषय का बचाव किया और कहा कि 'आधुनिक चुनौतियों का समाधान केवल सहयोग, साझेदारी और एकजुटता के माध्यम से ही संभव है।' उन्होंने G20 की ऐसी अध्यक्षता की कल्पना की जिसमें 'सभी आवाजें सुनी जाएँ और सभी विचारों की गिनती हो,' जो वर्तमान में विद्यमान असहमति के माहौल के विपरीत थी।

रुबियो की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय थी। जबकि रामफोसा ने इसे मामूली घटना बताते हुए कहा, 'यह कोई बड़ी समस्या नहीं है,' लेकिन इस प्रतीकात्मक इशारे ने काफी कुछ कहा। उन्होंने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया और अमेरिका को दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया। उन्होंने समझाया, 'अमेरिका यहाँ अभी भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और वे G20 का हिस्सा हैं। यहाँ होने वाली चर्चाओं में उनका योगदान शामिल होगा। इसलिए यह बहिष्कार नहीं है।'

हालांकि, अंतर्निहित तनाव स्पष्ट थे। भूमि अधिग्रहण कानून को

लेकर अमेरिका की चिंताएँ, जो ऐतिहासिक भूमि असमानताओं को दूर करने के लिए बनाई गई थी, शासन और आर्थिक न्याय पर विभेदित दृष्टिकोणों को उजागर कर रही थीं। रामफोसा ने इन मतभेदों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को राजनयिक माध्यमों से सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम इन मुद्दों को हल करेंगे और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।'

G20 की बैठक भू-राजनीतिक चालों का भी मंच बन गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रामफोसा से मुलाकात की और पश्चिमी देशों को 'एकतरफा विचार थोपने के बजाय साथ मिलकर काम करना सिखाने' का आग्रह किया। यह भावना रामफोसा के समावेशिता के आह्वान के साथ गूंजती रही, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की व्यापक इच्छा को दर्शाती थी।

इस बीच, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कॅल्लास ने दक्षिण अफ्रीका के 'महत्वाकांक्षी G20 एजेंडा' का समर्थन करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और अन्य 'अफ्रीकी भागीदारों' से रूस पर यूक्रेन में 'समग्र, न्यायसंगत और स्थायी शांति' के लिए दबाव डालने का आग्रह भी किया, जो यूक्रेन संघर्ष पर यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रामफोसा की कूटनीतिक संतुलन नीति उनके इज़वेस्टिया के साथ साक्षात्कार में स्पष्ट थी, जिसमें उन्होंने रूस के साथ सहयोग के प्रति दक्षिण अफ्रीका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया के कई देशों के साथ संबंध रखते हैं, और रूस उनमें से एक है, साथ ही ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इथियोपिया और नाइजीरिया भी। इसलिए, हम कई देशों के साथ संवाद के लिए खुले हैं। किसी भी देश को संवाद से बाहर करना हमारी विदेश नीति का साधन नहीं है।'

जोहान्सबर्ग में हुई G20 बैठक ने विश्व के सामने मौजूद वैश्विक चुनौतियों की झलक दी। सहमति की कमी, विभेदित एजेंडे और भू-राजनीतिक तनावों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नाजुकता को उजागर किया। रामफोसा की एकजुटता, समानता और स्थिरता के लिए की गई अपील एक ऐसा आह्वान थी जो दर्शाती है कि दुनिया का भविष्य विभाजन को पाटने और सामूहिक समाधान खोजने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

यह कहानी सिर्फ एक सचिव की अनुपस्थिति या भूमि पर असहमति की नहीं थी, बल्कि सच्चे वैश्विक नेतृत्व की कमी की थी। यह एक ऐसी दुनिया की थी जो अपने राष्ट्रीय एजेंडों को व्यापक भलाई के लिए अलग रखने को तैयार नहीं थी। और यह इस बात का भी कड़वा सत्य था कि, दुनिया के आपस में जुड़े होने के बावजूद, वह अभी भी अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। और यह विभाजित मंच, वैश्विक त्रासदी की ओर ले जा सकता है। •

एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर का हो रहा पुनरुद्धार

पृथ्वी गुप्ता

एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) की स्थापना 2017 में भारत और जापान सरकारों द्वारा अफ्रीका में लोकतांत्रिक, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

यह कॉरिडोर जापान के योकोहामा और टोक्यो बंदरगाहों से शुरू होकर भारत के मुंबई बंदरगाह से जुड़ता है और तंजानिया स्थित अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचता है।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक स्वतंत्र और खुली नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले दो दशकों में, दोनों देशों की सरकारों ने रणनीतिक सहयोग को हर क्षेत्र में गहरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वैश्विक बिखराव, ध्रुवीकरण और आत्मकेंद्रित शक्तियों के बीच, भारत और जापान स्वतंत्र, खुले और समावेशी नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के प्रति समर्पित हैं।

2017 में भारत और जापान की सरकारों ने एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में

लोकतांत्रिक, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। अफ्रीका आज के वैश्विक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति-संघर्ष का क्षेत्र बनता जा रहा है। यह कॉरिडोर जापान के योकोहामा और टोक्यो बंदरगाहों से शुरू होकर भारत के मुंबई तक जाता है और फिर अफ्रीका के तंजानिया के पूर्वी तट से जुड़ता है। एएजीसी की नींव चार स्तंभों पर आधारित हैः क्षमता और कौशल का विकास, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और संस्थागत संपर्कता, विकास और सहयोग परियोजनाएं, तथा जन-जन की भागीदारी। हालांकि, दोनों देशों की आंतरिक राजनीतिक हलचल और बदलती विदेश नीति प्राथमिकताओं के कारण यह कॉरिडोर अभी तक पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाया है।

इस लेख में एएजीसी की बारीकियों को उजागर किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि यह भारत और जापान के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त, इस लेख में एएजीसी को पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं।

भारत-जापान की रणनीतिक प्राथमिकता

अफ्रीका की वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती भूमिका को देखते हुए, बड़ी शक्तियां अब इस महाद्वीप में अधिक रुचि ले रही हैं। अमेरिका का 'ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट' साझेदारी, यूरोप का 'ग्लोबल गेटवे', इटली की 'मत्तेई योजना', और चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) महाद्वीप के हर कोने में किसी न किसी आर्थिक और संपर्क कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं।

इनमें से, चीन का बीआरआई सबसे ज्यादा भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पैदा कर रहा है। पिछले 15 वर्षों में, चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा ऋणदाता और विकास भागीदार बना रहा है। बीआरआई के तहत चीन का अफ्रीका में आर्थिक सहयोग 2013 से 2024 के बीच 200 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है। रूस भी अफ्रीका में अपना सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और अब तक 43 देशों के साथ रक्षा सहयोग और उपकरण खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के मामले में रूस अफ्रीका का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इस प्रकार, चीन और रूस ने अफ्रीका में आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के क्षेत्रों पर लगभग एकाधिकार कर लिया है।

एएजीसी भारत और जापान के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है क्योंकि चीन का आर्थिक प्रभाव भारत की वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व की स्थिति, विकास सहयोग और अफ्रीका में दशकों से स्थापित बहुपक्षीय संबंधों को चुनौती दे सकता है। जापान के लिए, स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को बनाए रखना, बहुपक्षीय संगठनों में नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को समर्थन देना, और संसाधन-समृद्ध अफ्रीका के साथ सहयोग करना, वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन की रणनीति अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक विकास के आधार पर गठबंधन बनाना और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आलोचना को दबाना रही है। अफ्रीका में चीन और रूस का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र में उनके मतदान पैटर्न में भी झलकता है। अफ्रीका के आधे से भी कम देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ गंभीर बहुपक्षीय कार्रवाई के पक्ष में मतदान किया। यह बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव भारत के लिए हानिकारक है, जो लगातार वैश्विक शासन में बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार, रूस का बढ़ता प्रभाव जापान की एफओआईपी नीति

आंकड़ों की दृष्टि में भारत-अफ्रीका

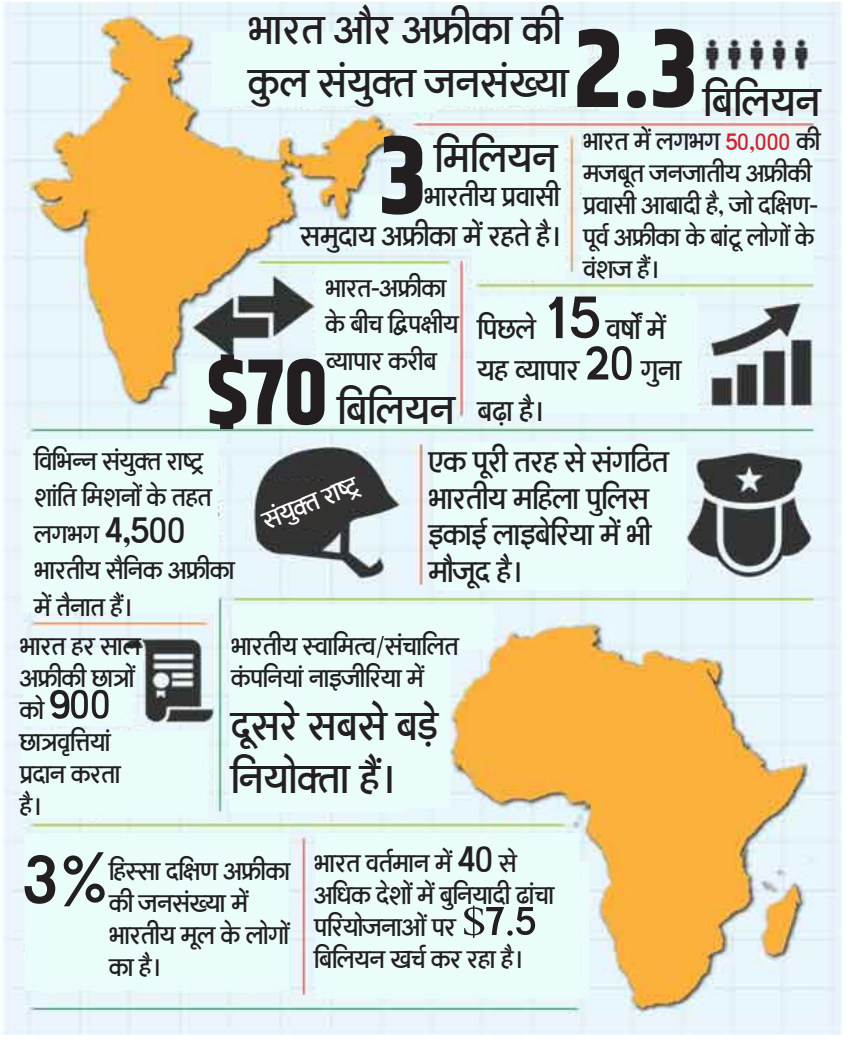

के लिए प्रतिकूल है।

भारत और जापान के अफ्रीका में मिलते हुए हितों को एएजीसी के साकार रूप में देखा जाना चाहिए। एएजीसी अफ्रीका में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को संतुलित करने और दोनों देशों की भू-राजनीतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।

रुकावटें और सिफारिशें

2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें अक्सर मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) अवधारणा के जनक के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह कॉरिडोर तब से बाधित हो गया है। जापान में सरकार के बदलाव, वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव (विशेषकर महामारी के कारण), और कई अन्य प्रतिस्पर्धी कॉरिडोर जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर, और दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की विकास परियोजनाओं के कारण यह परियोजना पटरी से उतर गई।

एएजीसी को मजबूती देने के लिए भारत और जापान को एक तीन-स्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें समान विचारधारा वाले निवेशकों को जोड़ा जाए, अफ्रीकी कॉरिडोर साझेदारों को शामिल किया जाए, और इस कॉरिडोर को हरे-भरे, स्वच्छ और डिजिटल

एएजीसी को मजबूती देने के लिए भारत और जापान को एक तीन-स्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें समान विचारधारा वाले निवेशकों को जोड़ा जाए, अफ्रीकी कॉरिडोर साझेदारों को शामिल किया जाए, और इस कॉरिडोर को हरे-भरे, स्वच्छ और डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया जाए। इसके साथ ही आर्थिक और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बंदरगाह विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

कनेक्टिविटी पहलों के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया जाए। इसके साथ ही आर्थिक और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बंदरगाह विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

निवेशक जोड़नाः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) 2024 में अफ्रीका में सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अबू धाबी के शाही परिवारों के पास डीपी वर्ल्ड और अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप जैसी कंपनियों का नियंत्रण है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर सात बंदरगाहों का संचालन करती हैं। यूएई को एएजीसी में निवेशक के रूप में शामिल करने से कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिल सकती है। भारत और यूएई के बीच विशेष और घनिष्ठ संबंध अबू धाबी को इस कॉरिडोर में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही, क्वाड (क्वाड) देशों को इस साझेदारी में जोड़ने से इस कॉरिडोर के सहयोग ढांचे को औपचारिक रूप से मजबूत किया जा सकता है।

मजबूतियों का लाभ उठानाः एएजीसी के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं की श्रेणियों को पुनर्गठित किया जा सकता है। अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स का परिदृश्य बेहद प्रतिस्पर्धी हो चुका है, जहां अमेरिका का पीजीआई, चीन का बीआरआई, यूरोप का ग्लोबल गेटवे और यूएई परिवहन, समुद्री, रेल, और सड़क संपर्क परियोजनाओं में अग्रणी हैं। भारत और जापान को अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री उपसंरचना, दूरसंचार, ग्रीन टेक और हरित ऊर्जा (सौर, पवन, जल) विकास के क्षेत्र में एएजीसी का विस्तार करना चाहिए। यद्यपि बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्य ध्यान बंदरगाह और आंतरिक भूमि कनेक्टिविटी के साथ-साथ इन क्षेत्रों पर भी होना चाहिए।

अफ्रीकी साझेदारों को जोड़नाः एएजीसी के निवेशकों को अफ्रीका में विस्तार के लिए सेशेल्स, केन्या, मेडागास्कर, और मोज़ाम्बिक जैसे देशों को इस कॉरिडोर में शामिल करना चाहिए। वर्तमान में केवल तंजानिया एएजीसी का हिस्सा है। इन देशों को शामिल करने से व्यापार मार्गों में विविधता आएगी, अफ्रीकी भागीदारी बढ़ेगी, और इन राष्ट्रों को चीन पर समान शर्तों पर निर्भरता से छुटकारा मिलेगा।

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद आर्थिक कनेक्टिविटी, व्यापार और टैरिफ मानकीकरण, और परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बरकरार रहेंगी। फिर भी, क्वाड+यूएई प्रारूप के साथ अफ्रीका से समान विचारधारा वाले प्रतिबद्ध साझेदार एएजीसी को पोस्ट-कोविड प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकते हैं। •

यह लेख 'एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का पुनरुद्धार' पहले ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के ब्लॉग पर प्रकाशित किया गया था। इसे अद्यतन जानकारियों के साथ पुनः साभार प्रकाशित किया जा रहा है।

भारतनेट

अधूरा रह गया है भारत का महत्त्वाकांक्षी इंटरनेट प्रोजेक्ट

पूजा दास

भारतीय सरकार का हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सपना, जिसे भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से साकार किया जाना था, उसकी डिजिटल सशक्तिकरण रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। 2011 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना था, लेकिन 2025 की शुरुआत तक भी यह लक्ष्य अधूरा है। मात्र 1.99 लाख गांव, जो कि 6.5 लाख गांवों का सिर्फ 30.4% हिस्सा हैं, अब तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़े हैं। यह लेख भारतनेट की देरी, अव्यवस्था, और इसकी कमज़ोरी के कारणों पर प्रकाश डालता है, जिसमें फंडिंग, आधारभूत संरचना की समस्याएं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शासन पर इसका प्रभाव शामिल है।

भारतनेट की परिकल्पना और विकास

भारतनेट की जड़ें 2011 में शुरू की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) पहल से जुड़ी हैं। सरकार का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को फाइबर-ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ना था। 2012 में, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को इस परियोजना की निगरानी के लिए स्थापित किया गया। मूल लक्ष्य 2017 तक हर ग्राम पंचायत तक 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना था। हालांकि, भारतनेट की प्रगति धीमी रही और 2014, 2015, 2019 और 2023 की समय सीमाएं लगातार चूक गईं।

भारतनेट पहल को तीन चरणों में विभाजित किया गया

पहला चरण (2011-2014) – इसका लक्ष्य 2014 तक 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना था, लेकिन इस समय सीमा तक केवल 58 कनेक्शन ही स्थापित हो पाए।

दूसरा चरण (2015-2023) – इसमें 150,000 और ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन अगस्त 2023 की विस्तारित समय सीमा तक केवल 2.13 लाख ग्राम पंचायतों को ही जोड़ा जा सका।

तीसरा चरण (2023-2025) – इसका फोकस शेष गांवों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नवाचारी दृष्टिकोणों के माध्यम से जोड़ने पर है। 2025 तक पूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसके पूरा होने पर संदेह जता रहे हैं।

आधारभूत ढांचे और परियोजना निष्पादन में चुनौतियां

भारतनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आधारभूत संरचना का विकास है। बीबीएनएल ने शुरुआत में बीएसएनएल जैसे टेलीकॉम प्रदाताओं के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई थी ताकि ग्राम पंचायतों तक फाइबर-ऑप्टिक बिछाया जा सके, जबकि अंतिम-मील कनेक्टिविटी (इंटरनेट को प्रत्येक घर तक पहुंचाना) स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना था। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक टेलीकॉम प्रदाताओं की कमी के कारण परियोजना का ध्यान बीच की कनेक्टिविटी से हटकर अंतिम-मील सेवा पर आ गया।

2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, विस्तृत नेटवर्क निर्माण के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बैंडविड्थ का केवल 1.19% ही उपयोग हो रहा था। फरवरी 2023 तक ग्रामीण

घरों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन केवल 2% घरों तक ही पहुंच पाए थे, और स्थापित किए गए वाईफाई हॉटस्पॉट्स में से केवल 6% ही सक्रिय थे।

भारतनेट संरचना को बनाए रखने के जिम्मेदार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ रहे, जिससे परियोजना की सफलता में और बाधाएं उत्पन्न हुईं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए कोई समर्पित फंडिंग नहीं थी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता पर असर पड़ा। बाद में, सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें एक केंद्रीकृत नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (सीएनओसी) के माध्यम से 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया गया और सेवा गुणवत्ता समझौतों (एसएलए) के आधार पर भुगतान की व्यवस्था की गई।

भारतनेट परियोजना के वित्तीय संसाधनों का अधूरा उपयोग

भारतनेट परियोजना के वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (यूएसओएफ), जिसे अब 'डिजिटल भारत निधि' के रूप में जाना जाता है, से होता है। अगस्त 2023 तक इसमें ₹ 1,71,588.7 करोड़ की राशि थी, लेकिन केवल आधी राशि का ही उपयोग हो पाया। राज्यों की अक्षमता और प्रभावी ढंग से निधियों का उपयोग न कर पाने के कारण यह समस्या बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे बीएसएनएल को आउटसोर्सिंग और बार-बार परियोजना के दायरे में बदलाव ने प्रगति को और भी अधिक बाधित किया है।

केंद्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति (सीएसईपी) के वरिष्ठ नीति सलाहकार दीपक माहेश्वरी ने कहा कि असली चुनौती राज्य की सीमित क्षमता में निहित है, जो इतने बड़े पैमाने पर परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सीमित विद्युत आपूर्ति, राइट-ऑफ-वे विवाद, और ठेकेदारों की अक्षमता जैसी समस्याएं परियोजना के कार्यान्वयन में और भी बाधा डाल रही हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन में चुनौतियां

भारतनेट की धीमी प्रगति ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक केवल 24% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा के ऑनलाइन मोड में बदलने पर यह कनेक्टिविटी की कमी ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित हुई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, अस्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन को धीमा कर दिया है। हरियाणा जैसे राज्यों में, स्वास्थ्यकर्मी अभी भी इंटरनेट की अनुपलब्धता

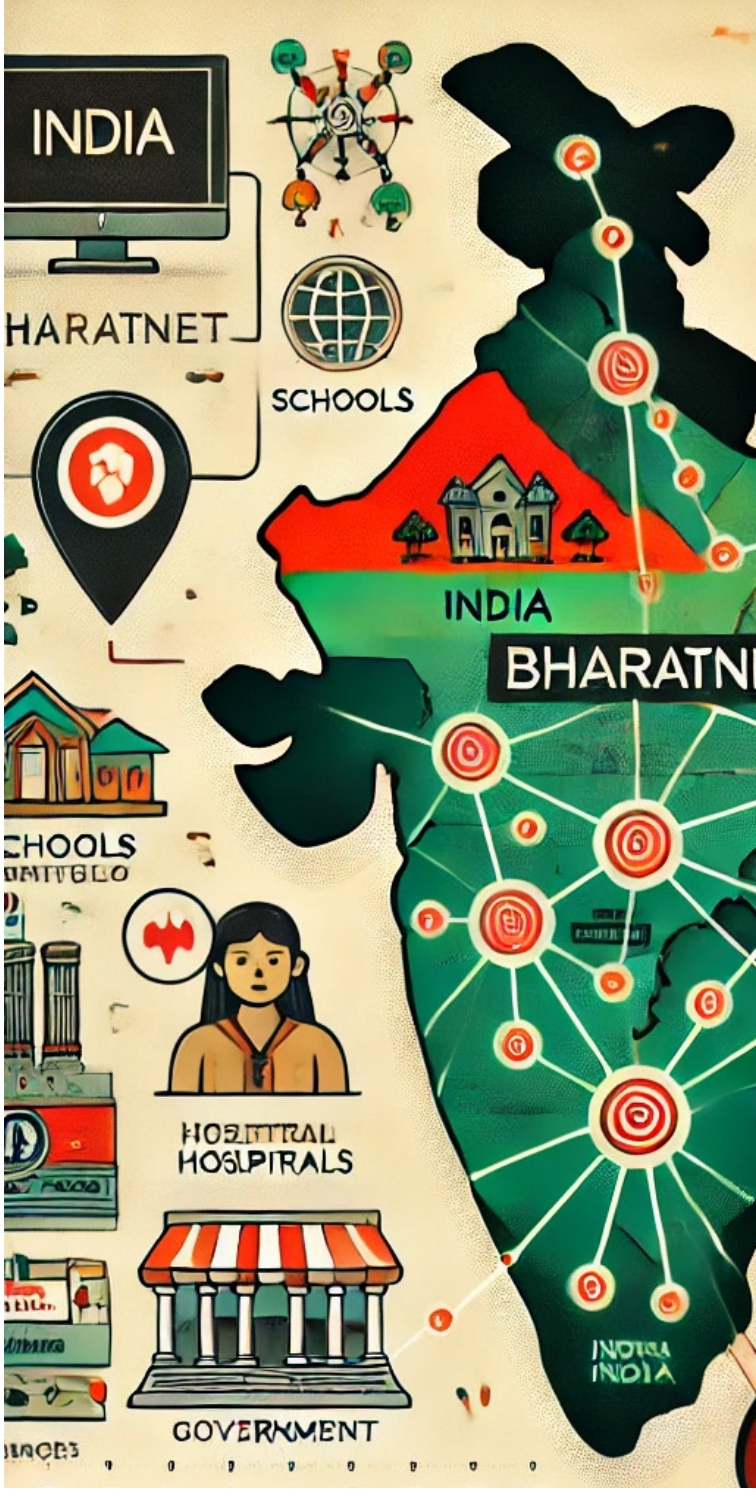

के कारण कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनके कार्यभार में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में देरी होती है।

ई-शासन के क्षेत्र में भी प्रभाव देखा गया है। कई हाशिये पर स्थित समुदायों के लिए आधार केंद्रों की कमी और कमजोर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, कई आदिवासी क्षेत्रों में गैर-संस्थागत जन्म होने

के कारण आधार नामांकन में समस्याएं आती हैं, जो कि सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए आवश्यक होता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि कमजोर कनेक्टिविटी के कारण श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती और उन्हें मजदूरी खोनी पड़ती है।

क्षेत्रीय असमानता और जवाबदेही की कमी

भारतनेट परियोजना का सबसे बड़ा अवरोध क्षेत्रीय असमानता है। कुछ क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, जबकि अन्य, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य, काफी पीछे हैं। 2023 तक, पूर्वोत्तर के केवल 60% ग्राम पंचायतों में सेवा उपलब्ध हो पाई, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% था।

परियोजना की निगरानी और जवाबदेही की स्पष्ट कमी ने इसे और भी देरी दी है। भारतनेट परियोजना में तीसरे पक्ष के आकलन का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन परियोजना की प्रभावशीलता या प्रगति का ट्रैक करने के लिए कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट नहीं है।

आगे का रास्ता: क्या बदलना चाहिए

भारतनेट की सफलता के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों का समाधान आवश्यक है। पहला, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, और निजी ठेकेदारों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। दूसरा, अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को सीधे घरों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए गाँव-स्तरीय उद्यमियों के साथ साझेदारी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल की आवश्यकता होगी, जो स्थानीय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता हो।

बेहतर योजना और कार्यान्वयन तंत्र भी महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक बजट आवंटन के बजाय, एक स्थिर तीन से पांच साल की वित्तीय योजना दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता में सुधार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भारतनेट की सफलता केवल इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को डिजिटल सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारतनेट परियोजना, अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि के बावजूद, देरी, वित्तीय समस्याओं और अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से जूझ रही है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिये पर स्थित समुदायों में, प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, बेहतर योजना, वित्तीय स्थिरता और अंतिम-मील कनेक्टिविटी पर बढ़ते ध्यान के साथ, भारतनेट अभी भी भारत के गांवों में डिजिटल सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह परियोजना अभी भी अधूरी है, लेकिन समर्पित प्रयासों और रणनीतिक सुधारों के साथ, डिजिटल रूप से जुड़े ग्रामीण भारत का सपना साकार हो सकता है। •

यह लेख 'भारतनेट क्यों एक अधूरा सपना बना हुआ है' पहली बार इंडिया स्पेंड पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था। हम इसे अद्यतन जानकारी एवं उचित श्रेय के साथ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

रणनीतिक नृत्य

भारत-अमेरिका की साझेदारी से वैश्विक व्यापार का भविष्य

संदीप कुमार

भारत और अमेरिका की साझेदारी वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। हालांकि, अमेरिका में द्विदलीय समर्थन के बावजूद भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, डिजिटल व्यापार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), और औद्योगिक नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के रुख को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह लेख भारत की जटिल व्यापारिक स्थिति और वैश्विक व्यापार के भविष्य पर अमेरिका-भारत संबंधों के प्रभाव की पड़ताल करता है।

अमेरिका-भारत संबंधों का उदय

भारत की रणनीतिक महत्वता ट्रंप प्रशासन के दौरान काफी बढ़ी, जिसने रक्षा संबंधों को गहराई दी। सिर्फ चार सालों में, भारत ने अमेरिका के साथ तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो इसके पारंपरिक सतर्क दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत थे।

जॉर्ज बुश से लेकर जो बाइडन तक, सभी अमेरिकी प्रशासन ने चीन को अमेरिका-प्रधान वैश्विक व्यवस्था के लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा है। इस मान्यता ने अमेरिका को पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर नई साझेदारियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

भारत की रणनीतिक महत्वता ट्रंप प्रशासन के दौरान काफी बढ़ी, जिसने रक्षा संबंधों को गहराई दी। सिर्फ चार सालों में, भारत ने अमेरिका के साथ तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो इसके पारंपरिक सतर्क दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत थे। बाइडन ने इस नींव पर काम किया है, खासकर भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका और उनके 'फ्रेंडशोरिंग' पहल, जिसका उद्देश्य सप्लाई चेन में विविधता लाना और चीन पर निर्भरता कम करना है, पर जोर दिया है।

इसके बावजूद, अमेरिका की भारत के आर्थिक हितों और उदार अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण में एक जानकारी का अभाव है। इस अंतर को पाटना आवश्यक है, ताकि भारत को चीन के खिलाफ एक प्रभावी संतुलन के रूप में पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, विशेषकर वैश्विक व्यापार में।

रक्षा सहयोग के नीचे व्यापारिक तनाव

जहां रक्षा संबंध फल-फूल रहे हैं, वहीं अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी प्रशासन अक्सर भारत की संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना करता रहा है, जो आयात पर शुल्क लगाती हैं और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती हैं। दूसरी ओर, भारत का तर्क है कि अमेरिका ने उसकी विकासशील देश की स्थिति को मान्यता नहीं दी है, जिससे व्यापार घाटे और शुल्कों पर टकराव हुआ है।

इन तनावों को ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा ने और बढ़ाया, जो भारत की खुद की व्यापार नीतियों से टकराया। हालांकि, इन जटिलताओं का समाधान एक संतुलित संबंध के लिए आवश्यक है। अमेरिका को भारत के व्यापारिक रुख को, खासकर डिजिटल वाणिज्य और औद्योगिक नीति जैसे क्षेत्रों में, गहराई से समझने की जरूरत है, ताकि टकराव के बजाय सहयोग हो सके।

डिजिटल व्यापार: नीति में विरोधाभास

अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंधों में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक डिजिटल व्यापार है। हाल के वर्षों में भारत की तकनीकी क्षेत्र ने जबरदस्त वृद्धि की है और यह दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी केंद्रों में से एक बन गया है। हालांकि, डिजिटल वाणिज्य पर भारत की नीतियां वैश्विक रुझानों से मेल नहीं खातीं।

भारत का डिजिटल व्यापार पर रुख संरक्षणवादी है, जो डेटा लोकलाइजेशन (डेटा को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर संग्रहीत करने) और सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करने पर जोर देता है। ये कदम राष्ट्रीय हितों और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं, लेकिन अक्सर इसकी अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र की आवश्यकताओं के खिलाफ जाते हैं, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। दिलचस्प बात यह है कि बाइडन प्रशासन का डिजिटल व्यापार में संरक्षणवाद की ओर झुकाव भी

इन दोनों देशों को अजीब तरह से एक ही लाइन में खड़ा कर देता है, भले ही भारत की नीति ढांचे में विरोधाभास हों। ट्रंप प्रशासन की इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन डिजिटल वाणिज्य पर अमेरिका-भारत संवाद भविष्य में तकनीक-प्रधान व्यापार सहयोग के लिए एक कसौटी बन सकता है।

डब्ल्यूटीओ में भारत की भूमिका: नेता या बाधा?

भारत ने खुद को डब्ल्यूटीओ में वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। वहीं, ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से पीछे हटने का कदम उठाया, इसकी अक्षमताओं की आलोचना की और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका पर सवाल उठाया। इस वापसी ने भारत के लिए वैश्विक व्यापार एजेंडा को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका खोला है।

हालांकि, भारत का दृष्टिकोण रचनात्मक नहीं रहा है। कृषि वार्ताओं और मछली पकड़ने की सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति को सुगम बनाने के बजाय, भारत अक्सर डब्ल्यूटीओ के एजेंडे को धीमा करता रहा है। यह बाधा भारत की अपनी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो इसके घरेलू उद्योगों और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका अनपेक्षित परिणाम यह हुआ कि जिन वैश्विक दक्षिण देशों का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उनसे वह अलग-थलग पड़ गया है।

यह विरोधाभास अमेरिका और डब्ल्यूटीओ दोनों के लिए एक चुनौती है। डब्ल्यूटीओ में नेतृत्व की भूमिका निभाने की भारत की इच्छा उसके कार्यों से मेल नहीं खाती, जो अक्सर वैश्विक व्यापार वार्ताओं में बाधा डालते हैं। अमेरिका के लिए, डब्ल्यूटीओ में भारत के साथ प्रभावी जुड़ाव आवश्यक है ताकि दोनों देशों के व्यापारिक हितों का संतुलन बन सके और वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अखंडता बनी रहे।

औद्योगिक नीति: उद्देश्यपूर्ण संरक्षणवाद

भारत लंबे समय से ऐसी औद्योगिक नीतियों पर निर्भर रहा है जो घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, को प्राथमिकता देती हैं। इन नीतियों में सब्सिडी और आयात शुल्क शामिल हैं, जो भारतीय निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने और स्थानीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि, ये उपाय व्यापार विवादों का कारण बनते हैं, खासकर उन देशों के साथ, जैसे कि अमेरिका, जो इन नीतियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में देखते हैं।

फिर भी, औद्योगिक नीति भारत के लिए अनूठी नहीं है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और यहां तक कि चीन ने भी अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार की नीतियों को अपनाया है, खासकर COVID-19 महामारी के बाद। वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद की प्रवृत्ति ने एक प्रकार से भारत की इस नीति को वैधता प्रदान की है। हालांकि, भारत की नीतियां अक्सर अधिक कठोर होती हैं और अभी तक इसके विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं ला पाई हैं।

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी औद्योगिक नीतियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ गहरे एकीकरण की आवश्यकता के साथ संतुलित करे। अमेरिका के लिए, भारत की औद्योगिक विकास की आवश्यकता को समझना और सम्मान करना अनावश्यक व्यापार संघर्षों से बचने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आगे का रास्ता: व्यापार सहयोग के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण

भारत के साथ एक वास्तविक प्रभावी साझेदारी बनाने के लिए, अमेरिका को व्यापार पर अधिक सूक्ष्म संवाद में संलग्न होना होगा। केवल भारत को रक्षा सहयोग या चीन के मुकाबले एक प्रतिरोधक के रूप में देखने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका को भारत की डिजिटल व्यापार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में उसकी भूमिका, और उसकी औद्योगिक नीतियों के प्रति चिंताओं को इस दृष्टिकोण से संबोधित करना होगा कि वह भारत के विकासात्मक आवश्यकताओं और वैश्विक मंच पर नेतृत्व की उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझे और सम्मानित करे।

भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण की गहन समझ ही अमेरिका-भारत संबंधों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। अंतर्निहित तनावों को संबोधित करके और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करके, दोनों देश रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर एक अधिक संतुलित और स्थायी आर्थिक साझेदारी बना सकते हैं।

निष्कर्ष: वैश्विक व्यापार के भविष्य को आकार देना

अमेरिका-भारत संबंध केवल चीन के उदय की पृष्ठभूमि में की जा रही एक रणनीतिक नृत्य से कहीं अधिक हैं। यह एक बहुआयामी साझेदारी है, जो यदि देखरेख और आपसी समझ के साथ संभाली जाए, तो वैश्विक व्यापार व्यवस्था को पुनः आकार दे सकती है। भारत के व्यापार से संबंधित अद्वितीय चुनौतियों और दृष्टिकोणों को संबोधित करके, अमेरिका एक अधिक न्यायसंगत और स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों लोकतंत्र तेजी से बदलती दुनिया में व्यापार, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास की जटिलताओं को कैसे नेविगेट करते हैं। •

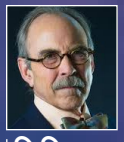

विलियम एच. जेनेवे

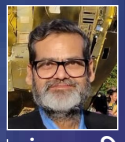

संजय श्रीवास्तव

AI एल्गोरिदम से परे

Beyond Algorithms

अनिश्चितता हमेशा से मानव अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा रही है। चाहे हम अपने बौद्धिक प्रयासों या तकनीकी चमत्कारों के माध्यम से कितनी भी प्रगति कर लें, जीवन की अराजक प्रकृति बनी रहती है। जितना हम इस दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यह अक्सर हमारे प्रयासों को चुनौती देती है। आज, कई लोग इस आशा में हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक जटिल होती दुनिया में स्पष्टता ला सकती है, लेकिन दो नई किताबें इस धारणा पर सवाल उठाती हैं। वे यह सुझाव देती हैं कि हमें उम्मीद करने के बजाय कि एआई हमारे चारों ओर की अराजकता को नियंत्रित करेगा, हमें शायद उस अनिश्चितता को अपनाना होगा जो हमारे जीवन को आकार देती है।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड स्पीगलहॉल्टर और नील डी. लॉरेंस, अपनी पुस्तकों में, अनिश्चितता की मूल प्रकृति और इसके हमारे दैनिक जीवन में स्थायी प्रभावों का अध्ययन करते हैं। स्पीगलहॉल्टर, जो एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् हैं, और लॉरेंस, जो मशीन लर्निंग के विशेषज्ञ हैं, अपनी विविध व्यावसायिक अनुभवों पर आधारित होकर यह जांचते हैं कि मानवता ने ऐतिहासिक रूप से अनिश्चितता को कैसे मापा, प्रबंधित किया और इसके साथ जीने की कोशिश की। उनके विश्लेषण गहराई से इस बात की पड़ताल करते हैं कि हम जोखिम को कैसे समझते हैं, विश्वास कैसे बनाया या खोया जाता है, और एआई का आधुनिक दुनिया को आकार देने में क्या योगदान है।

अनिश्चितता का स्थायी स्वभाव

अंग्रेजी कवि जॉर्ज मेरिडिथ ने 150 से अधिक वर्षों पहले अनिश्चितता की निराशा को

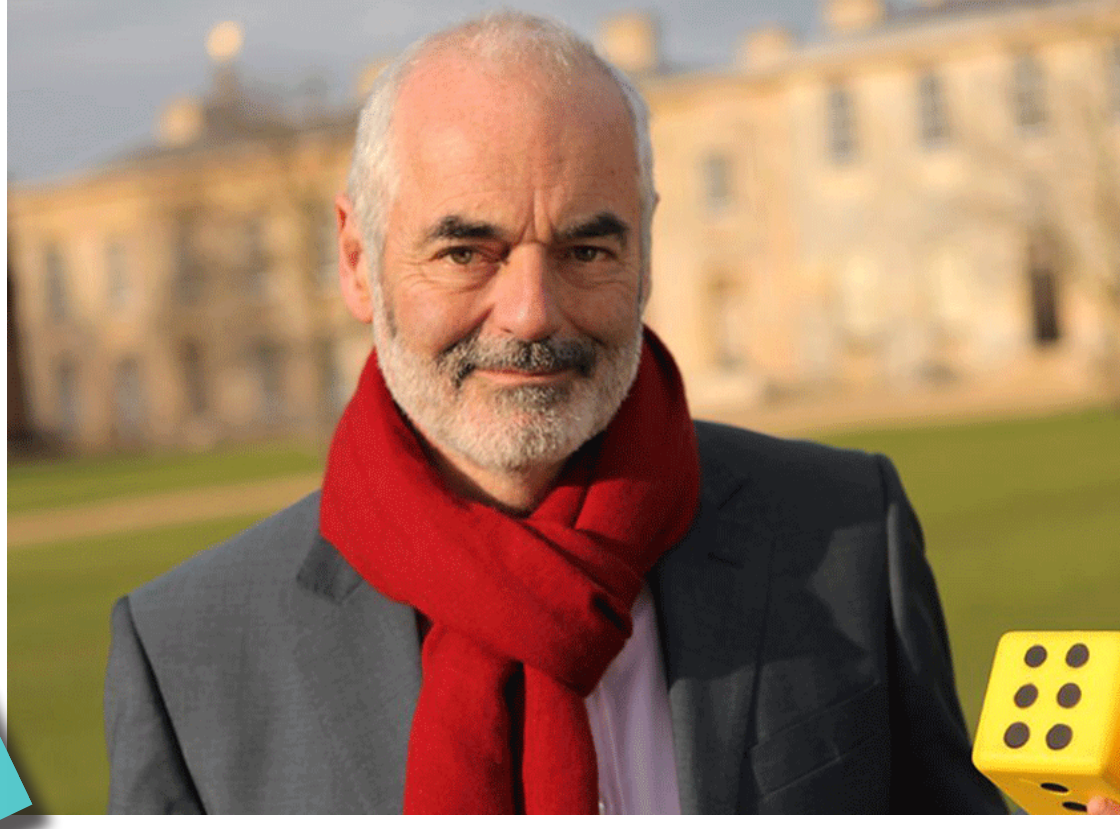

सर डेविड जॉन स्पीगेलहॉल्टर एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद् हैं, चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज के फेलो और सार्वजनिक जोखिम समझ के लिए पूर्व विंटन प्रोफेसर रह चुके हैं। वह विंटन सेंटर फॉर रिस्क एंड एविडेंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष हैं। उनकी हालिया पुस्तक 'द आर्ट ऑफ अनसर्टेन्टी' को व्यापक सराहना मिली है। वह यूके सांख्यिकी प्राधिकरण के अकार्यकारी निदेशक भी हैं।

इस पंक्ति में अभिव्यक्त किया था, 'What a dusty answer gets the soul when hot for certainties in this our life!' (क्या धूल भरा उत्तर मिलता है आत्मा को, जब यह निश्चितताओं के लिए आतुर होती है इस जीवन में!) यह भावना स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस दोनों के कार्यों के केंद्र में है। दोनों लेखक मानते हैं कि अनिश्चितता केवल मानव अज्ञानता या नियंत्रण की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि अस्तित्व का एक मौलिक पहलू है। विज्ञान और तकनीक में हमारी प्रगति के बावजूद, अनिश्चितता एक अपरिहार्य सत्य बनी रहती है।

अपनी पुस्तक में, स्पीगलहॉल्टर उन ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं जिनके माध्यम से मानवता ने अनिश्चितता को मापने का प्रयास किया है। वे विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का विश्लेषण करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंटिस्ट दृष्टिकोण और बेयसियन विश्लेषण, जो एक अप्रत्याशित दुनिया में भविष्यवाणी की एक भावना प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं। फ्रीक्वेंटिस्ट विधियां तब प्रभावी होती हैं जब जोखिमों को शारीरिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे सिक्का उछालने की संभावना। दूसरी ओर, बेयसियन विश्लेषण में व्यक्तिपरक जोखिम आकलन शामिल होते हैं और यह अक्सर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अधिक अनुकूल होता है, जहां अनिश्चितता कम स्पष्ट होती है।

नील डी. लॉरेंस इस चर्चा में एक अलग दृष्टिकोण लाते हैं, अपनी मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि को मिलाकर यह बताते हैं कि अनिश्चितता कैसे तकनीकी प्रगति को आकार देती है। शैक्षणिक जीवन में प्रवेश करने से पहले, लॉरेंस ने एक नॉर्थ सी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर एक इंजीनियर के रूप में काम किया था, जहाँ उन्होंने देखा कि कैसे अप्रत्याशित घटनाएं सबसे सुनियोजित ऑपरेशनों को भी बाधित कर सकती हैं। उनके कॉर्पोरेट और शैक्षणिक दोनों दुनियाओं में अनुभव उन्हें आधुनिक सिस्टम, विशेष रूप से एआई, द्वारा अनिश्चितता से निपटने के तरीकों का विश्लेषण करने का एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अनिश्चितता के युग में विश्वास

स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस के कार्यों को एकजुट करने वाला एक केंद्रीय विषय 'विश्वास' का विचार है। एक ऐसी दुनिया में जो अनिश्चितताओं से भरी हुई है, विश्वास एक महत्वपूर्ण मुद्रा बन जाता है। इसके बिना, समाज सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते।

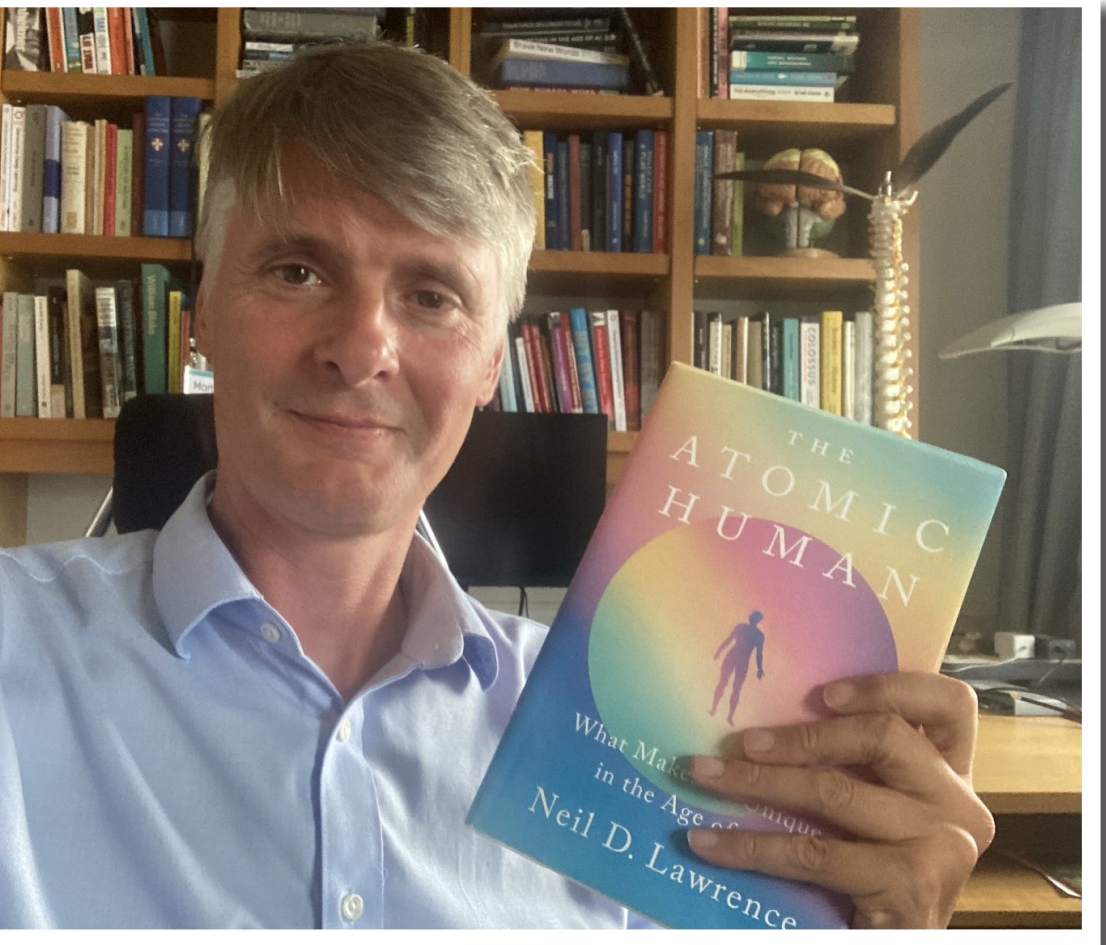

नील डेविड लॉरेंस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डीपमाइंड प्रोफेसर ऑफ मशीन लर्निंग हैं और एलन ट्यूरिंग संस्थान में वरिष्ठ एआई फेलो तथा शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। उनकी हालिया पुस्तक 'द एटॉमिक ह्यूमन' ने व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है।

चाहे वह सरकारों, संस्थाओं, या व्यक्तियों पर विश्वास हो, यह अमूर्त लेकिन आवश्यक तत्व समाज को एक साथ बांधे रखता है।

स्पीगलहॉल्टर दार्शनिक ओनोरा ओ'नील के कार्यों पर आधारित हैं, विशेष रूप से उनके 'बुद्धिमान पारदर्शिता' के सिद्धांत पर। ओ'नील के अनुसार, नीति निर्माताओं को अनिश्चितता के सामने विश्वास को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी होना चाहिए, और यह पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए जो जनता को जानकारी को समझने और उस पर विचार करने में सक्षम बनाए। स्पीगलहॉल्टर का तर्क है कि इस प्रकार की पारदर्शिता विश्वास बनाने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उस युग में जब गलत सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं।

लॉरेंस भी विश्वास के महत्व को छूते हैं, विशेष रूप से एआई के संदर्भ में। 2022 के अंत में ChatGPT जैसे जेनरेटिव एआई मॉडल्स के उदय के बाद से, यह बहस बढ़ी है कि क्या इन सिस्टम्स पर भरोसा किया जा सकता है। ये मॉडल मानव-जनित डेटा के विशाल भंडार को संसाधित करते हैं और अक्सर विचारशील और सटीक प्रतीत होने वाली प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन लॉरेंस सवाल करते हैं कि क्या यह विश्वास सही है। वे ओ'नील के उस तर्क का उल्लेख करते हैं कि विश्वास किसी प्रणाली में अंतर्निहित नहीं होता, बल्कि इसे उन लोगों द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए जो उन प्रणालियों को संचालित करते हैं। अगर एआई मॉडल्स को मानव पर्यवेक्षण से अलग किया गया है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय सही ढंग से लेंगे?

जेनरेटिव एआई का उदय

2022 के अंत में ChatGPT का लॉन्च एआई पर सार्वजनिक चर्चा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ChatGPT जैसे जेनरेटिव मॉडल्स तकनीक के भविष्य और समाज में इसकी भूमिका पर होने वाली बहसों के केंद्र बिंदु बन गए हैं। ये मॉडल्स विशाल मात्रा में डेटा के आधार पर टेक्स्ट और दृश्य प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं, जिससे कई लोगों का मानना है कि एआई आधुनिक जीवन की अराजकता को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

हालांकि, स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस दोनों इन सिस्टम्स पर अधिक विश्वास करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि एआई मॉडल्स मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपकरण हैं, और अन्य किसी भी उपकरण की तरह इनकी भी सीमाएं हैं। ये मॉडल्स तार्किक प्रतीत होने वाली प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन इनका दुनिया की वास्तविक समझ नहीं होती। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ यह है कि एआई वह निश्चितता प्रदान नहीं कर सकता जिसकी कई लोग उम्मीद करते हैं। वास्तव

में, एआई पर अत्यधिक निर्भरता और भी अधिक अनिश्चितता पैदा कर सकती है, क्योंकि ये मॉडल्स त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं और गलत या भ्रामक परिणाम उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं।

लाप्लास का डेमन और पूर्वानुमान की सीमाएं

दोनों पुस्तकों के केंद्र में 'लाप्लास का डेमन' नामक एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग पर चर्चा है। 1814 में, फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे-साइमन लाप्लास ने एक ऐसे डेमन की कल्पना की थी, जिसे ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति का संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें प्रकृति की सभी शक्तियाँ और हर परमाणु की स्थिति शामिल हो। इस ज्ञान के साथ, वह डेमन भविष्य की भविष्यवाणी पूर्ण निश्चितता के साथ कर सकता था, जिससे संयोग की अवधारणा अर्थहीन हो जाती।

लाप्लास का डेमन ब्रह्मांड के एक निर्धारक (deterministic) दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सब कुछ एक पूर्वानुमानित पथ का अनुसरण करता है। हालाँकि, स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस दोनों तर्क देते हैं कि हमारा संसार इससे बहुत अलग है। हमारी सर्वोत्तम कोशिशों के बावजूद, कि हम अपने पर्यावरण को समझ सकें और नियंत्रित कर सकें, अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लॉरेंस इस वास्तविकता को 'लाप्लास का ग्रीमलिन' कहते हैं, यह इंगित करते हुए कि अप्रत्याशितता मानव जीवन की एक परिभाषित विशेषता है। चाहे हमारे उपकरण कितने भी परिष्कृत क्यों न हो जाएं, हमेशा ऐसे कारक होंगे जो हमारे नियंत्रण से बाहर होंगे—चाहे वह अंधा संयोग हो, भाग्य हो, या अज्ञानता—जो घटनाओं की दिशा को आकार देते हैं।

अनिश्चितता को अपनाना

अंततः, दोनों लेखक एक समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: अनिश्चितता हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा है। जबकि हम बेहतर उपकरण विकसित कर सकते हैं जो जोखिमों को प्रबंधित करने और जटिलताओं से निपटने में मदद करें, हम अनिश्चितता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। यह एहसास हमें अनिश्चितता के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जैसे-जैसे हम एक तेजी से अप्रत्याशित दुनिया में आगे बढ़ते हैं, विश्वास, पारदर्शिता और मानव पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

एक ऐसे समय में जब कई लोग तकनीक से स्पष्टता और नियंत्रण लाने की उम्मीद कर रहे हैं, स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस एक वास्तविकता पर आधारित याद दिलाते हैं कि अनिश्चितता ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पूरी तरह से हरा सकते हैं। यह मानव स्थिति का एक अभिन्न हिस्सा है, और इसे जीतने के बजाय, इसके साथ नेविगेट करना सीखना 21वीं सदी में सफल होने की कुंजी हो सकता है।

अनिश्चितता को वश में करना: स्पीगलहॉल्टर के दृष्टिकोण से अप्रत्याशितता का प्रबंधन

अनिश्चितता, जो मानव अस्तित्व का एक अभिन्न पहलू है, सदियों से विद्वानों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित करती रही है। यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और ठोस शक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन और निर्णयों को प्रभावित करती है। अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ अनसर्टेंटी (The Art of Uncertainty) में डेविड स्पीगलहॉल्टर इस बात की पड़ताल करते हैं कि मानवता निरंतर अप्रत्याशित दुनिया को समझने, प्रबंधित करने और उससे निपटने के लिए कैसे संघर्ष करती है। संभावना के सिद्धांत (Probability Theory) के दृष्टिकोण से, वे इस पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि हम अनिश्चितता का सामना कैसे करते हैं, और यह हमारे दृष्टिकोण, विकल्पों, और वास्तविकता के मॉडल पर कैसे गहरा प्रभाव डालती है। स्पीगलहॉल्टर का कार्य यह उजागर करता है कि संभावनाएँ किस प्रकार अनियमितता और हमारी अज्ञानता दोनों से गहराई से जुड़ी होती हैं, जिससे पाठकों को उन जटिल शक्तियों को समझने का एक बेहतर तरीका मिलता है जो हमारे भविष्य को आकार देती हैं।

संभावनाओं का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनिश्चितता का स्वभाव

स्पीगलहॉल्टर के मुख्य तर्कों में से एक यह है कि संभावना कोई बाहरी, वस्तुनिष्ठ शक्ति नहीं है जो मानव अवलोकन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होती है। इसके बजाय, यह अत्यधिक व्यक्तिगत होती है और हमारे अनुभवों, ज्ञान, और पूर्वाग्रहों द्वारा आकार ली जाती है।

स्पीगेलहॉल्टर के मुख्य तर्कों में से एक यह है कि संभावना कोई बाहरी, वस्तुनिष्ठ शक्ति नहीं है, जो मानव अवलोकन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती हो।

यह दृष्टिकोण पारंपरिक मान्यता को चुनौती देता है कि संभावनाएँ केवल गणितीय संरचनाएँ हैं जो खोजी जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बल्कि, यह हमारे और अनिश्चितता के बीच के संबंध को दर्शाती हैं, जो इस बात को प्रतिबिंबित करती हैं कि हम अपनी अज्ञानता के प्रति कितने जागरूक हैं।

इसे स्पष्ट करने के लिए, स्पीगलहॉल्टर एक क्लासिक उदाहरण पेश करते हैं: एक सिक्का उछालने की साधारण क्रिया। इस परिदृश्य में, वे बताते हैं कि दो प्रकार की अनिश्चितताएँ खेल में हैं। पहला है एलेटरी अनिश्चितता (aleatory uncertainty), जो एक घटना की अंतर्निहित अनियमितता को संदर्भित करता है, जैसे सिक्का उछालने की प्रक्रिया। दूसरा है एपिस्टेमिक अनिश्चितता (epistemic uncertainty), जो किसी ऐसी घटना के बारे में जानकारी की कमी से उत्पन्न होती है जो पहले ही घट चुकी हो (जैसे, सिक्का सिर की तरफ गिरा है या पूंछ की तरफ)। जबकि हम सिक्के के सिर या पूंछ की तरफ गिरने की संभावना का मॉडल बना सकते हैं (एलेटरी), हम तब तक किसी विशेष उछाल का परिणाम नहीं जान सकते जब तक कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से न देख लें (एपिस्टेमिक)।

स्पीगलहॉल्टर इस उदाहरण का उपयोग इस बात को समझने के लिए करते हैं कि सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करके हम अधिक जटिल परिस्थितियों में अनिश्चितता को कैसे कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक छह-पक्षीय पासा फेंकते हैं, तो हम जानते हैं कि हर तरफ के ऊपर आने की समान संभावना होती है। यह सरल फ्रीक्वेंटिस्ट (frequentist) दृष्टिकोण, जो पिछले परिणामों पर आधारित होता है, हमें भविष्य के संभावित परिणामों की सीमा को संकुचित करने की अनुमति देता है। हालांकि, जब परिणाम भौतिक सीमाओं से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते या जब मानव व्यवहार शामिल होता है, तो स्थिति काफी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

मॉडलों की सीमाएँ और गेम थ्योरी की भूमिका

स्पीगलहॉल्टर इस बात पर जोर देते हैं कि जबकि मॉडल्स हमें अनिश्चितता से निपटने में मदद कर सकते हैं, वे वास्तविकता के संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं होते। एक मॉडल, एक नक्शे की तरह, दुनिया को सरल बनाने वाली एक उपयोगी अमूर्तता है, लेकिन यह कभी भी उसकी सभी जटिलताओं को कैप्चर नहीं कर सकता। यह अंतर्दृष्टि विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब हम मानव व्यवहार से निपट रहे होते हैं, जिसे सटीकता के साथ अनुमान लगाना अक्सर कठिन होता है।

उदाहरण के लिए, गेम थ्योरी ने सामरिक निर्णय लेने की हमारी समझ में कठोरता जोड़ी है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां व्यक्तियों को केवल दूसरों के कार्यों का ही नहीं, बल्कि उन कार्यों के प्रति उनकी अपेक्षाओं का भी जवाब देना होता है। फिर भी, जैसा कि फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस ने दिखाया है, जब व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करते हैं, तो यह एक पुनरावृत्त चक्र उत्पन्न करता है जो हमारी पूर्वानुमान की क्षमता की सीमाओं को धक्का देता है। यह प्रतिक्रिया पाश जटिलता की एक और परत जोड़ता है, जिससे मानव निर्णयों का मॉडल बनाना और भविष्यवाणी करना और भी कठिन हो जाता है।

स्पीगलहॉल्टर हमें याद दिलाते हैं कि सभी मॉडल, चाहे वे कितने भी परिष्कृत क्यों न हों, अंततः सीमित होते हैं। वे वास्तविकता का लगभग अनुमान होते हैं, वास्तविकता नहीं। उनके काम में इस बात को स्वीकार करना कि मॉडल त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, एक केंद्रीय विषय है, और यह दिखाता है कि अनिश्चितता से निपटने के लिए लचीलापन, संशयवाद, और निरंतर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

बेयसियन विश्लेषण की शक्ति

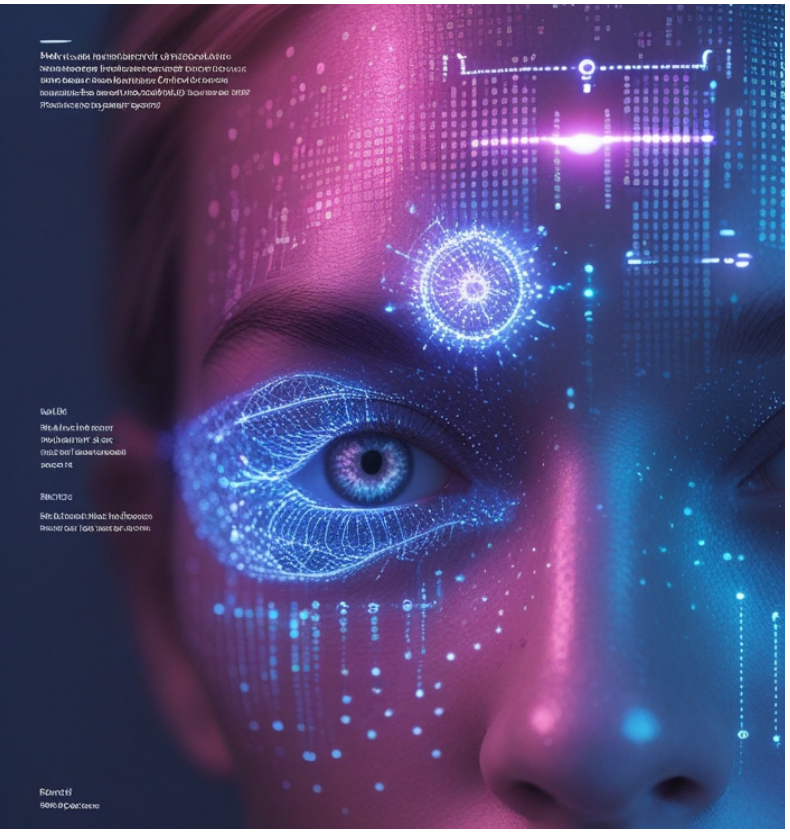

स्पीगलहॉल्टर के अनुसार, संभावना सिद्धांत के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बेयस प्रमेय (Bayes' Theorem) है। यह प्रमेय 18वीं सदी में अंग्रेज़ मंत्री थॉमस बेयस द्वारा तैयार किया गया था, और इसने इस बात को पूरी तरह से बदल दिया कि हम संभावनाओं के बारे में कैसे सोचते हैं। इसके मूल में, बेयस प्रमेय हमें नए साक्ष्य के आलोक में अपनी मान्यताओं को अपडेट करने की अनुमति देता है। यह पूर्व संभावना (prior probability) को परिभाषित करता है, यानी किसी परिणाम की संभावना को देखते हुए हमें जो साक्ष्य मिले हैं, और फिर इसे अद्यतन करता है जब हमें नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

स्पीगलहॉल्टर बेयस प्रमेय के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को विचारोत्तेजक उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, क्यों अधिक टीकाकृत लोग कोविड-19 से मर सकते हैं, बजाय उनके जो टीकाकरण नहीं कराए गए हैं? पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है। लेकिन बेयसियन तर्क के माध्यम से हम इस तथ्य का आकलन कर सकते हैं कि जब अधिकांश जनसंख्या टीकाकृत होती है, तो अधिक संख्या में लोग टीकाकृत समूह में होंगे, और इसलिए कुल मौतों की संख्या अधिक हो सकती है, भले ही टीकाकृत व्यक्तियों में मृत्यु का जोखिम कम हो।

एक अन्य उदाहरण में पुलिस इमेजिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो संभावित खतरों को चिह्नित करता है। बेयसियन विश्लेषण का उपयोग करते हुए, हम यह आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में वह व्यक्ति जो सॉफ़्टवेयर द्वारा चिह्नित किया गया है, एक खतरा है या नहीं, सॉफ़्टवेयर की समग्र सटीकता और जनसंख्या में खतरों की व्यापकता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए।

ये उदाहरण एक प्रमुख बिंदु को रेखांकित करते हैं: संभावनाएँ हमेशा भौतिक गुणों का कार्य नहीं होतीं, जैसे सिक्का या पासा। अक्सर, वे व्यक्तिपरक अपेक्षाओं और साक्ष्य की व्याख्याओं से आकार लेती हैं। बेयस प्रमेय हमें इस व्यक्तिपरकता को हमारे विश्लेषण में शामिल करने का एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे हमें नए साक्ष्य उपलब्ध होने पर अनिश्चितता की हमारी समझ को परिष्कृत करने में मदद मिलती है।

क्रॉमवेल का नियम: अनिश्चितता को अपनाना

सांख्यिकीय तर्क की शक्ति के बावजूद, स्पीगलहॉल्टर यह स्वीकार करते हैं कि अनिश्चितता को पूरी तरह से नियंत्रित करने की हमारी क्षमता स्वाभाविक रूप से सीमित है। वे क्रॉमवेल के नियम पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह चेतावनी देता है कि किसी भी घटना को शून्य या एक की संभावना नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह तार्किक रूप से असंभव या निश्चित न हो। यह नियम ओलिवर क्रॉमवेल की 1650 में स्कॉटलैंड की चर्च की जनरल असेंबली से की गई एक अपील के नाम पर रखा गया है और यह हमें वास्तविक दुनिया की जटिल परिस्थितियों में त्रुटि की संभावना और पुनर्मूल्यांकन के लिए खुले रहने की याद दिलाता है।

व्यावहारिक रूप से, क्रॉमवेल का नियम हमें भविष्यवाणियों में अत्यधिक आत्मविश्वास से बचने की चेतावनी देता है। जब भी संभावनाएँ कम प्रतीत होती हैं, अप्रत्याशित घटनाओं के घटने की संभावना बनी रहती है। स्पीगलहॉल्टर इस नियम का उपयोग यह उजागर करने के लिए करते हैं कि एक अनिश्चित दुनिया में पूर्ण निश्चितता खतरनाक हो सकती है। औपचारिक तर्क की सीमाओं के बाहर, जहाँ परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, हमेशा संदेह, अस्पष्टता और आश्चर्य के लिए जगह होती है।

जीवन की अनिश्चितता को अपनाना

द आर्ट ऑफ अनसर्टेंटी (The Art of Uncertainty) में, डेविड स्पीगलहॉल्टर इस बात की गहन पड़ताल करते हैं कि हम जीवन की अप्रत्याशितता को कैसे देखते हैं, उसका मॉडल कैसे बनाते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण को दार्शनिक अंतर्दृष्टियों के साथ मिलाकर, वे पाठकों को अनिश्चितता को मानव स्थिति का अपरिहार्य हिस्सा मानने का निमंत्रण देते हैं।

अनिश्चितता को समाप्त करने की कोशिश करने के बजाय, हमें इसके साथ जीना सीखना चाहिए, और बेयसियन विश्लेषण और गेम थ्योरी जैसे उपकरणों का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, हमें अनिश्चितता के सामने विनम्र बने रहना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे मॉडल और हमारे ज्ञान की भी सीमाएँ हैं।

आखिरकार, स्पीगलहॉल्टर का काम यह याद दिलाने का काम करता है कि अनिश्चितता कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे समझने की ज़रूरत है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ अप्रत्याशितता ही सामान्य है, अनिश्चितता को अपनाने की कला हमारी क्षमता में है कि हम जीवन की जटिलताओं से जिज्ञासा और खुलेपन के साथ कैसे निपटते हैं।

विश्वासपूर्ण प्राणी: एआई के युग में मानव बुद्धिमत्ता की अवधारणा का विस्तार

द आर्ट ऑफ अनसर्टेंटी में मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर गहराई से विचार करते हुए, स्पीगलहॉल्टर ने रैडिकल अनसर्टेंटी (कट्टर अनिश्चितता) के विचार के खिलाफ एक सूक्ष्म तर्क प्रस्तुत किया है। जबकि फ्रैंक नाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया था कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हम वास्तव में नहीं जानते, स्पीगलहॉल्टर इस मानवीय संबंध के बारे में एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। वे इस धारणा को खारिज करते हैं कि हम पूरी तरह से भविष्य से अंधे हैं। इसके बजाय, उनका मानना है कि अनिश्चितता एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रबंधित किया जा सकता है, भले ही इसे पूरी तरह से नियंत्रित न किया जा सके। अनिश्चितता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पर जोर देकर, स्पीगलहॉल्टर औपचारिक विश्लेषण की सीमाओं को फिर से पुष्ट करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं। उनका तर्क दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों है, जो यह प्रकट करता है कि हम अज्ञात के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं और कैसे व्यक्तिपरक संभावनाएँ हमारी घटनाओं की समझ को आकार देती हैं।

'द आर्ट ऑफ अनसर्टेन्टी' में डेविड स्पीगेलहॉल्टर इस बात की प्रभावशाली पड़ताल करते हैं कि हम जीवन की अनिश्चितता को कैसे समझते, उसका मॉडल तैयार करते और उसे नेविगेट करते हैं।

स्पीगलहॉल्टर का 'व्यक्तिगत निष्कर्ष' विश्लेषणात्मक कठोरता और गहरे, ओन्टोलॉजिकल अनसर्टेंटी के सामने अनुकूल सोच की आवश्यकता के बीच तनाव को उजागर करता है। यह प्रकार की अनिश्चितता सरल अज्ञात से परे है और अस्तित्व की अंतर्निहित अप्रत्याशितता को छूती है, जिसे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम बताता है कि एक बंद प्रणाली में क्रम अनिवार्य रूप से अनियमितता में बदल जाता है। स्पीगलहॉल्टर इस एंट्रॉपी को जीवन का हिस्सा मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि औपचारिक मॉडलों पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय, मनुष्यों को ऐसी रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो अनुमानित और अनपेक्षित दोनों परिणामों के अनुकूल हो सकें। इस प्रकार, अनिश्चितता कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह मानवता के सामने हमेशा से रही एक चुनौती है।

अनिश्चितता और अनुकूलनशीलता के बीच यह संबंध लॉरेंस के कार्य द एटॉमिक ह्यूमन में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जहाँ वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के संदर्भ में मानवीय सार का अध्ययन करते हैं। लॉरेंस स्पीगलहॉल्टर के मानव बुद्धिमत्ता के विश्लेषण और उस अनुकूलनशीलता के बीच तुलना करते हैं जो एक अनिश्चित दुनिया में फलने-फूलने के लिए आवश्यक है। वे 'परमाणु मानव' (atomic human) का विचार प्रस्तुत करते हैं, जो एक रूपक है और यह बताता है कि मानवीय बुद्धिमत्ता अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने की हमारी क्षमता से उत्पन्न होती है। लॉरेंस का विश्लेषण एआई और मानव अनुभूति के बीच की खाई को पाटता है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जो तकनीक के इतिहास को गहराई से प्रभावित करता हैः क्या मशीनें कभी वास्तव में मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल कर सकती हैं?

औपचारिक विश्लेषण की सीमाएँ और अनुकूलन की शक्ति

इस अनुकूलनशीलता का सबसे सशक्त उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान D-Day की पूर्व संध्या पर जनरल ड्वाइट आइजनहावर के निर्णय लेने की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। मित्र देशों की सेनाओं के कमांडर के रूप में, आइजनहावर के पास जर्मन सिफरों के महत्वपूर्ण डिक्रिप्ट्स सहित भारी मात्रा में खुफिया जानकारी थी, जिसे एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने तोड़ा था। हालांकि, उपलब्ध सभी जानकारी के बावजूद, आइजनहावर को अनिश्चितता के आधार पर निर्णय लेना पड़ा। इस निर्णय को लेते समय, उन्होंने औपचारिक विश्लेषण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत दृढ़ता के साथ अज्ञात को अपनाया। जब उन्होंने ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के असफल होने पर पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए एक ज्ञापन लिखा, तब यह एक शक्तिशाली गवाही थी कि मानव बुद्धिमत्ता कैसे विश्वास और निर्णय लेने के माध्यम से अनिश्चितता का सामना कर सकती है, सिर्फ ठंडे विश्लेषण के बजाय।

यह प्रकरण लॉरेंस के व्यापक सिद्धांत से गहराई से मेल खाता है, जिसमें वे मानव इतिहास में बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि मानव संज्ञानात्मक शक्ति प्राकृतिक चयन के

माध्यम से विकसित हुई है ताकि पर्यावरण में निहित अप्रत्याशितता से निपटा जा सके। समय के साथ, मनुष्यों ने जटिल कथाओं को संप्रेषित करने, ज्ञान और अनुभवों को साझा करने, और समाजों में विश्वास और सहयोग बनाने की क्षमता विकसित की। यह संचार और कथानिर्माण की क्षमता ही है जो हमें मशीनों से अलग करती है। यह एक विकासात्मक गुण है जो हमें 'माइंड थ्योरीज़' बनाने की अनुमति देता है, यानी हम अन्य लोगों के विचारों और इरादों का मॉडल बना सकते हैं—ऐसी चीज़ जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कम से कम वर्तमान स्वरूप में, नहीं कर सकती।

एआई और चिंतनशील बुद्धिमत्ता की समस्या

लॉरेंस इस अनुकूलनशीलता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अंतर्निहित सीमाओं के साथ तुलना करते हैं, विशेष रूप से बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) के संदर्भ में। मानव बुद्धिमत्ता, जो धीमी, विचारशील संचार और कथानिर्माण पर फलती-फूलती है, इसके विपरीत, एलएलएम बुनियादी रूप से संभाव्यत्मक भविष्यवाणी मशीनें हैं। वे मानव भाषा की नकल करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा संसाधित करते हैं, लेकिन उनमें अपनी सीमाओं की वास्तविक समझ या जागरूकता का अभाव होता है। लॉरेंस इसे 'महान एआई भ्रम' (The Great AI Fallacy) कहते हैं—यह गलत धारणा कि एआई सिस्टम ने मानव समझ के बराबर किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है।

लॉरेंस के अनुसार, यह भ्रम इस गलतफहमी पर आधारित है कि एआई वास्तव में क्या करता है। ये सिस्टम कारणात्मक तर्क (causal reasoning) में संलग्न नहीं होते हैं और न ही अपने परिणामों के अर्थ पर विचार करते हैं। इसके बजाय, वे डेटा के भीतर सांख्यिकीय संघों पर भरोसा करते हैं, ऐसी भविष्यवाणियाँ उत्पन्न करते हैं जो सटीक लग सकती हैं, लेकिन उनमें मानव तर्क की गहराई का अभाव होता है। कारणात्मकता पर विशेषज्ञ जुडिया पर्ल ने इस सीमा पर प्रकाश डाला है, यह बताते हुए कि मशीन लर्निंग मॉडल्स संभावना वितरणों का अनुमान लगाने में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन वे इन अनुमानों से आगे बढ़कर कारण-प्रभाव संबंधों को समझने में विफल होते हैं। दूसरे शब्दों में, एआई सिस्टम पैटर्न की पहचान में उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे उस वास्तविक बुद्धिमत्ता से बहुत दूर हैं जिसे मनुष्य समझते हैं।

परमाणु मानव और एआई का भविष्य

लॉरेंस के विचार में, एआई का भविष्य संभवतः मानव और मशीन बुद्धिमत्ता दोनों की ताकतों को जोड़ने वाले हाइब्रिड सिस्टम्स में निहित हो सकता है। वे 'मानव-समान मशीन' (Human-Analogue Machine, HAM) की कल्पना करते हैं, जो मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक विस्तार हो सकता है। ऐसा सिस्टम मानव बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं लेगा, बल्कि इसे बढ़ाएगा, जिससे

लोग जटिल, अनिश्चित वातावरण को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकेंगे। हालांकि, लॉरेंस इस बात पर जोर देते हैं कि एआई को मानव बुद्धिमत्ता के प्रतिस्थापन के रूप में देखने का प्रलोभन खतरनाक हो सकता है। वे तर्क देते हैं कि मानवता की अनूठी ताकत उसकी कमजोरियों में निहित है—हमारी अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने, संचार के माध्यम से विश्वास बनाने, और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की क्षमता।

यह चेतावनी तकनीकी इतिहास के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब लॉरेंस कंप्यूटिंग के विकास का पता लगाते हैं, प्रारंभिक साइबरनेटिक सिस्टम्स से लेकर आज के न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तक, वे इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि प्रत्येक तकनीकी सफलता मानव कौशल द्वारा प्रेरित रही है। फिर भी, इन प्रगतियों के बावजूद, मानवीय सार अपरिवर्तनीय बना हुआ है। मशीनें शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं, लेकिन वे उस तरह से अज्ञात के अनुकूल होने में असमर्थ हैं, जैसा कि मनुष्य कर सकते हैं। स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनिश्चितता जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है, और इससे निपटने की हमारी क्षमता औपचारिक विश्लेषण से कहीं अधिक पर

इस अर्थ में, 'एटॉमिक ह्यूमन' की अवधारणा हमें यह याद दिलाती है कि मानव बुद्धि को क्या अद्वितीय बनाता है। हमें मशीनों से अलग केवल संभावनाओं की गणना करने या डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं बनाती, बल्कि अनिश्चितता के बीच आत्मचिंतन, संचार और अनुकूलन की हमारी क्षमता ही हमें विशेष बनाती है।

निर्भर करती है।

अनिश्चितता को वश में करना: एक व्यापक दृष्टिकोण

स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस दोनों के विश्लेषणों के केंद्र में यह मान्यता है कि अनिश्चितता को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, इसे मानव अस्तित्व के एक मौलिक पहलू के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है कि एआई कभी सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त करेगा, क्योंकि यह उस अनुकूलनशीलता, विश्वास और आत्म-जागरूकता की नकल नहीं कर सकता जो मानवीय अनुभूति को परिभाषित करती है। जबकि एआई विशाल मात्रा में डेटा संसाधित कर सकता है और उस डेटा के आधार पर भविष्यवाणियाँ कर सकता है, इसमें अपनी सीमाओं पर विचार करने या ऐसे कथानक बनाने की क्षमता का अभाव है जो विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दे सके।

अनिश्चितता को अपनाना

स्पीगलहॉल्टर की The Art of Uncertainty और लॉरेंस की The Atomic Human दोनों पुस्तकों में मानव बुद्धिमत्ता की प्रकृति और अनिश्चितता के साथ इसके संबंधों पर मूल्यवान

अंतर्दृष्टि दी गई है। जहां एआई में तकनीकी प्रगति ने डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियाँ करने के लिए शक्तिशाली उपकरण बनाए हैं, वहीं ये सिस्टम मानव अनुभूति के विशिष्ट गुणों की नकल करने में असमर्थ हैं। जैसे-जैसे हम एक तेजी से अनिश्चित होती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, यह पहचानना आवश्यक है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति अनिश्चितता को समाप्त करने की क्षमता में नहीं, बल्कि अनजान चुनौतियों का सामना करने में, अनुकूलन, संचार, और विश्वास बनाने में निहित है।

डेटा या भ्रम? डेटा की सीमाएं, अनिश्चितता, और मानव निर्णय-निर्धारण

ऐसे युग में जहाँ डेटा को अक्सर निर्णय लेने के लिए अंतिम उपकरण के रूप में देखा जाता है, डेटा पर निर्भरता और इसके सीमाओं के बीच एक बढ़ता हुआ तनाव है। स्पीगलहॉल्टर और लॉरेंस, दोनों ही, इस बात की सराहना करते हैं कि कैसे मनुष्य डेटा को संसाधित कर सूचित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। फिर भी, वे स्वीकार करते हैं कि बिना संदर्भ के डेटा का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। असल मुद्दा इस बात में है कि हम डेटा की व्याख्या कैसे करते हैं और उसे क्या अर्थ देते हैं। संदर्भ की अनुपस्थिति और दुनिया की अंतर्निहित अनिश्चितताओं के कारण, डेटा-आधारित निर्णय विशेष रूप से अप्रत्याशित परिदृश्यों में गलत हो सकते हैं।

एआई और आपराधिक न्याय प्रणाली में पक्षपात

अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई के बढ़ते उपयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डेटा कैसे भ्रामक हो सकता है। एआई सिस्टम्स को आपराधिक सज़ाओं की अनुशंसा करने और पैरोल आवेदन मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सतही तौर पर, यह एक तार्किक प्रगति प्रतीत होती है—डेटा का उपयोग कर निष्पक्षता और संगति सुनिश्चित करने का प्रयास। लेकिन ये एआई सिस्टम्स उसी पूर्वाग्रह और पक्षपात को प्रतिबिंबित करते हैं जो उनके प्रशिक्षण डेटा में अंतर्निहित होते हैं। नतीजतन, असमानता को कम करने के बजाय, वे मौजूदा पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जनसांख्यिकीय समूहों में पूर्ववर्ती सज़ा के रुझान भविष्य में अनुचित सज़ाओं को कायम कर सकते हैं, जिससे सामाजिक असमानताएँ और बढ़ सकती हैं। जब तक इन पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक डेटा-चालित एआई सिस्टम्स मानव निर्णय लेने वालों की तरह ही त्रुटिपूर्ण रह सकते हैं।

मूल समस्या केवल तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक है—क्या हम उस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं जिसे हम उपयोग कर रहे हैं? यह प्रश्न हमें एक गहरी चुनौती की ओर ले जाता हैः ओन्टोलॉजिकल अनसर्टेंटी।

ओन्टोलॉजिकल अनसर्टेंटी की समस्या

स्पीगलहॉल्टर ओन्टोलॉजिकल अनसर्टेंटी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं—यह विचार कि हम हमेशा भविष्य की सभी संभावित स्थितियों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह अनिश्चितता केवल सांख्यिकीय नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति से जुड़ी है। मानव बुद्धिमत्ता लाखों वर्षों में विकसित हुई है, एक ऐसी दुनिया में जिसने हमेशा आश्चर्य, उथल-पुथल और अप्रत्याशित बदलाव देखे हैं। फिर भी, आज की डेटा-चालित समाज में, हम इस धारणा पर तेजी से भरोसा कर रहे हैं कि जिस प्रक्रिया ने वह डेटा उत्पन्न किया है, वह समय के साथ स्थिर रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? क्या हम डेटा पर भरोसा कर सकते हैं जब इसे उत्पन्न करने वाली स्थितियाँ अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं?

यह चिंता नई नहीं है। 2015 में प्रकाशित अपनी पुस्तक Post Keynesian Theory and Policy में अर्थशास्त्री पॉल डेविडसन ने मुख्यधारा की आर्थिक सोच में एक महत्वपूर्ण खामी की ओर इशारा कियाः यह विश्वास कि अतीत के डेटा का उपयोग भविष्य के बारे में सांख्यिकीय रूप से सही पूर्वानुमान बनाने के लिए किया जा सकता है। डेविडसन ने इस धारणा पर सवाल उठाया कि आर्थिक प्रणालियाँ स्थिर, एर्गोडिक प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं (यानी, ऐसी प्रक्रियाएँ जो समय के साथ स्थिर रहती हैं)। वास्तव में, अर्थव्यवस्था अधिक अराजक प्रणाली की तरह है, जहाँ भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी हमेशा पिछले डेटा के आधार पर नहीं की जा सकती।

ML

वित्तीय संकट और नियंत्रण का भ्रम

2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे अतीत के डेटा पर भरोसा सुरक्षा की झूठी भावना पैदा कर सकता है। संकट से पहले, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों का मानना था कि उन्होंने जोखिम प्रबंधन के लिए परिष्कृत मॉडल विकसित किए हैं। उन्होंने यह मान लिया था कि हेजिंग और पूंजी भंडार बढ़ाने जैसी रणनीतियों के माध्यम से अनिश्चितता को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, जब आवासीय बुलबुला फूटा और संकट प्रकट हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया कि ये मॉडल संकट की गंभीरता का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं थे। यह धारणा कि वित्तीय बाजार पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करते हैं, टूट गई। इसके जवाब में, नियामकों ने संकट से उजागर हुई कमियों को दूर करने के उपाय किए, लेकिन ये उपाय अतीत को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, भविष्य के संकटों को देखने के लिए नहीं।

स्पीगलहॉल्टर ने कहा, 'हमारी कल्पना दुनिया के साथ मिलकर काम करती है और उस दुनिया पर निर्भर करती है ताकि उसे वह निरंतरता प्रदान की जा सके जिसकी उसे आवश्यकता होती है।' लेकिन दुनिया स्थिर नहीं रहती—यह लगातार व्यवधानों, शासन परिवर्तनों और क्रांतियों से आकार लेती है। जैसा कि लॉरेंस इंगित करते हैं, इतिहास अप्रत्याशितता से भरा हुआ है, और यह अप्रत्याशितता डेटा-चालित निर्णय लेने की नींव को चुनौती देती है।

जोखिम, अनिश्चितता और अज्ञानता: ज़ेकहाउज़र का मॉडल

अर्थशास्त्री रिचर्ड ज़ेकहाउज़र ने दुनिया की स्थिति के बारे में विभिन्न ज्ञान स्तरों को समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जो विभिन्न निर्णय लेने के वातावरण से मेल खाती है। ज़ेकहाउज़र तीन क्षेत्रों के बीच अंतर करते हैं: जोखिम, अनिश्चितता, और अज्ञानता।

जोखिम की स्थिति में, संभावित परिणाम और उनकी संभावनाएँ ज्ञात होती हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ सांख्यिकीय मॉडल और डेटा सबसे प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो दो शेयरों के बीच चयन कर रहा है, वह ऐतिहासिक डेटा का उपयोग विभिन्न रिटर्न की संभावनाओं का आकलन करने के लिए कर सकता है।

अनिश्चितता की स्थिति में, संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं, लेकिन उनकी संभावनाएँ नहीं। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो एक नया उत्पाद लॉन्च कर रहा है, वह जानता है कि यह या तो सफल होगा या विफल, लेकिन प्रत्येक परिणाम की सटीक संभावना जानने का कोई तरीका नहीं है।

अंत में, अज्ञानता उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहाँ संभावित परिणाम भी अज्ञात होते हैं। यह सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निर्णय लेने वालों को सभी संभावित जोखिमों को जाने बिना ही चुनाव करना पड़ता है। अज्ञानता अक्सर नई प्रौद्योगिकियों या अभूतपूर्व घटनाओं से जुड़े परिदृश्यों में उत्पन्न होती है। इन मामलों में, निर्णय कठिन डेटा के बजाय अनुमान और अनुमान पर आधारित होते हैं।

ज़ेकहाउज़र का मॉडल डेटा-आधारित निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण सीमा को उजागर करता है। जबकि डेटा हमें जोखिम की स्थितियों को नेविगेट करने में मदद कर सकता है, यह अनिश्चितता और अज्ञानता की स्थितियों में कम उपयोगी होता है। ऐसे मामलों में, हमें निर्णय लेने के लिए विवेक, अंतर्ज्ञान और कल्पना पर निर्भर रहना पड़ता है—वे गुण जो एआई सिस्टम, अपनी सभी शक्तियों के बावजूद, अभी भी नहीं रखते।

अनिश्चितता की आत्म-सिद्ध प्रकृति

स्पीगलहॉल्टर इस बात को स्वीकार करते हैं कि कभी-कभी 'हम सभी संभावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते' और 'हमें यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि हम नहीं जानते।' यह स्वीकारोक्ति

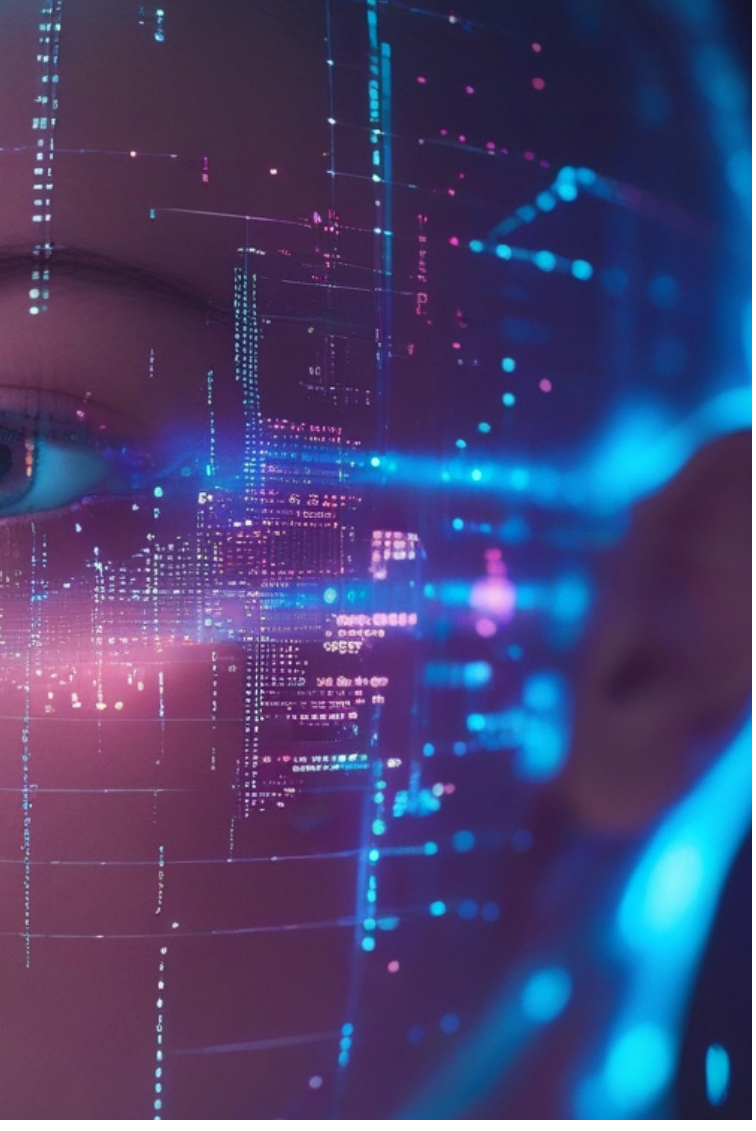

महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मान्यता देती है कि अनिश्चितता केवल एक बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि एक आत्म-सिद्ध (self-fulfilling) समस्या भी है। अपने प्रसिद्ध 'ब्यूटी कॉन्टेस्ट' रूपक में, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस बात का वर्णन किया कि भविष्य के बारे में लोगों की अपेक्षाएँ इस पर कैसे निर्भर करती हैं कि वे दूसरों को क्या करते हुए मानते हैं। ऐसी स्थितियों में, अनिश्चितता एक प्रतिक्रिया पाश (feedback loop) उत्पन्न कर सकती है, जहाँ हर कोई अन्य लोगों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे समूह व्यवहार (herding) और बाजार बुलबुले (market bubbles) बन सकते हैं।

यह गतिशील विशेष रूप से वित्तीय बाजारों में स्पष्ट होती है, जहाँ भविष्य की कीमतों के बारे में अनिश्चितता सट्टा बुलबुलों को जन्म दे सकती है। जब निवेशक किसी संपत्ति के वास्तविक मूल्य को लेकर अनिश्चित होते हैं, तो वे अपने निर्णयों को वस्तुनिष्ठ डेटा के बजाय इस पर आधारित कर सकते हैं कि वे सोचते हैं कि अन्य

यह सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निर्णय लेने वालों को सभी संभावित जोखिमों को जाने बिना ही चुनाव करना पड़ता है।

लोग क्या विश्वास करते हैं। जैसे-जैसे अधिक से अधिक निवेशक बाजार में आते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, यह धारणा मजबूत होती जाती है कि संपत्ति मूल्यवान है। लेकिन जब बुलबुला फूटता है, तो वही प्रतिक्रिया पाश कीमतों को नीचे ले जाता है, क्योंकि हर कोई बेचने की जल्दी में होता है।

निष्कर्ष: डेटा की सीमाएं और निर्णय में विवेक की आवश्यकता

अंत में, लॉरेंस और स्पीगलहॉल्टर का संदेश स्पष्ट है: डेटा एक मूल्यवान उपकरण है, लेकिन यह सबकुछ नहीं है। दुनिया बहुत जटिल, बहुत अनिश्चित, और बहुत अप्रत्याशित है जिसे केवल डेटा के माध्यम से पूरी तरह से कैप्चर किया जा सके। हमें अपने मॉडलों की सीमाओं को पहचानना चाहिए और अनिश्चितता के सामने विनम्र बने रहना चाहिए। जोखिम की स्थितियों में, डेटा हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अनिश्चितता और अज्ञानता की स्थितियों में, हमें मानव निर्णय, रचनात्मकता, और अनुकूलनशीलता पर निर्भर रहना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें डेटा-आधारित निर्णय लेने को छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत, डेटा हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, उनके माध्यम से नेविगेट करने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन हमें हमेशा इसकी सीमाओं से अवगत रहना चाहिए और इस प्रलोभन का विरोध करना चाहिए कि हम इस पर अत्यधिक निर्भर न हो जाएँ। जैसा कि स्पीगलहॉल्टर याद दिलाते हैं, 'कभी-कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि हम नहीं जानते।' ऐसे क्षणों में, यह हमारी मानव क्षमता—चिंतन, कल्पना और सहयोग—है जो हमें अनजान रास्तों पर मार्गदर्शन करेगी। •

यह लेख विलियम एच. जेनेवे के लेख 'इन एआई वी ट्रस्ट' से प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर आधारित है, जिसमें कुछ अतिरिक्त पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि इस विषय की और व्यापक समझ प्रदान की जा सके। पूरे सम्मान के साथ, हम इन अंतर्दृष्टियों का पुनः उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जेनेवे को एआई के मानव मूल्यों पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता है। हम उनकी इस चिंता को समझते हैं और इसे और विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। विलियम एच. जेनेवे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित सम्बद्ध प्रोफेसर हैं और डूइंग कैपिटलिज्म इन द इनोवेशन इकॉनमी (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018) के लेखक हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा बांध या चीन की परख?

त्सांगपो नदी पर मेगा बांध बनाने की योजनाएं वर्षों पहले छोटे-छोटे बांधों की श्रृंखला बनाने की संभावना में बदल गई थीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये कब— और क्या वास्तव में— निर्मित किए जाएंगे।

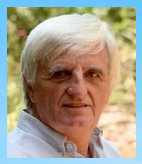

क्लॉड अर्पी

25 दिसंबर 2024 को, चीन की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने तिब्बत में यारलुंग त्संगपो नदी के निचले हिस्से में एक जलविद्युत परियोजना (एचपीपी) के निर्माण की बीजिंग द्वारा स्वीकृति की सूचना दी। यह वही नदी है जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जाना जाता है और दो अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संगम के बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।

तब से, भारतीय और वैश्विक मीडिया ने 'बांध' के मुद्दे पर सैकड़ों विशेषज्ञों के विश्लेषण प्रस्तुत किए, हालांकि चीनी रिपोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार का जलविद्युत संयंत्र (या संयंत्र) बनाया जाएगा या निर्माण कब शुरू होगा।

सामान्यतः यह माना गया है कि यह एक विशाल बांध होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा और 22,500 मेगावाट क्षमता वाले थ्री गॉर्जेज बांध की तुलना में तीन गुना अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेगा।

हालांकि, वर्षों से चीनी मीडिया के अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि एकल मेगा बांध के निर्माण की योजना इस घोषणा से काफी पहले ही छोड़ दी गई थी और इसके बजाय एक अधिक विस्तृत परियोजना का चयन किया गयाः दक्षिणी तिब्बत के नयिंगची सिटी में पाई टाउन के पास स्थित दूरस्थ स्थान डेयांग से अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमा के निकट तक एक श्रृंखला में छोटे जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण।

इस मेगा परियोजना को साकार करने के लिए कई कारक शामिल हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, यह एक राजनीतिक निर्णय होना

चाहिए, जिसमें पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही तिब्बत के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का भी आकलन किया जाना चाहिए।

यह संभव है, या यहां तक कि संभावना है कि 25 दिसंबर की शिन्हुआ की प्रेस विज्ञप्ति केवल भारत की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण गुब्बारा थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी शामिल थी। यही कारण हो सकता है कि उस वक्तव्य में अस्पष्टता थी।

अप्रैल 2004 में, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद अप्रत्याशित रूप से चीन के पश्चिमी हिस्से में नु (सलवीन) नदी पर एक विशाल बांध प्रणाली की योजना को निलंबित कर दिया था, जो देश के सबसे अछूते स्थलों में से एक को नष्ट कर सकती थी।

अखबार ने आगे कहाः 'मिस्टर वेन का हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि चीन के शीर्ष नेताओं ने उस योजना को मंजूरी नहीं दी थी जिसे अधिकांश बांध विरोधियों ने तयशुदा मान लिया था। उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप एक अलोकतांत्रिक सरकार में एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है, जिसने अतीत में प्रमुख सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में कम ही चिंता दिखाई थी।'

अपने लिखित निर्देश में, वेन ने अधिकारियों को कई जलविद्युत परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दियाः 'पर्यावरणविद तिब्बत में उत्पन्न होने वाली नु नदी को एशिया की अंतिम अछूती नदियों में से एक मानते हैं, जो युन्नान प्रांत से होते हुए 1,750 मील बहती है।'

लेकिन 2012 में, जब वेन अब सरकार की बागडोर में नहीं थे, परियोजनाओं को फिर से एजेंडे में शामिल कर लिया गया। रॉयटर्स ने बतायाः 'जैसे ही चीन के लोकलुभावन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ सेवानिवृत्त होते हैं और नई नेतृत्व टीम 2020 की महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दौड़ लगाती है, चीन में नए जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या बढ़ सकती है,' यह कहते हुए कि 'बांध निर्माण वेन के शासन में काफी धीमा हो गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से जलविद्युत परियोजनाओं को रोकने और स्थानीय जनसंख्या से विरोध की संभावना से बचने के लिए हस्तक्षेप किया था।'

यह स्पष्ट है कि यारलुंग त्संगपो पर जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण का निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया जाएगा, और जबकि वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर इन अस्थिर मेगा संरचनाओं के पक्ष में नहीं होता, बांध लॉबी (जो बड़े अनुबंधों से होने वाले वित्तीय लाभों से प्रेरित होती है) बीजिंग को 'निवेश' के लिए प्रेरित कर रही है।

संयोग से, जब राष्ट्रपति हू जिंताओ ने 2006 में दिल्ली का दौरा

यह परियोजना दशकों से योजना चरण में है। पहले ही नवंबर 2020 में, बीजिंग ने इस उद्देश्य से यारलुंग त्सांगपो के ग्रेट बेंड के सर्वेक्षण को चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) में शामिल कर लिया था।

किया, तो उन्होंने भारतीय सरकार को आश्वासन दिया कि 'बांध' का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, संयुक्त वक्तव्य के अनुसारः 'दोनों पक्षों के बीच सहमत सीमा-पार नदियों के संबंध में बाढ़ के मौसम के जलमापीय आंकड़ों के प्रावधान, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए एक विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाएगा।'

कुछ अन्य कारक भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मुख्य रूप से तकनीकी मुद्दे।

हालांकि यह सच है कि जलविद्युत विकास 'कई दशकों से गहन शोध के दौर से गुजर चुका है,' जैसा कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, फिर भी यह संदेह है कि नया विकास, यदि होता है, तो निचले इलाकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह परियोजना दशकों से योजना के तहत है। पहले ही नवंबर 2020 में, बीजिंग ने इस उद्देश्य के लिए चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) में यारलुंग त्संगपो के ग्रेट बेंड के सर्वेक्षण को शामिल कर लिया था।

चार साल पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि एकल बांध की योजना को छोड़ दिया गया था और इसके बजाय नौ या दस बड़े रिवर रन-ऑफ जलविद्युत संयंत्रों की श्रृंखला की योजना बनाई गई थी, जिनमें न्यूनतम जलाशय होंगे।

एक महत्वपूर्ण कारक जुलाई 2021 में पाई-मेटोक (पाई-मो) राजमार्ग का उद्घाटन था, जो नयिंगची को मेटोक से जोड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के उत्तर में स्थित है। राजमार्ग के पूरा होने के बाद, नयिंगची सिटी से मेटोक काउंटी तक की सड़क की लंबाई 346 किलोमीटर से घटकर 180 किलोमीटर हो गई और यात्रा का समय 11 घंटे से घटकर 4.5 घंटे हो गया।

रणनीतिक रूप से, 67 किलोमीटर का राजमार्ग और डोशुंग-ला पर्वत के नीचे एक सुरंग, खेल को बदलने वाला साबित हो सकता है। इससे निश्चित रूप से जलविद्युत परियोजनाओं के मार्ग को सुगम

बनाने में मदद मिलेगी।

एक अन्य प्रश्न यह है कि उत्पादित बिजली को मुख्य भूमि तक कैसे पहुंचाया जाएगा।

पीपल्स डेली के 26 जनवरी के लेख में आंशिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। यह हमें एक तकनीकी सफलता के बारे में जानकारी देता हैः 'चीन के 'पावर हाइवे' में से एक, 800 केवी अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (यूएचवीडीसी) ट्रांसमिशन परियोजना, जो जिन्शा (यांग्त्सी) नदी के ऊपरी हिस्सों से केंद्रीय चीन के हुबेई प्रांत तक बिजली पहुंचाती है, का कमीशन।'

कम्युनिस्ट समाचार पत्र बताते हैंः '1,901 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ, ट्रांसमिशन परियोजना उत्तर-पश्चिम चीन के शिजांग (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत, दक्षिण-पश्चिम चीन के चोंगकिंग नगर पालिका और हुबेई से होकर गुजरती है।'

कुछ ऐसा जो दशकों से एक मुद्दा बना हुआ था, उसे यांग्त्सी नदी पर हल कर लिया गया है। यारलुंग त्संगपो पर भी इसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

यारलुंग त्संगपो के ग्रेट बेंड और हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल (भूकंपीयता) इस क्षेत्र में किसी भी बड़े या विशाल परियोजना के लिए एक प्रमुख आपत्ति रही है। यह एक गंभीर समस्या है।

15 अगस्त 1950 को, असम-तिब्बत भूकंप आया था, जो आज के अरुणाचल प्रदेश के लोहित और अंजाव जिलों में हुआ था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.7 मापी गई थी। उस समय, 15 वर्षीय दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया थाः 'यह तोपों की बमबारी जैसा था—हमने यही मान लिया कि भूकंप और इस आवाज़ का कारण तिब्बती सेना द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के परीक्षण हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी, आसमान में एक अजीब सी लाल चमक

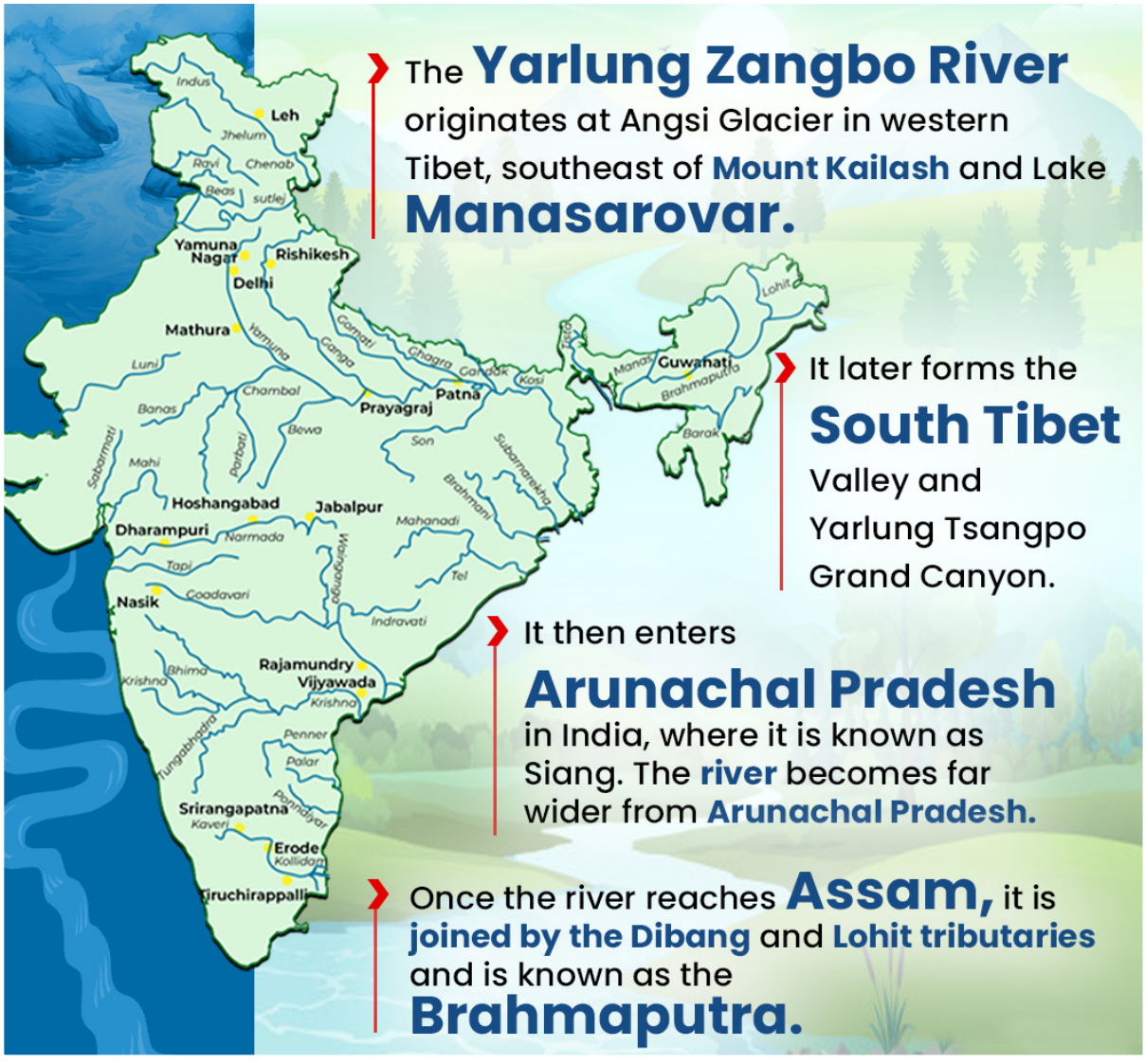

दिखाई दी।'

1950 का यह भूकंप ग्रेट बेंड (और अपर सियांग) के बहुत निकट हुआ था, जिसने उस क्षेत्र में नदियों के मार्ग को बदल दिया। ऐसे भूकंपों से एक के बाद एक बनने वाले जल विद्युत परियोजनाओं के समूहों के लिए वास्तविक खतरा है।

इन सभी कारकों को बीजिंग को ध्यान में रखना होगा, इससे पहले कि वह इस जोखिम भरी परियोजना को शुरू करने का निर्णय ले।

अंततः, क्या बीजिंग भारत के साथ जल युद्ध चाहता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल भविष्य ही दे सकता है। •

यह लेख सबसे पहले 'डाउन टू अर्थ' में प्रकाशित हुआ था। क्लॉड आर्पी, शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस, दिल्ली-एनसीआर के हिमालय अध्ययन केंद्र में एक प्रतिष्ठित साथी हैं। हम इसे उचित श्रेय के साथ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता एक गंभीर खतरा

बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, जिसके अंतर्निहित कारणों, संभावित परिणामों और भारत के लिए निहितार्थों की पड़ताल आवश्यक है। यह पड़ताल देश में बढ़ती कट्टरता, बांग्लादेश की सेना के विस्तार, आर्थिक संकट और बाहरी हस्तक्षेप के बढ़ते खतरे जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

संतु दास

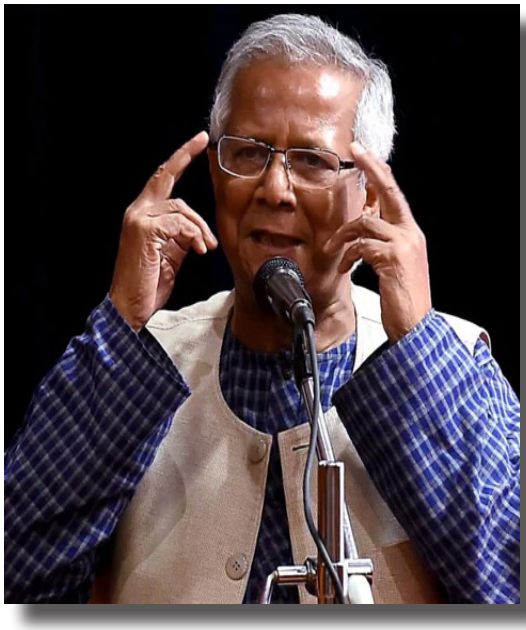

बांग्लादेश, अपनी संघर्षपूर्ण स्वतंत्रता और जटिल राजनीतिक इतिहास के साथ, वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश की राजनीतिक व्यवस्था, जो लंबे समय से अवामी लीग (AL) और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के बीच द्विदलीय प्रतिस्पर्धा से परिभाषित रही है, विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के अभिसरण से उत्पन्न गहरे संकट का सामना कर रही है। यह संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक चुनौतियों, कट्टरपंथीकरण के बढ़ते खतरे और बाहरी हस्तक्षेप की संभावना से उपजा है, जो न केवल बांग्लादेश की स्थिरता को खतरे में डालता है बल्कि भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी गंभीर सुरक्षा निहितार्थ रखता है।

बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, जिसके अंतर्निहित कारणों, संभावित परिणामों और भारत के लिए निहितार्थों की पड़ताल आवश्यक है। यह पड़ताल देश में बढ़ती कट्टरता, बांग्लादेश की सेना के विस्तार, आर्थिक संकट और बाहरी हस्तक्षेप के बढ़ते खतरे जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख दलों, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच गहन ध्रुवीकरण से त्रस्त है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और आर्थिक विकास पर जोर देती है। दूसरी ओर, खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेशी राष्ट्रवाद और इस्लामिक मूल्यों को बढ़ावा देती है और अक्सर अवामी लीग की नीतियों का विरोध करती है।

इन दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और संस्थानों के राजनीतिकरण का कारण रही है। हाल के वर्षों में, बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय की संभावना दिखाई दी है, जिसके समर्थन में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि यूनुस ने अमेरिका के पिछले प्रशासन से वादा किया था कि वह एक नई पार्टी का गठन करेंगे जो अमेरिका के प्रति वफादार रहेगी। हालांकि, यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है और आलोचकों का मानना है कि यह बांग्लादेश की राजनीतिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञता और बाहरी समर्थन पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जो देश की धर्मनिरपेक्ष नींव के लिए एक गंभीर खतरा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ इन तत्वों के संपर्क लगातार बने हुए हैं, और वे चुपचाप हथियार मंगवा रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

चिटगांव हिल ट्रैक्स जैसे क्षेत्रों में हिंसा बढ़ी है, जो जातीय और

धार्मिक तनाव से ग्रस्त है। यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश की सेना भी कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिलकर काम कर सकती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। कट्टरपंथी समूहों का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की सीमा पर अशांति फैलाना और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना है।

बांग्लादेश इस समय अपनी सैन्य क्षमता का भी विस्तार कर रहा है। यह सवाल उठता है कि बांग्लादेश को सैन्य शक्ति बढ़ाने की जरूरत क्यों है? बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसकी म्यांमार या किसी अन्य देश से युद्ध की संभावना है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश अपनी सीमा पर भारत से किसी संभावित कार्रवाई का डर महसूस कर रहा है। इस डर के चलते बांग्लादेश ने ड्रोन, टैंक्स और असॉल्ट वेपंस जैसी चीजों की मांग की है।

सेना के विस्तार का एक और संभावित कारण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना हो सकता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, सरकार को सेना को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। वैश्विक आर्थिक संकट, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और भ्रष्टाचार के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव है। इसके साथ ही, शेख हसीना की सरकार भी अब दबाव में है। बांग्लादेश की राजनीति में आवामी लीग और BNP दोनों ही दलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूनुस और उनके समर्थक स्टूडेंट लीडर्स इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं।

आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश में सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण लोग सरकार से निराश हैं। इसके चलते बांग्लादेश में धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे वहां की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

बांग्लादेश की यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के बांग्लादेश में अपनी-अपनी भूमिका निभाने के संकेत मिल रहे हैं। खासकर पाकिस्तान की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान, जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है, बांग्लादेश में भी यही रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्रभाव बढ़ने से भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा।

चीन भी बांग्लादेश में अपनी आर्थिक और राजनीतिक उपस्थिति

बढ़ा रहा है। चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है और बांग्लादेश की सेना को हथियार बेच रहा है। अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का दावा करता है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में चीन के प्रभाव को कम करना है।

भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा है, और बांग्लादेश में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ता है। बांग्लादेश में जब भी कोई बड़ा संकट आता है, तो लोग भारत की सीमा की ओर पलायन करने लगते हैं। पहले भी भारत में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का पलायन हो चुका है, जिनकी संख्या अब करीब 2 करोड़ हो गई है। इससे भारत को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासन स्थापित होने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थियों का बड़ा influx हो सकता है, जो वहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा, बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ने से भारत में आतंकवादी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखे। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव और बढ़ता है, तो भारत को अपनी सीमा की सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी। यही कारण है कि अजीत डोभाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी बांग्लादेश सीमा पर दौरे कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की स्थिति का आकलन करना और भारतीय सुरक्षा बलों को संभावित खतरों के लिए तैयार करना है।

भारत के लिए यह भी जरूरी है कि वह बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति में सीधे हस्तक्षेप न करे, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो भारत को अपनी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके साथ ही, बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

यह आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थक एक नए तालिबान की तरह शासन प्रणाली स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में यूनुस ने एक रेडिकलाइज्ड मॉब और जेल से रिहा किया है और इन कट्टरपंथियों को प्रस्तावित नई पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके मोबोकरेसी (जनता के नाम पर हिंसक शासन) की स्थापना करना।

यह कहा जा रहा है कि यूनुस एक ऐसे सिस्टम की स्थापना करना चाहते हैं जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खुनैवी की तरह वह खुद शासन करेंगे और उनके नीचे कुछ खास छात्र प्रोटेस्टर्स होंगे, जो मंत्रियों और प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही उनके समर्थक रेडिकलाइज्ड मॉब का गठन करेंगे, जो देश में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए तैयार रहेंगे। यह पूरी योजना लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने और शक्ति के माध्यम से शासन करने की ओर इशारा करती है।

यह भी आरोप है कि यूनुस के विरोधियों को हिंसा के जरिए चुप कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, घरों में आगजनी की जा रही है, और राजनैतिक नेताओं को देश से बाहर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि यूनुस की योजना एक 'नया अफगानिस्तान' और 'नया तालिबान' बनाने की है। तालिबान की तरह ही ये लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर एक रेडिकल शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं।

बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है और इसके भारत पर भी गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों का बढ़ता प्रभाव, पाकिस्तानी हस्तक्षेप और आर्थिक संकट ने वहां की राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर दिया है। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा, और इस पूरे परिदृश्य पर करीबी नजर बनाए रखनी होगी।

यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में मौजूदा समय में गंभीर संकट पैदा हो रहा है, जिसमें रेडिकलाइज्ड समूह लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने और सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, यह स्थिति भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है, जिससे शरणार्थी संकट और सीमाओं पर अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है।

भारत को बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही, भारत को बांग्लादेश के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। अंत में, भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए ताकि बांग्लादेश में अस्थिरता का भारत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। बांग्लादेश की स्थिति जटिल और बहुआयामी है, और भारत को एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि अपने हितों की रक्षा करते हुए बांग्लादेश की स्थिरता में योगदान किया जा सके। •

छिपी दरार नए मध्य पूर्व का खुलासा

गाज़ा, सीरिया और क्षेत्र का अगला संकट

महा याह्या

पिछले 15 वर्षों में मध्य पूर्व युद्ध, विनाश और विस्थापन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गाजा, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया और यमन में जारी संघर्षों के कारण लाखों लोगों की जान गई है और करोड़ों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस हिंसा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में हुई प्रगति को पीछे धकेल दिया है और घरों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, रेलवे लाइनों और बिजली के ढांचों को तबाह कर दिया है। गाजा में युद्ध ने खास तौर पर क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को 1955 के स्तर पर ला खड़ा किया है।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संगठनों ने अनुमान लगाया है कि मध्य पूर्व के पुनर्निर्माण और पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान करने के

लिए $350 से $650 अरब तक की आवश्यकता होगी। अकेले गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $40 से $50 अरब की जरूरत है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आकलन किया है।

इन बर्बाद समाजों को मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करना लाखों लोगों के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर निकट भविष्य में। लेकिन यह चिंता की बात है कि कई पश्चिमी सरकारें, जिनमें वाशिंगटन भी शामिल है, विदेशों में दी जा रही सहायता और मानवीय सहायता को सीमित कर रही हैं। हालांकि, अंततः अरब जगत के पुनर्निर्माण में मुख्य बाधा धन की कमी नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक विवाद और मतभेद होंगे। यह क्षेत्र असफल राष्ट्रों से भरा हुआ है, जहां अलग-अलग शक्तियां इस अराजकता का अपने भू-राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रही हैं। इन समस्याओं के कारण स्थायी शांति असंभव प्रतीत होती है।

क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां इस तथ्य को जानती हैं। ईरान, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अरब खाड़ी के देशों ने दशकों तक इस क्षेत्र को अपने तरीके से ढालने का प्रयास किया है, लेकिन संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित किए बिना, वे बार-बार विफल हुए हैं। उन्होंने शांति के बजाय सुरक्षा की खोज की, लेकिन अंततः न तो शांति मिली और न सुरक्षा। इसके बावजूद, उनकी वर्तमान योजनाएं अतीत के प्रयासों से बहुत मिलती-जुलती हैं। इन देशों ने फिर से नए क्षेत्रीय आदेश के विज़न को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें बिना किसी राजनीतिक समझौते के पुनर्निर्माण हो। उन्होंने इजरायल-सऊदी संबंधों की सामान्यीकरण, ईरान और खाड़ी राज्यों के बीच एक आर्थिक समझौते जैसे ऊंचे प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन राजनीतिक वास्तविकताओं, स्थानीय परिस्थितियों या व्यापक परिणामों पर विचार किए बिना। परिणामस्वरूप, उनकी योजनाएं चक्रीय हिंसा को समाप्त नहीं करेंगी, बल्कि इसे और बढ़ावा देंगी।

स्थिरता प्राप्त करने के लिए युद्धग्रस्त मध्य पूर्व को अपनी दिशा बदलनी होगी। इसकी शक्तियों को क्षेत्रीय और स्थानीय विभाजनों को कागजी कार्रवाई से छिपाने के बजाय उन्हें संबोधित करने की कठिनाई से गुजरना होगा। उन्हें बिखरे हुए समाजों को एक साथ लाने में मदद करनी

होगी, जवाबदेह राजनीतिक संस्थाएं बनानी होंगी और संक्रमणकालीन न्याय की प्रणालियों को प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें ऐसे पुनर्निर्माण का समर्थन करना होगा जो व्यापक शांति निर्माण एजेंडे का हिस्सा हो। और उन्हें फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने वाले राजनीतिक ढांचे का निर्माण करना होगा। उन्हें अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने या कम से कम बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का तरीका भी खोजना होगा। अन्यथा, यह मायने नहीं

और समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर सहायता पैकेज पारित करना शुरू किया, जिसमें क्षेत्र पर $13.3 अरब (आज के डॉलर में $170 अरब से अधिक) खर्च किए गए। लेकिन यह धन शर्तों के साथ आया था। प्राप्तकर्ताओं को अन्य यूरोपीय राज्यों के साथ व्यापार की अधिकांश बाधाओं को हटाना पड़ा। उन्हें ऐसी नीतियां अपनानी पड़ीं, जो उनके निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका तक बढ़ा सकें और अधिक अमेरिकी वस्तुओं को अपने बाजार में लाने की

रखेगा कि दुनिया पुनर्निर्माण पर कितना खर्च करती है; यह क्षेत्र टूटा हुआ ही बना रहेगा।

1945 में, यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। छह वर्षों के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए थे। महाद्वीप के कई समृद्ध शहर बमों और गोलाबारी से नष्ट हो गए थे। क्षेत्रीय मुद्राएं ध्वस्त हो गई थीं, जिससे लोग भीख मांगने और वस्तु-विनिमय के लिए मजबूर हो गए थे।

इसके जवाब में, ट्रूमैन प्रशासन ने महाद्वीप के पुनर्निर्माण के लिए वाशिंगटन से खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल की सलाह पर, कांग्रेस ने यूरोप के लोगों अनुमति दे सकें। उद्देश्य केवल यूरोप के घरों, सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि महाद्वीप को उभरते हुए अमेरिकी-नेतृत्व वाले उदार आदेश में लाना था।

यह रणनीति सफल रही। मार्शल योजना के प्राप्तकर्ताओं ने अमेरिकी-नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में शामिल होकर सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत किया, जिससे यूरोपीय संघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन निर्णयों की बदौलत, यूरोप न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश से आर्थिक रूप से उभरा, बल्कि सदियों के संघर्ष के बाद, वह दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया।

आज के मध्य पूर्व में तबाही का पैमाना 1945 के यूरोप जैसा ही है। मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला है, हालांकि उतना ज्यादा नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्थाएं मिट चुकी हैं। राष्ट्रीय मुद्राएं अपने अधिकांश मूल्य खो चुकी हैं: यमनी रियाल ने 2014 से 80 प्रतिशत तक अपनी कीमत गंवाई है। क्षति सबसे अधिक गाजा में देखी जा सकती है, जहां जनवरी के अंत तक आधिकारिक मौत का आंकड़ा 47,000 से अधिक है—संभवतः यह संख्या कम आंकी गई है—और जहां इजरायली बमबारी ने एक साल में लगभग 70 प्रतिशत इमारतों को मलबे में बदल दिया। (संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि मलबा हटाने में एक दशक से अधिक का समय लगेगा।) लेकिन अन्य देशों ने भी समान नुकसान झेले हैं। 14 साल से जारी सीरियाई गृहयुद्ध ने 1.2 करोड़ लोगों को विस्थापित किया और 6 लाख से अधिक लोगों की जान ली; अब देश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यमन में, आधी से अधिक आबादी अब गरीबी से जूझ रही है। वहां लगभग 2 करोड़ लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है। आर्थिक कुप्रबंधन और शोषणकारी नीतियों ने मिस्र, इराक और लेबनान जैसे देशों में आर्थिक गिरावट को और बढ़ा दिया है।

मध्य पूर्व को एक मार्शल योजना की आवश्यकता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप के विपरीत, कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र के लिए कोई एकल समर्थक नहीं है, और इसे संकट से बाहर निकालने के तरीके पर कोई सहमति भी नहीं है। इसके विपरीत, मध्य पूर्व असहमति और प्रतिद्वंद्विता से ग्रस्त है। विभिन्न अमेरिकी, ईरानी, इजरायली, तुर्की और खाड़ी देशों के प्रस्तावों में एकमात्र सामान्य बात यह है कि वे मूलभूत चुनौतियों की उपेक्षा करते हैं।

पहले अमेरिकी दृष्टिकोण पर विचार करें। वाशिंगटन का मानना है कि एक बेहतर मध्य पूर्व की नींव में ईरान, उसके प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी, को कमजोर करना और इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना शामिल है, जिससे नए निवेशों का रास्ता खुलेगा। वाशिंगटन गाजा के पुनर्निर्माण में योगदान देना चाहता है, हालांकि उसका मानना है कि अधिकांश धन अरब देशों से आना चाहिए। लेकिन अमेरिकी योजना फिलिस्तीनियों के लिए किसी राजनीतिक समाधान के बिना पुनर्निर्माण की बात करती है।

इजरायलियों के बीच यह कल्पना साझा की जाती है। लेकिन उनमें से कुछ तेहरान और फिलिस्तीनियों के मामले में और भी अधिक आक्रामक होना चाहते हैं। इजरायली गाजा में युद्ध का बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहे हैं, और जनवरी में युद्धविराम के बाद भी कई लोग फिर से बमबारी करना चाहते हैं। इजरायली नेताओं की आक्रामकता को ईरान और हिज़्बुल्लाह—लेबनान की मिलिशिया जिसे तेहरान समर्थन देता है—को कमजोर करने में मिली सफलता से और बढ़ावा मिला है। इजरायल गाजा का पुनर्निर्माण तभी करना

वाशिंगटन का मानना है कि एक बेहतर मध्य पूर्व की नींव में ईरान, उसके प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी, को कमजोर करना और इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना शामिल है, जिससे नए निवेशों का रास्ता खुलेगा।

चाहता है जब फिलिस्तीनी, पूर्व इजरायली सुरक्षा अधिकारियों एमोस यादलिन और अवनेर गोलोव के शब्दों में, 'कट्टरपंथ से मुक्त' हो जाएं और यह साबित कर दें कि वे 'प्रभावी शासन' चलाने में सक्षम हैं। कुछ इजरायली अधिकारी तो गाजा का पुनर्निर्माण बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं।

इजरायली दृष्टिकोण नैतिक रूप से गलत है: फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का स्पष्ट अधिकार है। यह व्यावहारिक भी नहीं है। चाहे इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका कितना भी प्रयास कर लें, वे फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज करके शांति नहीं ला सकते। वास्तव में, ऐसा करने का प्रयास ही उन्हें यहां ले आया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहरीन, मोरक्को, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात को अब्राहम समझौतों के हिस्से के रूप में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए राजी किया, जिससे ट्रंप को उम्मीद थी कि यह एक इजरायल-नेतृत्व वाली सुरक्षा, व्यापार और निवेश समझौता बनेगा। इस बीच, इजरायल ने बस्तियों के निर्माण में तेजी लाई, दमन बढ़ाया और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाया। इसके जवाब में, हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को अपने भयावह हमले को अंजाम दिया। हमले की व्याख्या करते हुए हमास नेता इस्माइल हनियेह ने कहा, 'सभी सामान्यीकरण और मान्यता प्रक्रियाएँ, सभी समझौते जो (इजरायल के साथ) हस्ताक्षरित हुए हैं, कभी भी इस लड़ाई को समाप्त नहीं कर सकते।'

इस हमले ने इजरायल की तीव्र प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, जिससे इजरायल-सऊदी समझौते की प्रगति रुक गई और ईरान और उसके गैर-राज्य भागीदारों ने संघर्ष में कूदने का अवसर लिया। इजरायल ने इस 'प्रतिरोध की धुरी' को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने से रोका, और इजरायल रक्षा बलों ने खुद ईरान को कमजोर कर दिया। लेकिन इस्लामिक गणराज्य ने अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए शांति प्रस्ताव के साथ जवाब दिया, जिसमें अपने अरब पड़ोसियों के साथ गैर-आक्रामकता और आर्थिक समझौते की पेशकश की गई, जिसका उद्देश्य आंशिक रूप से इजरायल को अलग-थलग करना था।

यह सच है कि अरब जगत के कई लोग इस्लामिक गणराज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं जिससे उन्हें निपटना है। और गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन में इजरायली बमबारी अभियानों के बाद, अब क्षेत्र के लोग इजरायल को मध्य पूर्व का सबसे कट्टरपंथी और विनाशकारी अभिनेता मानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान की दृष्टि कोई अधिक यथार्थवादी है। यह क्षेत्र में ईरान के विघटनकारी व्यवहार को नज़रअंदाज़ करता है, जिसमें हिंसक गैर-राज्य अभिनेताओं को समर्थन देना और resulting राज्य विफलता शामिल है। ईरान की योजना फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देती है। लेकिन अरब देश क्षेत्रीय अराजकता का अंत चाहते हैं, न कि केवल इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का अंत।

फिर अरब खाड़ी राज्यों—बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात—द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण है, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टिकोण शायद सबसे प्रेरणादायक है। परिषद के प्रस्तावों में खाड़ी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को गहरा करना, संयुक्त रक्षा तंत्र की स्थापना करना और फिर किसी तरह इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को अब लगभग असंभव दो-राज्य समाधान के माध्यम से हल करना शामिल है। प्रस्ताव, ईरानी प्रस्ताव की तरह, कम से कम इस बात को स्वीकार करता है कि उस संघर्ष का अंत क्षेत्रीय सुरक्षा प्राप्त करने की कुंजी है। लेकिन यह किसी समझौते तक पहुंचने का कोई ठोस तंत्र नहीं बताता है। खाड़ी राज्यों की योजना क्षेत्र के अन्य संघर्षों या उनका समाधान कैसे किया जाए, इसके बारे में भी बहुत कम कहती है।

सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, ये विभिन्न दृष्टिकोण बहुत कम हासिल करेंगे। और सबसे खराब स्थिति में, वे अब्राहम समझौतों की तरह और अधिक संघर्ष उत्पन्न करेंगे। उन्होंने सुरक्षा पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित किया है कि उन्होंने शांति को आर्थिक विकास और बल का विषय बना दिया है। ऐसा लगता है कि मध्य पूर्व की शक्तियाँ मानती हैं कि युद्धग्रस्त लोग नए निर्माण से संतुष्ट हो जाएंगे—न्याय, जवाबदेही या अच्छे नेतृत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें हिंसा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता हैः उदाहरण के लिए, इजरायल, समान अधिकारों की मांग करने वाले फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर सकता है और मार सकता है। इस तरह की धारणाएं खतरनाक और गलत दोनों हैं।

क्षेत्र की समस्याओं के मूल में शासन के सवाल हैं। कई देश बिखर गए हैं या ढह गए हैं, जिनमें अक्सर विशेष जातीय या राजनीतिक समूहों द्वारा प्रमुखता वाले शक्ति के प्रतिस्पर्धी केंद्र हैं। यह गतिशीलता कहीं और अधिक स्पष्ट नहीं है जितनी सीरिया में है, जहाँ वर्षों के युद्ध ने देश के केंद्र और उसके परिधि के बीच

संबंधों को कमजोर कर दिया है और स्थानीय शासकों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। कुछ स्थानों पर कुर्दों का नियंत्रण है। असद ने जिन स्थानों पर उच्चतम समर्थन स्तर बनाए रखा था वे उनके अलावी समुदाय द्वारा बसे हुए थे। दक्षिण पर तथाकथित दक्षिणी संचालन कक्ष का नियंत्रण है, जो विद्रोही गुटों का एक गठबंधन है जो 2011 में उभरा और अन्य समूहों की तुलना में कम इस्लामी रुझान रखता है। जिसने अंततः असद को सत्ता से बाहर कर दिया, वह हयात तहरीर अल-शाम था, जो सुन्नी पूर्व जिहादियों का समूह है जिसमें गैर-सीरियाई लड़ाके भी शामिल हैं। उनका दावा है कि वे अन्य समूहों के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब से उन्होंने दमिश्क पर कब्जा किया, देश में बदले की हत्याओं और भीड़ हिंसा में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से अलावियों को लक्षित कर रही है। एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया के बिना, सीरिया विभाजन से त्रस्त रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप ने इन विभाजनों को सख्त कर दिया है, और आगे भी सख्त करता रहेगा। मध्य पूर्व की प्रमुख शक्तियाँ लगातार अधिक क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं, इसलिए जब

युद्ध होते हैं, तो वे शक्तियाँ अक्सर अलग-अलग समूहों का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, सीरिया में, तुर्की उत्तर में HTS और अन्य गुटों का समर्थन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कुर्दों की मदद कर रहा है। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात का सीरिया के दक्षिणी संचालन कक्ष पर काफी प्रभाव है। इजरायल अपने ड्रूज समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस शक्ति शून्य का उपयोग कर लगभग 155 वर्ग मील सीरियाई भूमि पर कब्जा कर लिया है।

अभी के लिए, सीरिया के गुट शांति बनाए हुए हैं। वास्तव में, 29 जनवरी की एक बैठक में, असद को सत्ता से हटाने में शामिल प्रमुख समूहों ने HTS नेता अहमद अल-शरा को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त करने के लिए एक साथ आए। लेकिन अहमद अल-अवदा, जो दक्षिणी संचालन कक्ष में प्रमुख व्यक्ति हैं, ने इस बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजा था, परंतु अवदा स्वयं शामिल नहीं हुए। कुर्द और ड्रूज गुटों ने पूरी तरह से इसका बहिष्कार किया। साझा दुश्मन के चले जाने के बाद, सीरियाई मिलिशिया एक-दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो सीरिया का भविष्य सोमालिया के

नगण्य शक्तियां उठती हैं, शासक उठते हैं, और फिर, कुछ वर्षों बाद, मिलिशिया सत्ता संभाल लेते हैं। इस तरह की लंबी अवधि की अराजकता की संभावना में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम है।

वर्तमान जैसा दिख सकता है, जिसमें विभिन्न गुट विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित कर रहे हैं। या यह पास के लीबिया जैसा दिख सकता है। सीरिया और लीबिया बहुत अलग देश हैं, लेकिन लीबिया ने भी एक अरब वसंत क्रांति का अनुभव किया जिसने कई सशस्त्र समूहों को एक लंबे समय के तानाशाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। इन समूहों ने 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंका, और फिर देश को साझा करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय मिलिशिया ने देश का लगभग पूरा नियंत्रण संभाल लिया। उनका संघर्ष आज भी जारी है।

मध्य पूर्व की ऐसी ही कहानी हैः नगण्य शक्तियां उठती हैं, शासक उठते हैं, और फिर, कुछ वर्षों बाद, मिलिशिया सत्ता संभाल लेते हैं। इस तरह की लंबी अवधि की अराजकता की संभावना में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम है। बल्कि, ये देश तेल व्यापार से अपना मुनाफा निकालते रहेंगे, खासकर अब जबकि गैस की कीमतें बढ़ गई हैं।

द्वंद्वग्रस्त संस्थानों को फिर से खड़ा करने के प्रयास कारगर नहीं होते। यमन में दस वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे गृह युद्ध के बाद, यह देश लीबिया की तरह ही राजनीतिक रूप से दो प्रतिद्वंद्वी ताकतों के बीच बंटा हुआ हैः उत्तर में हूती विद्रोही और राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद। हूती विद्रोही देश के एक तिहाई भू-भाग और दो तिहाई जनसंख्या पर नियंत्रण रखते हैं। बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने यहां भी संघर्ष को और बढ़ाया है। ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद को शरण दे रहा है। परंतु, स्वयं राष्ट्रपति परिषद में भी गुटबाजी है और बाहरी प्रतिस्पर्धा से यह विभाजन और गहरा हो रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक ऐसे गुट का समर्थन करता है जो यमन का दक्षिणी भाग अलग करने की वकालत करता है। हद्रमौत प्रांत को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव ने यहां और दरार पैदा कर दी है, जहां सऊदी अरब प्रांत के भीतरी हिस्सों पर और यूएई तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। इन दोनों शक्तियों से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष हो चुका है, और आगामी महीनों

में यह और उग्र हो सकता है। इस अराजकता ने अल-कायदा इन अरब प्रायद्वीप और अन्य आतंकवादी संगठनों को यमन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का मौका दिया है।

मध्य पूर्व में बाहरी हस्तक्षेप ने शांति की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। हालांकि, इस बाहरी हस्तक्षेप में एक सकारात्मक पक्ष भी है। चूंकि ये लड़ाके बाहरी समर्थकों पर निर्भर हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय ताकतें सुलह के प्रयास कर सकती हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच 2023 में हुए सामान्यीकरण समझौते जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच नजदीकियां संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन मध्यस्थता को प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों को पहले अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना होगा। सऊदी अरब और यूएई के बीच राजनीतिक और आर्थिक हब बनने की होड़ में बढ़ता तनाव एक प्रमुख बिंदु है, खासकर सूडान, सीरिया और यमन के संघर्षों में। कतर और तुर्की द्वारा इस्लामी संगठनों को समर्थन देने से मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के साथ विवाद उत्पन्न हो रहा है। और हालांकि ईरान-सऊदी समझौते ने सांप्रदायिक विभाजन को थोड़ा कम किया है, परंतु यह ईरान के दमनकारी गैर-राज्य संगठनों के समर्थन को रोक नहीं सका है, जिससे क्षेत्रीय शांति स्थापित करना मुश्किल बना हुआ है।

यह मान भी लें कि ये देश आपसी प्रतिद्वंद्विताओं को पूरी तरह समाप्त कर लें, फिर भी वे शांति की गारंटी नहीं दे सकते। उन्हें स्थानीय शक्तियों से निपटने की जरूरत होगी ताकि वे ऐसी संधियों को लागू कर सकें जो राज्यों का पुनर्निर्माण करें, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और टूटे हुए सामाजिक ताने-बाने को फिर से जोड़ें। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध की विभीषिका झेल चुके ये स्थानीय शक्तियां इस दिशा में सहयोग करेंगी। संक्रमणकालीन न्याय का मुद्दा भी बेहद पेचीदा साबित हो सकता है। युद्ध के बाद, समाजों को ठीक करने के लिए कुछ हद तक क्षमा की आवश्यकता होती है। लेकिन उन लोगों के लिए व्यापक माफी नहीं हो सकती, जिन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। अपने गृह युद्ध के अंत में, लेबनान ने 15 वर्षों के संघर्ष के दौरान किए गए सभी अपराधों के लिए एक समग्र क्षमा जारी की थी। इसका उद्देश्य तेजी से शांति स्थापित करना और देश का पुनर्निर्माण करना था। लेकिन इसने पुराने नेताओं को भी अभियोजन से बचा

लिया। परिणामस्वरूप, लेबनान ने समय-समय पर गृह अशांति का सामना किया है क्योंकि युद्ध के दौरान उत्पन्न असंतोष कभी समाप्त नहीं हुआ। सीरिया के नए नेताओं को 54 वर्षों के तानाशाही शासन के दौरान असद के प्रमुख अधिकारियों को उनके अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, यह व्यक्तिगत बदले की भावना को बढ़ावा देगा और एक स्थायी शांति की स्थापना को कठिन बना देगा।

मध्य पूर्व में संघर्षों को समाप्त करने और खोई हुई चीजों के पुनर्निर्माण के लिए एक सर्व-समाधान नहीं हो सकता। इन संघर्षों की कुछ समान विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन कई वर्षों से चले आ रहे ये संघर्ष अपने विशिष्ट स्वरूप में विकसित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, लेबनान में चुनौती केवल इजराइल के साथ संघर्ष से हुए विनाश के पुनर्निर्माण की नहीं है। यह एक टूटे हुए राजनीतिक तंत्र को फिर से खड़ा करने, हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने और कमजोर राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने की भी है। सीरिया, जो पूरी तरह से युद्ध में तबाह हो चुका है, एक नए राजनीतिक समझौते की आवश्यकता है। लेकिन सीरिया को सत्ता का केंद्रीकरण फिर से नहीं करना चाहिए, जैसा कि असद युग के दौरान हुआ था। जो भी समाधान निकले, उसे पूरे देश का समर्थन मिलना चाहिए और उसे युद्ध के दौरान उभरे स्थानीय ताने-बाने का ध्यान रखना होगा।

गाजा के मामले में चुनौतियां और भी गहरी हैं। हो सकता है कि गाजा की तबाही के पैमाने और दायरे के लिए कोई ऐतिहासिक मिसाल हो, लेकिन गाजा एक देश नहीं है। इसके पास अपनी सीमाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह बाहरी बाजारों से कटा हुआ है और जल, भोजन और कृषि या औद्योगिक उत्पादन के लिए भूमि जैसी बुनियादी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में इसे रहने लायक बनाना, या आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना बेहद कठिन है। इसके पुनर्निर्माण और फिर इसे कौन शासन करेगा, इस पर भी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। निकट भविष्य में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित एक संक्रमणकालीन प्राधिकरण गाजा का प्रशासन संभाल सकता है, जैसा कि 1990 के दशक में बाल्कन

मध्य पूर्व में संघर्षों को समाप्त करने और खोई हुई चीजों के पुनर्निर्माण के लिए एक सर्व-समाधान नहीं हो सकता। इन संघर्षों की कुछ समान विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन कई वर्षों से चले आ रहे ये संघर्ष अपने विशिष्ट स्वरूप में विकसित हो चुके हैं।

और कंबोडिया के कुछ हिस्सों को फिर से बनाने में किया गया था। अंततः इसे ऐसे फिलिस्तीनियों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जिन्हें लोकतांत्रिक समर्थन प्राप्त हो। लेकिन फिलहाल, न तो कोई अल्पकालिक समाधान है और न ही कोई दीर्घकालिक योजना।

राजनीतिक संधियों के बिना, पुनर्निर्माण के लिए धन वितरण भी कठिन हो जाएगा। वास्तव में, सहायता की व्यवस्था तनाव पैदा कर सकती है। घरेलू और क्षेत्रीय शक्तियां अक्सर सहायता वितरण में हेरफेर करती हैं, जिससे एक असमान अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है, जो कुछ लोगों को नाराज करती है और दूसरों को सशक्त बनाती है। राजनीतिक समूह भी सरकारों के खर्च पर स्वयं को मजबूत करने के लिए सहायता का उपयोग कर सकते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, इसका मतलब यह नहीं है कि मानवीय सहायता समूहों को मध्य पूर्व के बर्बाद हुए इलाकों, विशेष रूप से गाजा, में सहायता के साथ नहीं पहुंचना चाहिए। इस क्षेत्र में लाखों लोग बेघर हैं। लाखों लोग भुखमरी और चिकित्सा देखभाल की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके, हर संभव सहायता की आवश्यकता है।

निस्संदेह, मध्य पूर्व में एक नया युग आकार ले रहा है। लेकिन राजनीतिक समाधान के बिना, पुनर्निर्माण दीर्घकालिक रूप से बहुत मददगार नहीं होगा। यह उन शक्ति असंतुलनों, जातीय तनावों या टूटी हुई संस्थाओं को ठीक नहीं कर सकता जो जारी रक्तपात का कारण हैं। यह बाहरी शक्तियों को एकजुट करने के बजाय, उनके विरोध को बढ़ा सकता है। पुनर्निर्माण से लोग अपने घर, दुकानें और स्कूल तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जब तक स्थायी शांति स्थापित नहीं होती, ये इमारतें फिर से उसी संघर्ष में तबाह हो सकती हैं। •

यह लेख 'द फेटल फ्लॉव ऑफ द न्यू मीडिल ईस्ट' सबसे पहले फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित हुआ था। हम इसे आवश्यक अपडेट के साथ अनुवाद कर साभार पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

कठपुतली की डोर
अमेरिका का यूरोप पर शिकंजा

टिमोफ़े बोरडाचेव

हाल ही में संपन्न म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ने यूरोप और अमेरिका के बीच जारी ट्रांसअटलांटिक तनाव को उजागर किया। सार्वजनिक रूप से अमेरिकी विमुखता को लेकर चिंता जताने वाले यूरोपीय नेता, दरअसल, रूसी आक्रमण से अधिक अमेरिका की शक्ति पर निर्भर हैं। हालांकि कुछ यूरोपीय देश सैन्य स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अब भी वॉशिंगटन के प्रभाव में बंधे हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के संभावित परिणामों से वे भयभीत हैं।

हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ने यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया, जिससे कई विश्लेषण और टिप्पणियाँ सामने आईं। हालांकि, इन बयानों और चर्चाओं के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी हैः यूरोप के नेता रूस से अधिक अमेरिका की शक्ति से भयभीत हैं। यह भय केवल सतही नहीं है, बल्कि इस डर के पीछे कई ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक कारक काम कर रहे हैं, जो यूरोप और अमेरिका के संबंधों को गहराई से प्रभावित करते हैं।

यूरोप के राजनीतिक नेताओं द्वारा बार-बार उठाई जाने वाली अमेरिकी परित्याग की आशंका महज एक दिखावा है। यह एक रणनीतिक नाटक है, जो उनके वास्तविक डर को छिपाने के लिए खेला जा रहा है। यूरोप की वास्तविकता यह है कि उसकी भू-राजनीतिक स्थिति उसकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस के बीच संघर्ष के केंद्र में होने से उत्पन्न होती है। अमेरिकी परमाणु हथियारों की यूरोप में मौजूदगी, हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और नाटो की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। यह सब अमेरिका की यूरोप पर गहरी पकड़ को दर्शाता है।

यूरोपीय नेताओं का दिखावटी डर

यूरोपीय नेताओं का यह रवैया एक अमेरिकी लोककथा 'ब्रदर रैबिट' की कहानी से मिलता-जुलता है, जिसमें खरगोश ब्रदर फॉक्स से कहता है, 'कुछ भी कर लो, बस मुझे कांटों की झाड़ियों में मत फेंको,' जबकि वह जानता है कि वही झाड़ियां उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान हैं। इसी प्रकार, यूरोपीय नेता सार्वजनिक रूप से अमेरिकी अलगाव से डरने का प्रदर्शन करते हैं, जबकि गुप्त रूप से यह जानते हैं कि अमेरिका कभी उन्हें असल में नहीं छोड़ेगा।

यह नाटक यूरोप के विभिन्न देशों में बार-बार दोहराया जाता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता नियमित रूप से अमेरिकी हस्तक्षेप और उसकी पकड़ से नाखुशी जताते हैं, लेकिन उनके वास्तविक डर का कारण रूस नहीं, बल्कि यह है कि अमेरिका कहीं उनकी नाराजगी को गंभीरता से लेकर उन्हें वह स्वतंत्रता न दे दे जिसकी वे केवल दिखावटी रूप से मांग कर रहे हैं।

युद्ध के लिए इच्छाशक्ति की कमी

जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देशों के पास रूस के साथ सैन्य टकराव में उतरने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है। उनके नागरिक भी इस प्रकार के युद्ध में कोई रुचि नहीं रखते। पिछली सदी के शुरुआती दशकों की तरह जनता में किसी बड़े युद्ध के लिए उत्साह नहीं है। यहां तक कि पोलैंड, जो अक्सर रूस विरोधी बयानबाजी में सबसे आगे रहता है, भी इस बात से वाकिफ

है कि उसके नागरिक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में उलझना नहीं चाहते।

पोलैंड जैसे देशों की भले ही हॉकिश (युद्धोन्मुख) बयानबाजी हो, लेकिन वे भी जानते हैं कि उनकी जनता व्यापक सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। कुछ हजार भाड़े के सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि यूरोप रूस के साथ सैन्य संघर्ष नहीं चाहता।

छोटे राष्ट्र और रूस विरोध

हालांकि, छोटे यूरोपीय राष्ट्र, जैसे बाल्टिक राज्य और चेक गणराज्य, रूस विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। इन देशों में रूस को लेकर भय और अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर समर्थन अधिक स्पष्ट है। परंतु, अगर जर्मनी और फ्रांस मास्को के साथ कूटनीतिक संबंधों की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो इन छोटे देशों की चिंताएँ अप्रासंगिक हो जाएंगी। यह तथ्य नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के निर्माण के दौरान भी देखा गया, जिसे रूस-यूरोपीय संघ के बिगड़ते संबंधों के बावजूद जर्मनी के आर्थिक हितों के चलते अंजाम दिया गया था। इससे यह साफ होता है कि यूरोप के बड़े देश अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए रूस से संबंध बनाए रखने में रुचि रखते हैं।

अमेरिकी प्रभाव का चिरस्थायी प्रभुत्व

पश्चिमी यूरोप की स्वतंत्र नीति पर अमेरिका का गहरा नियंत्रण है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, आर्थिक प्रभाव और खुफिया नेटवर्कों ने यूरोपीय देशों पर अमेरिकी पकड़ को बनाए रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हारने वाले देशों जैसे जर्मनी और इटली आज भी एक तरह से अमेरिकी निगरानी के अधीन काम कर रहे हैं। यह अमेरिकी प्रभुत्व यह सुनिश्चित करता है कि यूरोप अपनी स्वतंत्र भू-राजनीतिक नीति विकसित नहीं कर सकता।

अमेरिका की पकड़ केवल सैन्य और आर्थिक स्तर पर ही नहीं है, बल्कि खुफिया सेवाओं के माध्यम से भी यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों पर नजर रखी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय नेतृत्व अमेरिकी नीतियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके।

यूरोपीय नेताओं का डर और अमेरिकी नियंत्रण

MCSC
MUNICH CYBER SECURITY CONFERENCE 2025

वॉशिंगटन द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना, जो यूरोपीय उद्योगों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, इस शक्ति संतुलन को दर्शाता है। अमेरिकी प्रतिक्रिया के भय से यूरोपीय नेताओं ने इन प्रतिबंधों का विरोध बेहद सीमित रखा।

यूरोप के नेताओं का डर केवल रूस से नहीं है, बल्कि अमेरिकी नियंत्रण के कारण भी है। यूरोपीय नेताओं को डर है कि अगर वे अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देंगे, तो इसका गंभीर परिणाम होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। उदाहरण के लिए, जब 2003 में इराक युद्ध के खिलाफ जर्मनी और फ्रांस ने विरोध किया था, तो अमेरिका ने उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया। यह कड़वा अनुभव अब भी यूरोपीय नेताओं के मन में ताजा है, और वे जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है।

हाल के वर्षों में भी इस प्रकार की घटनाएं दोहराई गई हैं। रूस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को लागू करने में यूरोपीय संघ का सहयोग, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक था, यह दर्शाता है कि यूरोपीय नेता अमेरिकी प्रतिशोध के डर से ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। यह स्पष्ट करता है कि यूरोपीय देशों की अमेरिकी नीति से स्वतंत्र होने की क्षमता बेहद सीमित है।

यूरोप में नेतृत्व का अभाव

यूरोप में आज वह नेतृत्व क्षमता दिखाई नहीं देती, जो अतीत में डि गॉल, एडेनॉयर और मिटरैंड जैसे नेताओं के समय में थी। आज के यूरोपीय नेता अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखते हैं। कई यूरोपीय राजनेता, विशेष रूप से छोटे देशों में, अमेरिकी समर्थन के लिए खुलेआम प्रयास करते हैं। इन छोटे देशों के नेता यूरोपीय संघ के भीतर अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं और जर्मनी या फ्रांस के रूस के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों को बाधित करते हैं।

अगर अमेरिका का प्रभाव यूरोप पर से हट जाए, तो जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश एक अधिक व्यावहारिक नीति अपना सकते हैं, जिसमें रूस के साथ संबंध सुधारने और पोलैंड की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अमेरिकी नियंत्रण के चलते यह संभावना फिलहाल दूर की कौड़ी है।

रूस से नहीं, अमेरिका से असली भय

यूरोपीय नेताओं में रूस का वास्तविक डर नहीं है। वे रूस की शक्तियों और कमजोरियों को अच्छी तरह समझते हैं और मास्को की व्यावहारिक कूटनीति पर भरोसा करते हैं। उनका असली डर अमेरिका से है, जो अपनी अप्रत्याशित और कठोर नीतियों से उन्हें प्रभावित करता है। यूरोप में कोई ऐसा आंदोलन दिखाई नहीं देता जो अमेरिकी प्रभाव से छुटकारा पाने की ओर बढ़ रहा हो। अमेरिका के नियंत्रण में पश्चिमी यूरोप की स्वतंत्र रणनीतिक नीति की कल्पना अभी भी एक सपना मात्र है।

हालांकि, अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने ट्रांसअटलांटिक संबंधों में तनाव पैदा किया है, परंतु यूरोप पर अमेरिकी प्रभुत्व की नींव इतनी गहरी है कि इसे हिलाना फिलहाल असंभव सा प्रतीत होता है। •

यह लेख सबसे पहले 'Vzglyad' **अखबार में** 'EU leaders fear the US more than Russia' **शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। लेखक टिमोफे बोरडाचेव वल्दाई क्लब के कार्यक्रम निदेशक हैं और इसे कल्ट करंट डेस्क द्वारा अनुवादित और संपादित किया गया है।**

अमेरिकी गैस के लिए ट्रंप का आह्वान क्या रूस बेहतर विकल्प है?

जैसे ही नई दिल्ली अपने एलएनजी आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास कर रही है, मॉस्को और वाशिंगटन दोनों ही बड़े समझौते सुनिश्चित करने के लिए भारत को रिझाने में लगे हैं।

मनीष वैध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की वॉशिंगटन यात्रा ने भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने का संकल्प लिया। अमेरिका ने खुद को भारत के लिए कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता स्थापित किया है। यह संबंध भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है।

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाना और दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता प्राप्त करना था। 2025 तक भारत एक जटिल वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य से गुज़र रहा है, जहां अमेरिका अपने प्राकृतिक गैस निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। वहीं, रूस एक स्थापित आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे रूस से ऊर्जा व्यापार जटिल हो गया है।

भारत की ऊर्जा रणनीति में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत की प्राकृतिक गैस की खपत में लगभग 60% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 2030 तक यह खपत 103 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक पहुंच सकती है।

फिलहाल, भारत अपनी गैस की मांग का लगभग 50% तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात के माध्यम से पूरा करता है, जो इसे ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में कमजोर बनाता है। भविष्यवाणियाँ बताती हैं कि 2030 तक भारत का एलएनजी आयात दोगुना होकर 65 बीसीएम तक पहुंच सकता है, जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक बन जाएगा। यह अत्यधिक निर्भरता भारत को मूल्य उतार-चढ़ाव, आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

मोदी की अमेरिका यात्रा ने भारत को दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध सुरक्षित करने, प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने और तेल एवं गैस अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने के नए अवसर प्रदान किए हैं। भारत-अमेरिका का उभरता हुआ ऊर्जा सहयोग न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर उसके संक्रमण के लक्ष्य के साथ भी मेल खाता है।

इस बीच, रूस भी भारत को अपने एलएनजी के प्रस्तावों के साथ आकर्षित कर रहा है। रूस, आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना से एलएनजी की आपूर्ति का प्रचार कर रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भू-राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क हैं। भारतीय और रूसी फर्मों के बीच चर्चाएँ जारी हैं, जिसमें भारत प्रतिस्पर्धी एलएनजी सौदे हासिल करने के सभी उपलब्ध विकल्पों की तलाश कर रहा है।

जैसे-जैसे भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों की जटिलताओं से निपटता है, अमेरिका और रूस दोनों ही आकर्षक, लेकिन चुनौतीपूर्ण, एलएनजी आपूर्ति विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अमेरिकी एलएनजी स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन यह महंगा साबित होता है। उदाहरण के लिए, 2024 की शुरुआत में, अमेरिकी खाड़ी तट से भारत तक एलएनजी शिपिंग की लागत लगभग $1.61 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) थी। इसके अलावा, अमेरिकी एलएनजी अनुबंध अक्सर कठोर शर्तों के साथ आते हैं, जो भारत की बाजार उतार-

चढ़ावों का जवाब देने की लचीलापन को सीमित कर देते हैं।

दूसरी ओर, रूसी एलएनजी भूगोलिक रूप से करीब और अधिक किफायती है, लेकिन यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और प्रतिबंधों के कारण वित्तीय लेनदेन और रसद संचालन जटिल हो गए हैं। जैसे-जैसे यूरोप रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, भारत रूस से कम कीमत पर ऊर्जा प्राप्त करने का मौका तलाश सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं।

अमेरिकी या रूसी एलएनजी पर अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकती है। अमेरिकी एलएनजी नीतिगत बदलावों से प्रभावित हो सकता है, जबकि रूसी एलएनजी पर प्रतिबंधों से संबंधित अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए, भारत मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से आपूर्ति के स्रोतों को विविधता प्रदान करके अपने एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक अधिक मजबूत ऊर्जा पोर्टफोलियो बनाया जा सके।

ट्रंप के साथ मोदी की चर्चाओं के बाद, भारत दीर्घकालिक अनुबंधों में प्रतिस्पर्धी एलएनजी मूल्य सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है। भारत के गैस-आधारित बिजली संयंत्रों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए, एलएनजी की कीमत $8 से $10 प्रति एमएमबीटीयू के बीच होनी चाहिए, जो उत्तर एशिया के वर्तमान में $16 प्रति एमएमबीटीयू की तुलना में काफी कम है।

अधिक किफायती एलएनजी प्राप्त करने के प्रयास में, गेल इंडिया एक अमेरिकी एलएनजी संयंत्र में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना तलाश रहा है। यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के हालिया फैसले के अनुरूप है, जिससे भारत को प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक अनुबंध सुरक्षित करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, भारत अपनी घरेलू गैस अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है ताकि ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सके।

प्रतिबंधों के बावजूद, भारत रूस के साथ ऊर्जा सहयोग बनाए रखने के लिए वैकल्पिक वित्तीय तंत्रों का भी परीक्षण कर रहा है। इन तंत्रों में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार करना शामिल है, जो भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। हाल की बातचीत से पता चलता है कि अमेरिकी डॉलर-आधारित लेन-देन से बचने के लिए ऊर्जा आयात जारी रखने की रणनीति में नई दिलचस्पी है।

ट्रंप प्रशासन, हालांकि, रूसी ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर सकता है, जिससे भारत की एलएनजी खरीद रणनीति और जटिल हो सकती है। यदि अमेरिकी नीतियाँ तीव्र होती हैं, तो भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों को सक्रिय रूप से विविध बनाना और स्थिर आयात सुनिश्चित करने के लिए अपने भुगतान तंत्रों को परिष्कृत करना होगा।

रूस के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग केवल एलएनजी तक सीमित नहीं है; यह तेल, कोयला और परमाणु ऊर्जा तक फैला हुआ है। रूसी कंपनियाँ भारत के तेल और गैस अन्वेषण में शामिल हैं, और एलएनजी शिपमेंट को बढ़ाने पर चर्चा जारी है। साथ ही, भारत मध्य पूर्वी एलएनजी उत्पादकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नए आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर रहा है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत किसी भी एकल ऊर्जा आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को कम कर रहा है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होती है।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी और रूसी ऊर्जा आपूर्ति के बीच संतुलन बनाते हुए, वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। •

मनीष वैद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जूनियर फेलो हैं, जिनकी शोध रुचि रणनीतिक ऊर्जा विश्लेषण और हरित परिवर्तन में है। इस लेख को Cult Current डेस्क द्वारा अतिरिक्त सामग्री के साथ अद्यतन किया गया है, और हम इसे उचित श्रेय देते हुए पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा

समृद्धि की नई साझेदारी

अशोक सज्जनहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरवरी 2025 में अमेरिका दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हुआ और इसकी टाइमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। आमतौर पर, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद शुरुआती महीनों में यूरोप, नाटो और अन्य रणनीतिक सहयोगी देशों के नेताओं को वाशिंगटन आमंत्रित किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी का अमेरिका दौरा इस तथ्य का प्रतीक था कि दोनों देशों के लिए यह संबंध कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले केवल इजरायली प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री और जॉर्डन के राजा को आमंत्रित किया गया था।

भारत-अमेरिका संबंध: स्थायी मित्रता की मिसाल

भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25 सालों में निरंतर मजबूत हुए हैं, खासकर 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद। दोनों देशों की राजनीति में हमेशा द्विपक्षीय सहमति रही है कि उनके रिश्ते को अधिक मजबूत बनाया जाए।

हालांकि, 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता, तो दुनिया भर में एक असमंजस की स्थिति बन गई। ट्रंप को लेकर अनिश्चितता इसलिए भी थी क्योंकि उनकी छवि एक अप्रत्याशित और व्यवसायिक नेता की रही है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप को यह समझने में कठिनाई हुई कि वे एक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पहले से कहीं अधिक मजबूती से सत्ता संभाली है।

2024 के चुनाव में ट्रंप ने निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने सभी सात महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में जीत दर्ज की। इस जीत ने ट्रंप को और भी आत्मविश्वासी बना दिया और उन्होंने 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' के अपने एजेंडे को पूरी मजबूती से लागू करने का निश्चय किया। इसके तहत उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगियों को अपनी कैबिनेट में अहम पदों पर स्थापित किया।

चुनौतियों के बावजूद मजबूत बंधन

हालांकि दुनिया भर में ट्रंप की सत्ता में वापसी को लेकर चिंता थी, भारत ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इसका प्रमुख कारण था दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और मोदी-ट्रंप की दोस्ताना केमिस्ट्री। चुनाव और ट्रंप के उद्घाटन के बाद, 27 जनवरी 2025 को मोदी-ट्रंप के बीच हुई बातचीत इस बात का प्रमाण थी कि दोनों देश आपसी साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, 'हम दोनों देश एक विश्वसनीय और लाभकारी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में मिलकर काम करेंगे।' विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अपनी वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत से उन्हें विश्वास हुआ है कि दोनों देशों को अधिक साहसिक और महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है।

तैयारियों की चुनौतियाँ

मोदी के दौरे की तैयारियों के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं। सबसे पहले, ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान और उसके बाद भारत को 'टैरिफ किंग' कहकर संबोधित किया था और धमकी दी थी कि अमेरिका उन देशों पर बराबर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने कुछ निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिए, जिसमें हाई-कैपेसिटी मोटरबाइक्स, सुपर लग्जरी ऑटोमोबाइल्स,

ईवी बैटरियां, और बॉर्बन व्हिस्की जैसे अमेरिकी निर्यात वस्तुएं शामिल थीं।

दूसरी चुनौती उन 100 से अधिक भारतीय अवैध प्रवासियों की थी, जिन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में जंजीरों और हथकड़ियों में बांधकर भारत वापस लाया गया। इस घटना ने भारतीय जनता और विपक्ष को बहुत नाराज किया और इसे एक शर्मनाक अपमान के रूप में देखा गया।

तीसरी चुनौती यह थी कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने भारत के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस स्थिति ने एक तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी रणनीति से इन कठिनाइयों को कुशलता से संभाला।

मोदी-ट्रंप बैठक: वैश्विक मंच पर एक मास्टरक्लास

प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसा परिणाम हासिल किया, जिसने सीएनएन जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मोदी-ट्रंप की बैठक 'दुनिया भर के नेताओं के लिए एक मास्टरक्लास' थी।

भारत-अमेरिका संबंध केवल द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इसका संबंध भू-राजनीतिक खतरों से भी है, खासकर चीन के आक्रामक उदय के कारण। भारत और अमेरिका के बीच यह साझेदारी दोनों देशों के लिए भू-राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

भारत और अमेरिका के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है और यह दौरा उस दिशा में एक और मजबूत कदम साबित हुआ। जहां अमेरिका के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक और तकनीकी साझेदार है, वहीं भारत के लिए अमेरिका से मिलकर काम करना चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है। इस दौरे ने दोनों देशों के नेताओं के बीच विश्वास को और मजबूत किया और यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका साझेदारी वैश्विक मंच पर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पीएम मोदी के इस दौरे ने न केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए दरवाजे खोले, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी के संकेत दिए। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए।

परिणाम:

व्यापार और शुल्क: प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के

बीच इस दौरे में प्रमुख उपलब्धियों में से एक था द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को सितंबर/अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप देने का निर्णय। इस समझौते ने भारतीय निर्यात पर तत्काल कोई दंडात्मक शुल्क लगाने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। साथ ही, दोनों देशों ने मौजूदा 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया।

रक्षा: रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों ने 'फ्रेमवर्क डिफेंस एग्रीमेंट' को अगले दस वर्षों यानी 2035 तक बढ़ाने का फैसला किया। इस समझौते के तहत भारत 'जैवलिन' एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, 'स्ट्राइकर' इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, और छह अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों को आयात करेगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, भारत और अमेरिका ने उन्नत रक्षा उपकरणों के सह-डिजाइन और सह-उत्पादन पर सहमति जताई। ट्रंप ने भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 भी पेश किया, लेकिन इसका अंतिम निर्णय भारत को विस्तृत मूल्यांकन के बाद लेना होगा।

ऊर्जा: भारत पहले से ही अमेरिका से प्रतिवर्ष 15 बिलियन डॉलर की तेल और एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का आयात करता है, जिसे बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर करने की योजना बनाई गई है। इससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन को कम किया जा सकेगा, जो वर्तमान में 46 बिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष पर है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने नागरिक परमाणु क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने का निर्णय लिया, जिसमें उन्नत और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल होंगे। भारत ने हाल के बजट में

अपनी नागरिक परमाणु कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण: डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यर्पण की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वह 'न्याय का सामना करेगा।' यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक जीत है, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि राणा कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकेगा, क्योंकि वह पिछले 15 वर्षों से जेल में है।

समृद्धि के लिए MEGA साझेदारी: प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने बताया कि जहां अमेरिका का नारा 'MAGA' (Make America Great Again) है, वहीं भारत की आकांक्षा 'विकसित भारत 2047' का मतलब 'Make India Great Again (MIGA)' से है। इस प्रकार, MAGA और MIGA का संयोजन दोनों देशों के लिए एक 'MEGA साझेदारी' का आधार बनेगा, जो समृद्धि और प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।

U.S.-India COMPACT (Catalysing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) पहल: ट्रंप और मोदी ने COMPACT नामक नई पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सैन्य, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक परिणाम-उन्मुख एजेंडा तैयार किया, जिसकी प्रारंभिक उपलब्धियां इस वर्ष प्राप्त होंगी।

U.S.-India TRUST (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) पहल: इस पहल का उद्देश्य सरकार-से-सरकार, अकादमिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुई क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल को जारी रखते हुए, दोनों देशों ने इस साल के अंत तक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेज करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया। साथ ही, भारत और अमेरिका ने खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान और निवेश में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।

इंडो-पैसिफिक और क्वाड: मोदी और ट्रंप ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी की महत्ता को दोहराया। उन्होंने कानून के शासन, समुद्री सुरक्षा, और समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। ट्रंप के कार्यकाल के पहले दिन क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के आयोजन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि क्वाड आने वाले वर्षों में मजबूत होता रहेगा। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ दबाव भी जारी रहेगा। हालांकि ट्रंप के शुरूआती वक्तव्यों में चीन के प्रति कुछ विरोधाभासी संकेत मिले थे, लेकिन यह माना जा सकता है कि चीन अमेरिका के लिए 'रणनीतिक प्रतिस्पर्धी' बना रहेगा।

आतंकवाद विरोधी प्रयास: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के अलावा, दोनों देशों ने भारत को पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटने में सहयोग देने पर सहमति जताई। साथ ही, जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), आईएसआईएस, अल कायदा जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, ताकि मुंबई के 26/11 हमले और अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण और अस्थिर परिस्थितियों के बीच हुई, लेकिन इसका परिणाम सकारात्मक रहा। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विश्वास पुनः स्थापित हुआ और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम खोले गए। भारत-अमेरिका संबंध अब तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और यह द्विपक्षीय व वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक सशक्त ताकत बनेंगे। •

अशोक सज्जनहार भारत के कज़ाखस्तान, स्वीडन और लातविया में राजदूत रह चुके हैं और वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, मॉस्को, जिनेवा, तेहरान, ढाका और बैंकॉक में विभिन्न राजनयिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के प्रमुख के रूप में भी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में, वे नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के अध्यक्ष और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं।

गोविंदा-सुनिता के रिश्ते में दरार?

अफवाह, साजिश या हकीकत!

बॉलीवुड के चहेते स्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनिता आहूजा की शादी में तनाव की खबरें उड़ रही हैं, जिससे फैंस हैरान हैं! 37 साल के रिश्ते पर तलाक की अफवाहों ने सनसनी मचा दी, लेकिन सच्चाई क्या है? जब गोविंदा से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से नकारते हुए कहा, 'ये सिर्फ बिजनेस की बातें हैं। कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही।' उन्होंने फैंस से जल्दबाज़ी में नतीजे पर न पहुंचने की अपील की और कुछ दिन इंतजार करने को कहा। लेकिन असली मसाला तो उनके मैनेजर शशि सिन्हा के बयान से आया!

शशि ने सुनिता पर इशारों-इशारों में निशाना साधते हुए कहा, 'उन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ कह दिया यही नतीजा है।' यानी, पारिवारिक बयानबाज़ी ने रिश्ते में तनाव ला दिया है। वहीं, गोविंदा के भतीजे विनय आनंद ने भी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बातों-बातों में इशारा कर दिया कि मामला उतना गंभीर भी नहीं हो सकता। ट्विस्ट ये है कि गोविंदा इन दिनों अपनी नई फिल्म के लॉन्च में व्यस्त हैं। तो क्या ये सच में शादी में दरार है या फिर किसी बड़े प्रमोशन का हिस्सा?

असली कहानी क्या है—प्यार का नया मोड़ या अलगाव की शुरुआत? बस थोड़ा इंतजार और सब सामने आ जाएगा! •

'चिकनी चमेली' पर शर्मिंदा हुईं श्रेया, बोलीं – 'छोटी बच्चियों को ये गाना गाते देख अजीब लगता है!'

सुर साम्राज्ञी श्रेया घोषाल ने अपने सुपरहिट गाने 'चिकनी चमेली' को लेकर बड़ा खुलासा किया है! साल 2012 में कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ था, लेकिन अब श्रेया खुद इस पर 'क्रिंज' महसूस करती हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में श्रेया ने माना कि 'सेक्सी और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच एक बारीक रेखा होती है, और इस गाने के बोल उस दायरे में आ जाते हैं, जो अब उन्हें असहज महसूस कराते हैं।' उन्होंने खासतौर पर छोटी बच्चियों द्वारा इस गाने को गाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'जब 5-6 साल की मासूम बच्चियां इसे मेरे सामने गाती हैं, तो अजीब लगता है। उन्हें इसका मतलब भी नहीं पता होता, और यही बात मुझे असहज कर देती है।' इतना ही नहीं, श्रेया ने बॉलीवुड में पुरुष-प्रधान गीत लेखन पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि 'अगर इस गाने के बोल किसी महिला ने लिखे होते, तो वे शायद ज्यादा ग्रेसफुल होते।' •

आलिया का हेटर्स को करारा जवाब

रणबीर कपूर एक 'ग्रीन फ्लैग' हैं, रेड फ्लैग नहीं!

बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग रणबीर को 'टॉक्सिक', 'मम्माज़ बॉय' और 'रेड फ्लैग' कहने से नहीं चूकते। अब आलिया ने अपने पति पर लग रहे इन आरोपों का करारा जवाब दिया है! हाल ही में एक फैन ने रणबीर की तारीफ करते हुए पोस्ट किया कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल ब्रांड 'ARKS' में अपनी पत्नी आलिया और बेटी राहा के नाम के शुरुआती अक्षरों को शामिल किया। इस पोस्ट में लिखा था, 'अगर रणबीर कपूर 'रेड फ्लैग' हैं, तो फिर इंटरनेट पर जितने भी ग्रीन फ्लैग हैं, उनसे तो ये कहीं बेहतर हैं!' आलिया ने इस पोस्ट को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाया, जिससे साफ है कि वो अपने पति के खिलाफ चल रही नेगेटिविटी को लेकर बिल्कुल शांत नहीं बैठने वालीं। ये पहली बार नहीं है जब आलिया ने रणबीर का बचाव किया हो। 'कॉफी विद करण' सीज़न 8 में भी उन्होंने रणबीर को लेकर होने वाले ट्रोलिंग पर बात की थी। करण जौहर ने कहा, 'रणबीर सोशल मीडिया पर नहीं हैं, इसलिए उनकी बातें अक्सर गलत तरीके से फैलाई जाती हैं।' •

पुस्तकों की ओर वापसी

क्या कागज़ी पाठ्यपुस्तकें ही भविष्य का रास्ता हैं?

अर्पण तुलस्यान

एक चौंकाने वाले कदम के तहत, स्वीडन 15 साल बाद डिजिटल पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर फिर से पारंपरिक किताबों की ओर लौट रहा है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण छात्रों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एकाग्रता, और बुनियादी पढ़ने-लिखने के कौशल में गिरावट को लेकर बढ़ती चिंताएँ हैं।

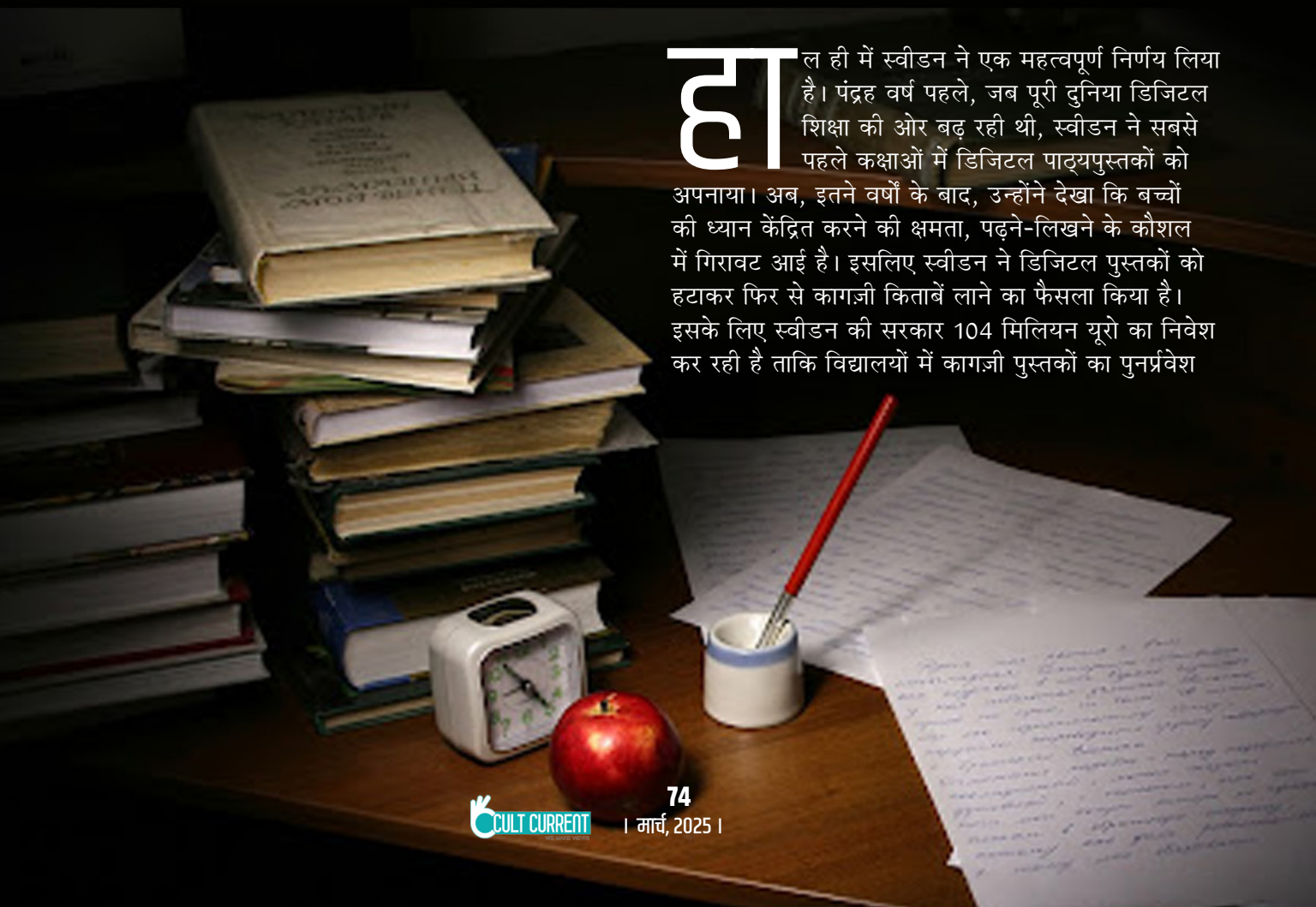

हाल ही में स्वीडन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंद्रह वर्ष पहले, जब पूरी दुनिया डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रही थी, स्वीडन ने सबसे पहले कक्षाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकों को अपनाया। अब, इतने वर्षों के बाद, उन्होंने देखा कि बच्चों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, पढ़ने-लिखने के कौशल में गिरावट आई है। इसलिए स्वीडन ने डिजिटल पुस्तकों को हटाकर फिर से कागज़ी किताबें लाने का फैसला किया है। इसके लिए स्वीडन की सरकार 104 मिलियन यूरो का निवेश कर रही है ताकि विद्यालयों में कागज़ी पुस्तकों का पुनर्प्रवेश

किया जा सके।

स्वीडन की शिक्षा एजेंसी को यह जाँचने का कार्य सौंपा गया है कि डिजिटल उपकरणों का उपयोग किस प्रकार हो रहा है और इसका प्रभाव क्या है। इसके आधार पर, वे डिजिटल उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अब तक, स्वीडन के प्री-स्कूल पाठ्यक्रम में प्रत्येक बच्चे के लिए डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य थी, जिसे अब संशोधित कर 'वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक समर्थन' के आधार पर 'चुनिंदा' उपयोग तक सीमित कर दिया गया है।

यह प्रवृत्ति केवल स्वीडन तक सीमित नहीं है। फिनलैंड के कुछ स्कूलों में भी डिजिटल-केन्द्रित शिक्षा पद्धति को छोड़कर छात्रों की एकाग्रता बढ़ाने और स्क्रीन के समय को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया में भी शैक्षणिक अधिकारियों ने छात्रों के पढ़ने की क्षमता में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसे आंशिक रूप से स्क्रीन के बढ़ते उपयोग से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञ अब छात्रों को प्रिंटेड किताबों से पढ़ने और हाथ से लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि इस संकट से निपटा जा सके।

स्क्रीन-मुक्त शिक्षा का प्रभाव

कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम का हेरिटेज स्कूल, जिसे देश का एकमात्र 'स्क्रीन-मुक्त विद्यालय' माना जाता है, ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिना किसी डिजिटल उपकरण के भी सर्वोत्तम शैक्षिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस स्कूल में लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट, या इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड का उपयोग नहीं होता है और फिर भी यहाँ के छात्रों ने बेहतरीन शैक्षणिक परिणाम हासिल किए हैं। स्कूल अपनी इस टेक्नोलॉजी-मुक्त शैक्षणिक पद्धति को 'नवोन्मेषी' मानता है और इसे 'एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण, जिसकी कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए खोज कर रहे हैं' के रूप में पहचाना जाता है।

अध्ययन बताते हैं कि बच्चों में पढ़ने के कौशल और उनकी स्वतंत्र रूप से पढ़ने की रुचि के बीच एक सहायक संबंध है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों (जैसे कि पीआईआरएलएस और पीआईएसए) ने संकेत दिया है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी आ रही है। इसका सीधा असर उनके पढ़ने के कौशल पर पड़ता है। जहाँ एक ओर कागज़ी किताबों का पढ़ना कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया जैसी मल्टीमीडिया सामग्री का उपभोग बढ़ता जा रहा है। यह दर्शाता है कि स्कूल शिक्षा में डिजिटल पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है।

गहन अध्ययन और समझ

अनुसंधान से पता चला है कि कागज़ी पुस्तकों का भौतिक रूप, जैसे उसे पकड़ना, पन्ने पलटना, और उसकी सुगंध, गहरे स्तर पर मस्तिष्क को संलग्न करता है। इससे पाठक जानकारी को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। दूसरी ओर, ई-पुस्तकें, जो कि हाइपरलिंक, स्क्रॉलिंग और मल्टीमीडिया सुविधाओं से भरपूर होती हैं, पाठक को अस्थिर और विचलित कर देती हैं। विशेषकर छोटे बच्चों के मामले में, ऑनलाइन पढ़ाई में फोकस और समझ की कमी देखी गई है। डिजिटल पठन भी पाठकों के व्यवहार और पसंद को प्रभावित करता है, जिससे वे धीमे और अधिक सोची-समझी पठन प्रक्रियाओं में रुचि खोने लगते हैं।

2000 से 2017 के बीच किए गए 54 अध्ययनों के एक विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्क्रीन पर पढ़ाई की तुलना में कागज़ी पठन अधिक प्रभावी है। यह परिणाम पाठकों की आयु, शिक्षा स्तर, पाठ की लंबाई और समझ के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित नहीं हुआ। खासकर समय की कमी वाले स्थितियों में और सूचनात्मक पाठों के संदर्भ में, कागज़ी पठन के लाभ अधिक स्पष्ट थे।

संवेदी संलग्नता और इंटरएक्टिविटी

कई शोध यह दिखाते हैं कि डिजिटल किताबों के मल्टीमीडिया फीचर्स, जैसे संगीत और ध्वनि प्रभाव, चित्रों की एनिमेशन, और अंतर्निर्मित शब्दकोश, छात्रों की रुचि और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। हालांकि, इन सुविधाओं का शैक्षणिक प्रभाव पूरी तरह से उनके डिज़ाइन और उनकी प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। ई-पाठ्यपुस्तकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे विविध कक्षाओं में व्यक्तिगत शिक्षा को लागू करना आसान हो जाता है।

हालांकि, यदि ई-पुस्तकें अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हैं और उनके उपयोग में शिक्षक की मदद मिलती है, तभी वे कागज़ी पुस्तकों से बेहतर परिणाम दे सकती हैं। लेकिन अगर डिजिटल किताबों में केवल वॉयसओवर या पॉपअप जैसी मामूली विशेषताएँ हैं, तो कागज़ी किताबें बेहतर परिणाम देती हैं। यद्यपि डिजिटल टेक्स्ट छात्रों को संलग्न करने में बेहतर हैं, वे अक्सर केवल सतही संलग्नता ही पैदा करती हैं, क्योंकि छात्रों की एकाग्रता कई बार बिखर जाती है। दूसरी ओर, कागज़ी किताबों से पढ़ाई में छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रीत और बिना किसी बाधा के होता है।

स्वास्थ्य संबंधी विचार

बच्चों में स्क्रीन उपयोग पर किए गए स्वास्थ्य अध्ययन मुख्य रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत पर केंद्रित रहे हैं। हालाँकि, कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि ई-पाठ्यपुस्तकों के लगातार उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इनमें आँखों की थकावट, गर्दन या पीठ में दर्द, और सूखी त्वचा जैसी समस्याएं शामिल हैं। साथ ही, छात्रों में तनाव, घबराहट, और निराशा जैसी मानसिक समस्याएँ भी देखी गई हैं। कागज़ी किताबें, जिनमें स्क्रीन की चमक नहीं होती, बच्चों के शरीर और मन के लिए अधिक आरामदायक पठन अनुभव प्रदान करती हैं।

नीति निर्धारण के लिए संदेश

जहाँ ई-पुस्तकें छात्रों को कुछ लाभ प्रदान करती हैं, वहीं उनके व्यापक उपयोग से पहले उनके दीर्घकालिक प्रभावों की पूरी तरह से समीक्षा करना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि डिजिटल पाठ्यपुस्तकों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे मूलभूत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कागज़ी पाठ्यपुस्तकों का पूरक बनें, न कि उनका प्रतिस्थापन।

राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी स्कूलों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग की जांच कर रही है और इसे कम करने के उपाय सुझा रही है। फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी डिजिटल लर्निंग पर पुनर्विचार कर रहे हैं ताकि छात्रों की एकाग्रता बढ़े और स्क्रीन टाइम कम हो। शोध बताते हैं कि पारंपरिक किताबें समझने की क्षमता और मानसिक सक्रियता को बढ़ाती हैं, जिससे शिक्षा में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

भविष्य में शिक्षा का स्वरूप एक गतिशील मिश्रण होगा, जहाँ कागज़ी और डिजिटल दोनों माध्यमों का सही संतुलन छात्रों की आवश्यकताओं, उनके शैक्षिक संदर्भों और पाठ्यक्रम उद्देश्यों के अनुसार किया जाएगा। •

अर्पण तुलस्यान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में सीनियर फेलो हैं।

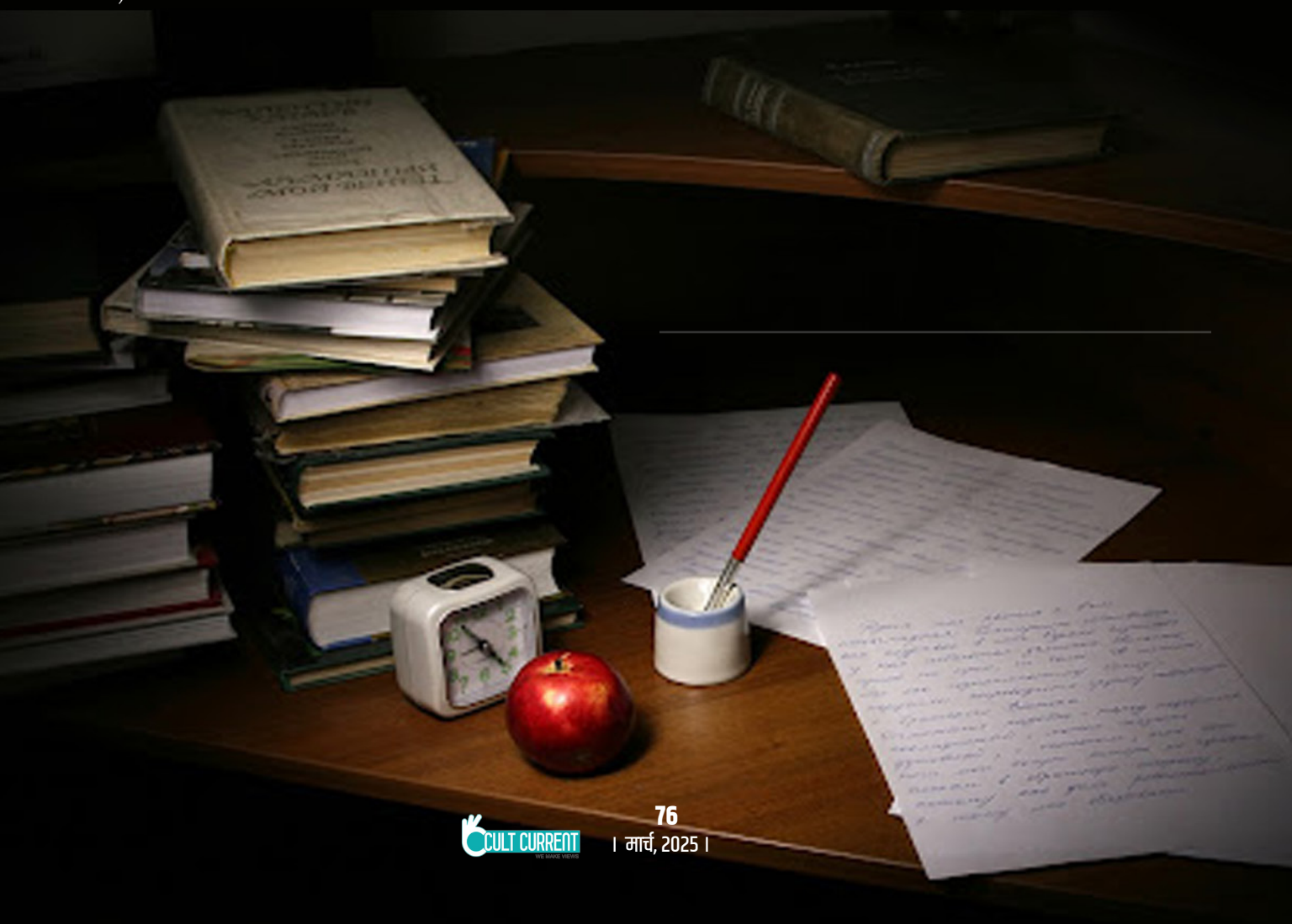

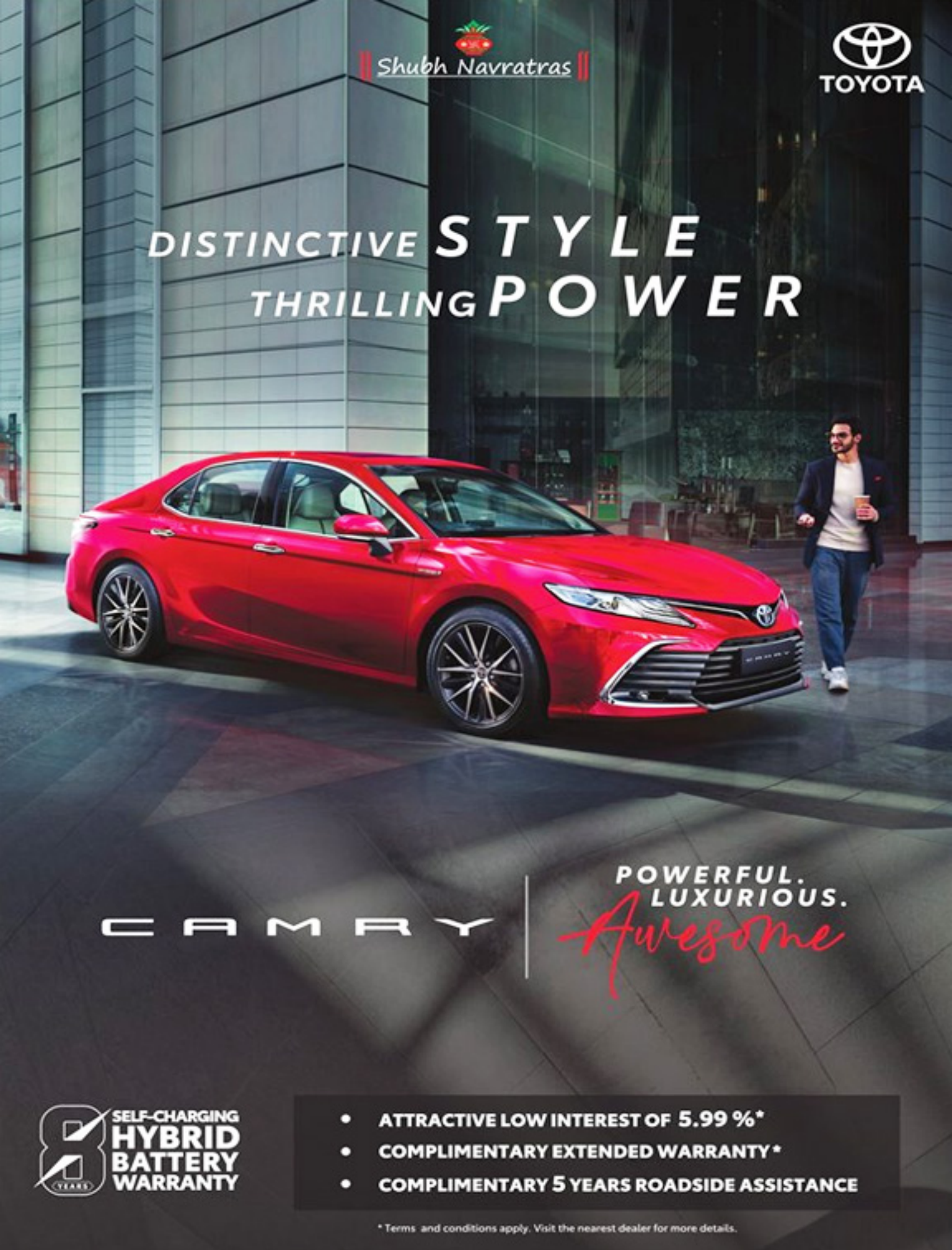

Shubh Navratras
TOYOTA
DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER
CAMRY
POWERFUL.
LUXURIOUS.
Awesome
8 YEARS
SELF-CHARGING
HYBRID
BATTERY
WARRANTY
ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE
* Terms and conditions apply. Visit the nearest dealer for more details.

RNI TITLE CODE : DELENG19447

MARC SANITATION PVT. LTD.
A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033
Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com